चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार

www.chauthiduniya.com

मूल्य 5 रुपये

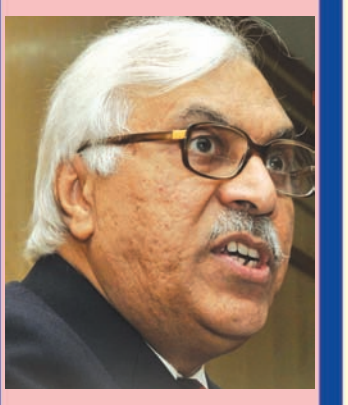

दिल्ली, 20 सितंबर-26 सितंबर 2010

नीतीश-लालू को बोनस

पेज-3

राजनीतिक उठापटक का दौर जारी

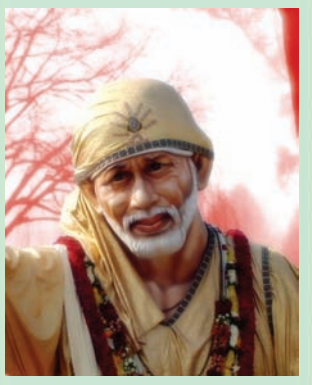

पेज-4

शेखावाटी का चेहरा बदल रहा है

पेज-7

साई की महिमा

पेज-12

मिलिए लोकतंत्र के राजाओं से

राजतंत्र नहीं रहा, उसकी जगह प्रजातंत्र आ गया, लेकिन अंतर क्या आया? अब एक राजा की जगह कई राजा मिल कर आम आदमी का शोषण करते हैं, वह भी इतनी सफाई से कि आम आदमी को भनक तक नहीं लगती. कुछ ऐसे ही राजाओं की ख़बर ली है चौथी दुनिया ने. आरटीआई से मिली सूचना के मुताबिक़, इन राजाओं की प्यास बुझाने के लिए आम आदमी को अपनी करोड़ों की कमाई गंवानी पड़ रही है. अपना घर अंधेरे में रखकर राजाओं के आलीशान महलों (मुख्यमंत्री आवास) को रोशन कर रहा है आम आदमी. ख़ुद के सिर पर छत नहीं, लेकिन वह इन राजाओं के महलों की पेंटिंग पर ही लाखों रुपये ख़र्च कर रहा है.

शशि शेखर

राजनीति पेशा है या समाजसेवा का ज़रिया, इसका जवाब इस साल संसद के मानसून सत्र को देखकर पता लग जाता है. सत्र के दौरान सांसदों ने जिस तरीक़े से अपना वेतन और भत्ता बढ़ाने की मांग की, उससे यह साफ हो गया कि इन माननीयों के लिए राजनीति समाजसेवा का ज़रिया तो कतई नहीं हो सकती. उनके लिए राजनीति पेशे से भी एक क़दम आगे की चीज है. यानी भरपूर सुख-सुविधा भोगने का एक ज़रिया. चाहे इसके लिए जनता को कोई भी क़ीमत क्यों न चुकानी पड़े. लेकिन यह हाल सिर्फ़ सांसदों का ही नहीं है, राज्य के मुख्यमंत्री भी जनता की जेब ढीली कर सुख-सुविधा भोगने में पीछे नहीं हैं. वह भी तब, जब दिल्ली जैसे शहर में 80 हज़ार से ज़्यादा लोगों के सिर पर छत नहीं है. विदर्भ में अब तक 2 लाख से ज़्यादा किसान असमय मौत को गले लगा चुके हैं. उत्तर प्रदेश में हर साल सैकड़ों बच्चे इंसेफ्लाइटिस की वजह से दम तोड़ देते हैं, लेकिन इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों की जीवनशैली पर नज़र डालें तो एक अलग ही तस्वीर दिखाई देती है. चमक-दमक से भरपूर तस्वीर. बिल्कुल इंडिया शाइनिंग की तरह. जिस देश की एक बड़ी आबादी को पीने का साफ पानी मयस्सर नहीं, वहीं इन राज्यों में से एक के मुख्यमंत्री आवास का पानी का बिल 62 लाख रुपये आए तो इसे आप क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र के कितने गांवों तक बिजली पहुंची है. और अगर पहुंचती भी है तो कितने घंटों के लिए, यह रिसर्च का मामला हो सकता है, लेकिन इन दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री अपने आवास को रोशन करने के लिए महीने में 20 लाख रुपये से ज़्यादा बिजली पर ख़र्च कर देते हों तो इसे आप क्या कहेंगे? चौथी दुनिया ने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास पर होने वाले ख़र्च का ब्योरा आरटीआई के ज़रिए जुटाया है. प्राप्त सूचना के विश्लेषण से पता चलता है कि कैसे आम आदमी की गाढ़ी कमाई इन राज्यों के मुख्यमंत्री आवासों पर बेहिसाब ख़र्च की जा रही है.

प्रधानमंत्री भले ही अपने मंत्रियों को विदेश दौरे न करने, सरकारी ख़र्च घटाने की सलाह देते रहते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में

(शेष पृष्ठ 2 पर)

उत्तर प्रदेश	
बिजली का बिल	92 लाख
बल्ब, सीएलएफ एवं बिजली मरम्मत	13 लाख
इलेक्ट्रॉनिक उपकरण	33 लाख
पेंटिंग	9 लाख
कर्टेन्स, कारपेट, टाइल्स	35 लाख
टेलीफोन का बिल	19 लाख
	कुल-2.1 करोड़ रु.

महाराष्ट्र	
बिजली का बिल	92.26 लाख
पानी का बिल/मिनरल वाटर	61.74 लाख
पेंटिंग	86 लाख
बिजली मरम्मत	8.5 लाख
इलेक्ट्रॉनिक उपकरण	6 लाख
कर्टेन्स	1.38 लाख
	कुल-2.56 करोड़ रु.

दिल्ली	
मिनरल वाटर (2006-09)	47 हज़ार
बिजली और पानी बिल	10 लाख
टेलीफोन का बिल	6 लाख
	कुल-16.47 लाख

माया की माया

उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बजाय असली मुद्दों पर ध्यान देने के पांच सितारा होटलों में रात्रिभोज (पार्टी) का आयोजन करती हैं और वह भी जनता के पैसों पर. दलित उत्थान की बात करने वाली मायावती की जन्मदिन की पार्टियां हमेशा से सुर्ख़ियां बटोरती रही हैं. वजह, ऐसे मौक़ों पर होने वाली शाहख़र्ची, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल, कार्यकर्ताओं से महंगे उपहार लेने जैसे आरोप. ख़ैर ये आरोप तो विरोधी दलों की तरफ़ से लगाए जाते रहे हैं, लेकिन सूचना का अधिकार क़ानून के तहत जो जानकारी मिली है, उससे ख़ुद को दलितों की मसीहा मानने में फख़्र महसूस करने वाली मायावती की शख़्सियत के एक अलग ही पहलू का पता चलता है. मई 2007 में राज्य विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीत दर्ज करके मायावती सरकार बनाती हैं. 13 मई, 2007 को माया सरकार शपथ ग्रहण करती है और 25 मई, 2007 को मुख्यमंत्री दिल्ली के पांच सितारा होटल ओबरॉय में एक शानदार पार्टी (रात्रिभोज) का आयोजन करती हैं. उपलब्ध दस्तावेज के मुताबिक़, इस रात्रिभोज में विशिष्ट महानुभावों को आमंत्रित किया गया. हालांकि इस दस्तावेज में इन विशिष्ट महानुभावों के नाम का जिक्र नहीं है. ज़ाहिर है, विशिष्ट होटल (पांच सितारा) में विशिष्ट महानुभावों को दी गई पार्टी (रात्रिभोज) का ख़र्च भी विशिष्ट ही आना था. इसलिए इस एक रात की पार्टी का ख़र्च आया 17 लाख 16 हज़ार 8 सौ 25 रुपये.

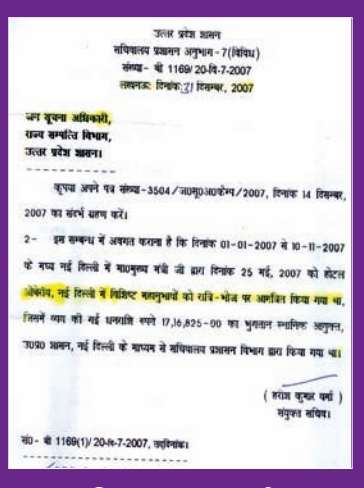

उत्तर प्रदेश शासन
सचिवालय प्रशासन अनुभाग-7(विविध)
संख्या- बी 1169/20-वि-7-2007
लखनऊ: दिनांक 21 दिसम्बर, 2007

जन सूचना अधिकारी,
राज्य सम्पत्ति विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

कृपया अपने पत्र संख्या-3504/[illegible]/2007, दिनांक 14 दिसम्बर, 2007 का संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि दिनांक 01-01-2007 से 10-11-2007 के मध्य नई दिल्ली में मा0मुख्य मंत्री जी द्वारा दिनांक 25 मई, 2007 को होटल ओबेराय, नई दिल्ली में विशिष्ट महानुभावों को रात्रि-भोज पर आमंत्रित किया गया था, जिसमें व्यय की गई धनराशि रुपये 17,16,825-00 का भुगतान स्थानिक आयुक्त, उ0प्र0 शासन, नई दिल्ली के माध्यम से सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा किया गया था।

([illegible] कुमार वर्मा)
संयुक्त सचिव।

सं0- बी 1169(1)/20-वि-7-2007, तद्दिनांक।

इस धनराशि का भुगतान स्थानीय आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन, नई दिल्ली के माध्यम से सचिवालय प्रशासन विभाग की ओर से किया गया. यह सूचना राज्य संपत्ति विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ़ से उपलब्ध कराई गई है. हो सकता है कि लोगों को यह रकम मामूली लगे, लेकिन सवाल धनराशि का नहीं है. सवाल पांच सितारा होटल में पार्टी देने का भी नहीं है. मायावती अपने जन्मदिन की पार्टियों पर जितना ख़र्च करती हैं, उसके मुक़ाबले 17 लाख की रकम कोई बहुत बड़ी रकम नहीं मानी जा सकती, लेकिन सवाल उस व्यवस्था का है, जहां हमारे नुमाइंदों को यह सोचने की फ़ुर्सत नहीं है कि जो एक पैसा भी वह अपने ऊपर ख़र्च करते हैं, वह ग़रीब जनता के हिस्से का होता है. वह ग़रीब जनता, जिसकी प्राथमिकता आज भी रोटी, कपड़ा और मकान है. सवाल हमारे नेताओं की उस मानसिकता का भी है, जो उन्हें पांच सितारा होटलों में पार्टी आयोजित करने के लिए प्रेरित करती है. इसका एक बेहतरीन उदाहरण ख़ुद मायावती ही हैं, जो अपना जन्मदिन समारोह मनाने के लिए अंबेडकर पार्क का ही चुनाव करती थीं. लेकिन 2007 के विधानसभा चुनाव तक पहुंचते-पहुंचते जैसे बसपा का नारा बहुजन से बदल कर सर्वजन हो गया, कुछ उसी तर्ज पर सत्ता मिलने के बाद मायावती की तरफ़ से दी जाने वाली पार्टियां भी पार्क से निकल कर पांच सितारा होटलों तक पहुंच गईं.

सभी फोटो-प्रभात पाण्डेय

प्रशिक्षण के लिए नए कार्यक्रमों, शिक्षा एवं शोध कार्यों के लिए वन अधिकारियों को विदेश भेजे जाने के फ़ैसले लिए गए हैं, लेकिन अब इन फ़ैसलों पर कहीं नए सिरे से सोचना न पड़े.

दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

नया चेयरमैन नहीं मिला

राष्ट्रीय राजमार्गों पर आसानी से दिख जाने वाला गड्ढा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की अंदरूनी हालत की असली तस्वीर पेश करता है. सरकार ने एनएचएआई के नए अध्यक्ष की तलाश में एक साल तक कोशिश की, लेकिन उपयुक्त उम्मीदवार न मिलता देख वह इसके मौजूदा अध्यक्ष ब्रजेश्वर सिंह को तीन महीने का सेवा विस्तार देने का फ़ैसला लेने के लिए मजबूर हो गई. सूत्रों से मिली ख़बर के मुताबिक़, दो बार उम्मीदवारों के नाम शॉर्टलिस्ट करने के बाद भी केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय ब्रजेश्वर सिंह के उत्तराधिकारी का चुनाव नहीं कर पाया. इस विभाग के मंत्री कमलनाथ के लिए सोचने का मुद्दा यह भी है कि जुलाई 2006 और दिसंबर 2008 के बीच एनएचएआई के अध्यक्ष को पांच बार क्यों बदलना पड़ा. हालांकि इसी से सरकार की मजबूरी को भी समझा जा सकता है कि वह क्यों नए अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर पाई. ऐसा लगता है कि अब तो कुछ करना ही होगा.

पर्दे में रहने दो

दिल्ली के सियासी गलियारों में शीर्ष नौकरशाहों की कोटरियों का होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाल के दिनों में ऐसी ही एक नई कोटरी के उदय ने लोगों के कान खड़े कर दिए हैं. शीर्ष अधिकारियों की कोटरी गोपनीय तरीके से महीने में एक बार मिलती है और लंच के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मद्दों पर गंभीर चर्चा करती है. अब तक मिले संकेतों से तो यही लगता है कि इन बैठकों में खाने का मेन्यू तो अच्छा होता ही है, इनमें होने वाला विचार–विमर्श भी काफ़ी संतोषजनक होता है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, इस समूह में कैबिनेट सचिव के एम चंद्रशेखर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन, गृह सचिव जी के पिल्लई, विदेश सचिव निरुपमा राव, थलसेना अध्यक्ष जनरल वी के सिंह, एयर चीफ मार्शल पी वी नाइक, एडमिरल निर्मल वर्मा और रक्षा सचिव प्रदीप कुमार शामिल हैं. ये सभी पिछले कुछ महीनों से लगातार मासिक बैठकें कर रहे हैं, जहां देश की सुरक्षा से जुड़े मामलों पर गंभीर, लेकिन अनौपचारिक विचार मंथन किया जाता है. सत्ता के गलियारों पर निगाह रखने वाले लोग बैठक के नतीजों से ज़्यादा उन लोगों के बारे में जानना चाह रहे हैं, जो इस समूह के सदस्य नहीं हैं. इसमें भी कोई संदेह नहीं कि शीर्ष पदों पर क़ाबिज़ अधिकारियों की यह कोटरी अनावश्यक ही अपना वक़्त बर्बाद नहीं कर रही होगी और आने वाले दिनों में हमें इन बैठकों के बारे में चटखारेदार ख़बरें सुनने को मिल सकती हैं. ये ख़बरें या तो इनमें शरीक लोगों से मिलेंगी या उन लोगों से, जो किसी वजह से इसमें शामिल नहीं हो पाए हैं.

वन अधिकारियों के जंगली किस्से

हाल के दिनों में सरकार लंबे समय से उपेक्षा के शिकार रहे भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के प्रति कुछ ज़्यादा ही उदार रही है. प्रशिक्षण के लिए नए कार्यक्रमों, शिक्षा एवं शोध कार्यों के लिए वन अधिकारियों को विदेश भेजे जाने के फ़ैसले लिए गए हैं, लेकिन अब इन फ़ैसलों पर कहीं नए सिरे से सोचना न पड़े. अभी थोड़े दिन पहले एक चीनी महिला ने मध्य प्रदेश के एक अधिकारी पर कनाडा में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान दुर्व्यवहार का आरोप लगाया और इससे सरकारी हलकों में चिंता की लकीरें खिंच गईं. हालांकि वन सेवा के अधिकारी एक अन्य बात को लेकर राहत महसूस कर सकते हैं. इसकी वजह यह है कि सरकार ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के उस प्रस्ताव को फ़िलहाल टाल दिया है, जिसमें उन्होंने वन एवं वन्यजीवों के लिए अलग–अलग विभागों के गठन का सुझाव दिया था.

dilipcherian@gmail..com

साउथ ब्लॉक

सीबीआई के निशाने पर 5 अधिकारी

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के पांच वरिष्ठ अधिकारी सीबीआई के निशाने पर हैं. हालांकि अधिकारियों के नामों को अभी गुप्त रखा गया है. ऐसा माना जा रहा है कि सीबीआई जांच के निर्णय से भानुमती का पिटारा खुल सकता है. स्वास्थ्य मंत्रालय में इन अधिकारियों के आगे किसी की नहीं चलती है. कई नेता भी इन अधिकारियों से परेशान थे और तमाम कोशिशों के बाद भी इन्हें हटवा पाने में असफल रहे थे. स्वास्थ्य राज्य मंत्री दिनेश त्रिवेदी भी अधिकारियों की मनमानी से परेशान थे.

संजीव रंजन संयुक्त सचिव!

आईएएस अधिकारी संजीव रंजन भारत सरकार में पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग में संयुक्त सचिव बनाए जा सकते हैं. संजीव रंजन पश्चिम बंगाल कैडर के 1979 बैच के आईएएस अधिकारी दिलीप रथ का स्थान लेंगे. रथ की वापसी उनके मूल कैडर में हो गई है.

नए दूरसंचार सचिव की तलाश

जनैतिक और अधिकारिक गलियारों में अगले दूरसंचार सचिव की नियुक्ति की चर्चा ज़ोरों पर है. सूत्रों की मानें तो यह तत्काल संभव नहीं है. हालांकि आंध्र प्रदेश के 1975 बैच के आईएएस अधिकारी एवं सूचना और तकनीकी विभाग के सचिव आर चंद्रशेखर को दूरसंचार मंत्रालय में अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया था. ख़बर है कि दूरसंचार मंत्री ए राजा इस मामले पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से बहुत जल्द मिलने वाले हैं. इस पद के लिए तीन वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों ने ज़ोर–शोर से मंत्रालय के चक्कर लगाने शुरू कर दिए हैं.

मित्तल कोलकाता टी बोर्ड के चेयरमैन होंगे

आख़िरकार यह तय हो गया कि 1983 बैच के आईएएस अधिकारी के के मित्तल वाणिज्य विभाग के तहत आने वाले टी बोर्ड, कोलकाता के नए चेयरमैन होंगे. मित्तल आईएएस अधिकारी बासुदेव बनर्जी की जगह लेंगे, जो अपना कार्यकाल इसी साल अक्टूबर में पूरा करेंगे. मित्तल का यह पद संयुक्त सचिव के बराबर है.

चार आईपीएस बनेंगे संयुक्त सचिव

1982 बैच के चार आईपीएस अधिकारी भारत सरकार में संयुक्त सचिव या समकक्ष पद के लिए सूचीबद्ध किए गए हैं. इनके नाम हैं–उत्तर प्रदेश कैडर के प्रवीण सिंह एवं रामदेव, केरल कैडर के अलेक्जेंडर जेकब और पश्चिम बंगाल कैडर के प्रभु रेड्डी.

मिलिए लोकतंत्र के राजाओं से

पृष्ठ 1 का शेष

उन्हीं की पार्टी के मुख्यमंत्री अपने आवास की रंगाई–पुताई पर पांच सालों में 86 लाख रुपया पानी की तरह बहा देते हैं. उत्तर प्रदेश में मायावती की शाही आदत के मुताबिक़ ही उनके आवास के रखरखाव पर बेशुमार पैसा ख़र्च किया जा रहा है. और यह सब कुछ हो रहा है एक ऐसे देश में, जहां का हर तीसरा नागरिक ग़रीब है. 70 फ़ीसदी आबादी की रोज की आय 20 रुपये से भी कम है. ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2009 के आंकड़ों के मुताबिक़, भारत में भूखे एवं कुपोषित लोगों की संख्या पाकिस्तान, नेपाल, सूडान, पेरू, मालावी और मंगोलिया जैसे देशों से भी ज़्यादा है. पांच साल से कम उम्र के अंडरवेट (उम्र के हिसाब से कम वजन) बच्चों की सूची में भारत की हालत बांग्लादेश, पूर्वी तिमोर और यमन जैसी है. भारत में नाइजीरिया के मुक़ाबले ज़्यादा भूखे और कुपोषित लोग हैं. देश की राजधानी दिल्ली की जन वितरण प्रणाली के तहत ज़्यादातर ग़रीब परिवारों के पास राशनकार्ड नहीं हैं. एपीएल कोटे वाले के पास बीपीएल कार्ड हैं. उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र में किसान मर रहे हैं, लेकिन इस सबसे बेपरवाह हमारे माननीय मुख्यमंत्रीगण इसी धरती पर स्वर्ग का मज़ा ले रहे हैं.

यह सब कुछ एक ऐसे देश में हो रहा है , जहां का हर तीसरा नागरिक ग़रीब है. ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2009 के आंकड़ों के मुताबिक़, भारत में भूखे एवं कुपोषित लोगों की संख्या पाकिस्तान, नेपाल, सूडान, पेरू, मालावी और मंगोलिया जैसे देशों से भी ज़्यादा है. अंडरवेट बच्चों की सूची में भारत की हालत बांग्लादेश, पूर्वी तिमोर और यमन जैसी है. जन वितरण प्रणाली के तहत ज़्यादातर ग़रीब परिवारों के पास राशनकार्ड नहीं हैं. उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र में किसान मर रहे हैं. लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्रीगण इसी धरती पर स्वर्ग का मज़ा ले रहे हैं.

राज्यवार मुख्यमंत्री आवास पर ख़र्च, वित्तीय वर्ष 2005–06 से 2009–10 के दौरान

उत्तर प्रदेश

हिंदी पट्टी के बीमारू राज्यों में से एक है उत्तर प्रदेश. 2005 से अब तक यहां के मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव और मायावती. एक ख़ुद को समाजवादी कहते हैं तो दूसरी ख़ुद को दलितों का मसीहा. इन समाजवादी और दलितों के मसीहा की निजी ज़िंदगी में कितना समाजवाद है, दलितों के लिए कितनी चिंता है, इसका खुलासा इनके आवास (मुख्यमंत्री आवास) पर होने वाले ख़र्च को देखकर हो जाता है. इन पांच सालों में मुख्यमंत्री आवास का बिजली बिल आया लगभग 92 लाख रुपये का. यानी हर साल लगभग 20 लाख रुपये. महीने के हिसाब से लगभग डेढ़ लाख रुपये. मुख्यमंत्री आवास को जगमग बनाने के लिए बल्ब, सीएफएल बदलने और बिजली मरम्मत इत्यादि पर भी 13 लाख रुपये ख़र्च किए गए. साथ ही मुख्यमंत्री आवास में एसी और इलेक्ट्रानिक उपकरण इत्यादि लगाने पर भी 33 लाख रुपये ख़र्च किए गए. टेलीफोन बिल भी आया 19 लाख का. दरवाजे और खिड़कियों के पर्दे बदलने में भी 35 लाख रुपये ख़र्च हो गए. बदरंग उत्तर प्रदेश की तस्वीर सुंदर दिखाने के लिए मुख्यमंत्री आवास की रंगाई–पुताई भी जमकर की गई.

महाराष्ट्र

महाराष्ट्र की एक और पहचान है. वह है विदर्भ. जहां के हर गांव में बड़ी संख्या में वैसी विधवाएं मिल जाती हैं, जिनके पति किसान थे और फ़सल अच्छी न होने की वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली थी. लेकिन इस राज्य के मुखिया चाहे वह विलासराव देशमुख रहे हों या अभी के मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, किसी को कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता. कम से कम उनकी निजी ज़िंदगी और उस पर आने वाले ख़र्च, जो जनता की जेब से चुकाए जाते हैं, को देखकर तो यही लगता है. महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादन विदर्भ क्षेत्र में होती है, लेकिन सारी बिजली मुंबई, नागपुर और पुणे जैसी जगहों के लिए आरक्षित कर ली जाती है. विदर्भ अंधेरे में डूबा रहता है, लेकिन मुंबई में मुख्यमंत्री आवास दिन–रात गुलज़ार रहता है. पिछले 5 सालों में इसकी क़ीमत भी जनता ने चुकाई है, 92.26 लाख रुपये. विदर्भ के किसानों की फ़सल भले ही सूखे से बर्बाद हो जाती है, लेकिन मुख्यमंत्री आवास में पानी के बिल/मिनरल वाटर के मद में 61.74 लाख रुपये ख़र्च हो जाते हैं. विदर्भ का बदरंग चेहरा मुख्यमंत्री को परेशान न करे, इस खातिर उनके आवास की रंगाई–पुताई पर पिछले 5 सालों में 86 लाख रुपये ख़र्च कर दिए गए.

दिल्ली

मुख्यमंत्री आवास पर ख़र्च के मामले में दिल्ली उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से काफी पीछे है, ख़र्च भी काफी कम है. वैसे यहां भी 47 हज़ार रुपये का मिनरल वाटर 2006–09 के दौरान पिया गया. बिजली और पानी का बिल भी क़रीब 10 लाख रुपये आया. टेलीफोन बिल क़रीब 6 लाख रुपये का.

shashishekhar@chauthiduniya.com

भूतपूर्व को भी अभूतपूर्व सुविधा

हाल तक झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं पर भी सालाना करोड़ों का ख़र्च था. हालांकि अब राज्यपाल ने इस सुविधा को ख़त्म करने का आदेश दे दिया है. झारखंड के 4 भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों शिबू सोरेन, बाबूलाल मरांडी, मधु कोड़ा एवं अर्जुन मुंडा के आवास, सुरक्षा और टेलीफोन बिल पर करोड़ों रुपये ख़र्च होते थे. शिबू सोरेन मुख्यमंत्री रहते जितने बड़े बंगले में नहीं रहते थे, उससे बड़ा बंगला उन्हें भूतपूर्व बन जाने पर मिला हुआ था. इन पूर्व मुख्यमंत्रियों के आवासों की देखरेख और साजसज्जा पर पिछले 6 सालों में 13 करोड़ रुपये ख़र्च हुए थे. पिछले वित्तीय साल के दौरान सिर्फ़ सुरक्षाकर्मियों का वेतन ही क़रीब 17 लाख रुपये आया. ध्यान दीजिए, भूतपूर्वों के उक्त शाही ख़र्च झारखंड जैसे राज्य में वहन किए जा रहे थे.

चौथी दुनिया
देश का पहला साप्ताहिक अखबार

वर्ष 2 अंक 28
दिल्ली, 20 सितंबर–26 सितंबर 2010

संपादक
संतोष भारतीय

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63, नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के – 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय

के –2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग
कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा
गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301

फोन न.

संपादकीय 0120–4783999/11–23418962
विज्ञापन + 91 9873575318
प्रसार + 91 9013478398
फैक्स न. 0120–4783950

पृष्ठ–16 (+4)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

बिहार में नक्सलियों के प्रभाव को देखते हुए इस तरह की सावधानी ज़रूरी बताई जा रही है. पिछली बार चार चरणों में चुनाव कराए गए थे, पर इस बार नक्सलियों के बढ़ते प्रभाव का नतीजा है कि दो चरण बढ़ा दिए गए.

बिहार विधानसभा चुनाव छह चरणों में

नीतीश-लालू को बोनस

फोटो- सुनील मल्होत्रा

छह चरणों में राज्य विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है. लंबा चुनाव कार्यक्रम कई दलों के लिए वरदान बनकर सामने आया है, लेकिन जनसामान्य चिंतित है. वजह, चुनाव के दौरान परिवहन के सार्वजनिक साधनों का सरकारी इस्तेमाल और रोजमर्रा की जिंदगी में सुरक्षा व्यवस्था से पैदा होने वाली दिक्कतें. जिस समय चुनाव हो रहे होंगे, उसी दौरान कई पर्व पड़ेंगे और शादी-ब्याह का मौसम भी होगा. लेकिन चुनाव आयोग के सामने भी एक गंभीर चुनौती है कि चुनाव को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष तरीके से कैसे संपन्न कराया जाए, क्योंकि राज्य के कई विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं, जहां नक्सलियों का वर्चस्व है.

सरोज सिंह

बिहार विधानसभा चुनाव छह चरणों में कराने की घोषणा ने एक साथ दो सवालों को जन्म दिया. पहला यह कि क्या इतनी लंबी चुनावी प्रक्रिया नक्सलियों के मंसूबों को नाकाम करने का कदम है और दूसरा यह कि कहीं इस थकाऊ कार्यक्रम से कुछ राजनीतिक दलों को जाने-अनजाने फ़ायदा तो नहीं मिल जाएगा? दोनों ही सवालों का जवाब तो उस समय मिलेगा, जब वोट पड़ेंगे, पर चुनाव आयोग की घोषणा के बाद राजनीतिक गलियारों में बहस तेज़ हो गई है. पहले सवाल पर मतभेद कम हैं. बिहार में नक्सलियों के प्रभाव को देखते हुए इस तरह की सावधानी ज़रूरी बताई जा रही है. पिछली बार चार चरणों में चुनाव कराए गए थे, पर इस बार नक्सलियों के बढ़ते प्रभाव का नतीजा है कि दो चरण बढ़ा दिए गए. हर चरण में कुछ सीटें नक्सलियों के प्रभाव वाली हैं, जहां ये चुनावी प्रकिया को बाधित या कहें प्रभावित करने की हैसियत रखते हैं. पहले चरण में सिमरी बख्तियारपुर और महिषी, दूसरे चरण में मीनापुर, पारू और साहेबगंज, तीसरे चरण में वाल्मीकिनगर, रामनगर (सुरक्षित), राघोपुर व पातेपुर (सुरक्षित), चौथे चरण में अलौली (सुरक्षित), सूर्यगढ़ा, तारापुर, जमालपुर, कटोरिया (सुरक्षित), बेलहर, सिकंदरा (सुरक्षित), जमुई, झाझा और चकाई में नक्सलियों से निपटने के लिए भारी सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं. इन सीटों पर मतदान का समय भी बदल गया है. इन सीटों पर सुबह सात बजे से दोपहर तीन बजे तक ही वोट डाले जाएंगे. इसी तरह पांचवें चरण में रजौली (सुरक्षित), गोविंदपुर, अरवल, कुर्था, जहानाबाद, घोसी, मखदुमपुर (सुरक्षित), बोधगया (सुरक्षित), फुलवारी (सुरक्षित), मसौढ़ी (सुरक्षित), पालीगंज और बिक्रम और छठे चरण में भभुआ, चैनपुर, चेनारी (सुरक्षित), सासाराम, दिनारा, डेहरी, काराकाट, गोह, नवीननगर, कुटुंबा(सुरक्षित), रफीगंज, गुरूआ, शेरघाटी, इमामगंज (सुरक्षित), बाराचट्टी (सुरक्षित) और टेकारी में नक्सलियों की ताकत को देखते हुए आयोग विशेष इंतजाम करने में जुट गया है. आयोग का तर्क है कि सुरक्षाबलों की समुचित तैनाती के लिए ही इस तरह का चुनाव कार्यक्रम बनाया गया है. आयोग का यह तर्क बहुत हद तक लोगों के गले उतर रहा है, पर इतने लंबे चुनाव कार्यक्रम के दौरान दैनिक कार्यों में होने वाली असुविधा को लेकर लोगों के पसीने छूटने लगे हैं. पिछला अनुभव रहा है कि इस तरह के चुनाव कार्यक्रम का सबसे ज़्यादा असर परिवहन व्यवस्था पर पड़ता है. चुनाव कार्यों में गाड़ियों के लग जाने से लोगों को आने-जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है. जो थोड़े-बहुत वाहन सड़कों पर दौड़ते हैं, वे मनमाना किराया वसूलते हैं. चूंकि प्रभावशाली लोगों की गाड़ियां सड़कों पर होती हैं, इसलिए आम जनता का विरोध कोई मायने नहीं रखता. यहां ध्यान देने वाली बात यह भी है कि चुनाव के दौरान सारे बड़े पर्व पड़ रहे हैं. इसके अलावा इसी दौरान शादी-ब्याह की तैयारी भी शुरू होनी है. मतलब साफ़ है कि आम लोगों को परेशानी झेलनी ही झेलनी है. दशहरा, दीपावली एवं छठ में लाखों बिहारी जो राज्य के बाहर काम करते हैं, अपने घर आते हैं. यही वक़्त होता है, जब ये लोग अपने सामाजिक सरोकार का खाता खोलते हैं और इसे मज़बूत करते हैं. यानी कि वे अपने रिश्तेदारों के घर जाते हैं और ख़ुद को समाज की मुख्यधारा से जोड़ते हुए सुख-दुःख बांटते हैं, पर इस बार इनके पैरों का बंधना तय है. इसके अलावा देखा गया है कि चुनाव प्रक्रिया लंबी होने का असर दैनिक उपभोक्ता वस्तुओं पर भी पड़ता है. खाने-पीने की चीज़ों के दाम भी आसमान छूने लगते हैं. इस बार छह चरणों में चुनाव होने के कारण इस तरह की दिक्कतों में इज़ाफ़ा होने की आशंका है. अब हम बात दूसरे सवाल की करते हैं.

चुनावी कार्यक्रम

चरण	अधिसूचना जारी करने की तिथि	नामांकन की अंतिम तिथि	नामांकन पत्रों के जांच की तिथि	नामांकन वापस लेने की तिथि	मतदान की तिथि
प्रथम चरण	सोमवार 27.09.2010	सोमवार 04.10.2010	मंगलवार 05.10.2010	गुरुवार 07.10.2010	गुरुवार 21.10.2010
दूसरा चरण	बुधवार 29.09.2010	बुधवार 06.10.2010	गुरुवार 07.10.2010	शनिवार 09.10.2010	रविवार 24.10.2010
तीसरा चरण	सोमवार 04.10.2010	सोमवार 11.10.2010	मंगलवार 12.10.2010	गुरुवार 14.10.2010	गुरुवार 28.10.2010
चौथा चरण	गुरुवार 07.10.2010	गुरुवार 14.10.2010	शुक्रवार 15.10.2010	सोमवार 18.10.2010	सोमवार 01.11.2010
पांचवां चरण	शुक्रवार 15.10.2010	शुक्रवार 22.10.2010	शनिवार 23.10.2010	सोमवार 25.10.2010	मंगलवार 09.11.2010
छठा चरण	बुधवार 27.10.2010	बुधवार 03.11.2010	गुरुवार 04.11.2010	शनिवार 06.11.2010	रविवार 20.11.2010

चुनाव प्रक्रिया लंबी होने से जाने-अनजाने कुछ राजनीतिक दलों को फ़ायदा मिलने की बात पर एक राय नहीं है. माना जाता है कि इस तरह के कार्यक्रम से उन दलों को फ़ायदा मिलता है, जिनके पास नेताओं की कमी है. ज़्यादा चरणों में चुनाव होने से इन दलों के नेता हर जगह जा सकते हैं. इशारा जदयू, लोजपा एवं राजद की तरफ़ है. चूंकि कांग्रेस एवं भाजपा जैसी बड़ी पार्टियों के पास नेताओं की कोई कमी नहीं है तो इन्हें कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता है. अगर चुनाव एक या दो चरण में भी होते हैं तो ये दल अपने किसी न किसी बड़े नेता को हर विधानसभा क्षेत्र में भेज सकते हैं. लेकिन लालू प्रसाद, नीतीश कुमार एवं रामविलास पासवान चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकते. ज़्यादा चरणों में चुनाव होने से छोटी पार्टियों को संसाधन जुटाने का भी समय मिल जाता है. सबसे बड़ी बात यह होती है कि उम्मीदवारों के चयन के लिए काफ़ी वक़्त इन्हें मिल जाता है और ये हर चरण के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करते हैं. एक साथ पूरी सूची जारी करने के दबाव से बच जाते हैं. इसके अलावा इन नेताओं को एक फ़ायदा यह भी मिलता है कि अगर एक चरण में कोई ग़लती रह गई तो बाद के चरण में उसे सुधारने का वक़्त मिल जाता है. इस बार के चुनाव में एक ख़ास बात यह भी होगी कि पर्व के मौक़े पर लाखों की संख्या में घर आने वाले बिहारी भी अपना वोट डाल सकेंगे. उम्मीद की जा रही है कि इन वोटों का फ़ायदा राजद एवं जदयू को मिलेगा. बाहर रहने वाले बिहारी मोटे तौर पर लालू प्रसाद एवं नीतीश कुमार को ही अपना नेता मानते हैं. यह ऐसा वोट होगा, जो कई क्षेत्रों में चुनाव परिणामों को प्रभावित कर सकता है. ख़ासकर मिथिलांचल के इलाक़े में ये वोट काफ़ी असर डालेंगे. राज्य से बाहर जाकर कमाने वाले ज़्यादातर वही लोग हैं, जो लालू एवं नीतीश के वोटर रहे हैं. चुनाव के मौक़े पर इनका अपने घरों में रहना जदयू एवं राजद के लिए बोनस की तरह है.

feedback@chauthiduniya.com

मतदान कब और कहां

प्रथम चरण 21 अक्टूबर (47 सीटें)
हरलाखी, बेनीपट्टी, खजौली, बाबूबरही, विस्फी, मधुबनी, राजनगर (अजा.), झंझारपुर, फूलपरास, लौकहा, निर्मली, पिपरा, सुपौल, त्रिवेणीगंज (अजा.), फारबिसगंज, अररिया, जोकीहाट, सिकटी, बहादुरगंज, ठाकुरगंज, किशनगंज, कोचाधामन, अमौर, बायसी, कसबा, बनमनखी (अजा.), रूपौली, धमदाहा, पूर्णिया, कटिहार, कदवा, बलरामपुर, प्राणपुर, मनिहारी (अजजा.), बरारी, कोढ़ा (अजा.), मधेपुरा, सोनवर्षा (अजा.), सहरसा, सिमरी बख्तियारपुर, महिषी.

दूसरा चरण 24 अक्टूबर (45 सीटें)
शिवहर, रीगा, बथनाहा (अजा.), परिहार, सुरसंड, बाजपट्टी, सीतामढ़ी, रुन्नीसैदपुर, बेलसंड, कुशेश्वर स्थान (अजा.), गौराबौरम, बेनीपुर, अलीनगर, दरभंगा ग्रामीण, दरभंगा, हायाघाट, बहादुरपुर, केवटी, जाले, गायघाट, औराई, बोचहा (अजा.), सकरा (अजा.), कुढ़नी, मुजफ्फरपुर, कांटी, वरूराज, कल्याणपुर (अजा.), वारिसनगर, समस्तीपुर, उजियारपुर, मोरवा, सरायरंजन, मोहिउद्दीननगर, विभूतिपुर, रोसड़ा (अजा.), हसनपुर, नरकटिया, पिपरा, मधुबन, चिरैया, ढाका, मीनापुर, पारू, साहेबगंज.

तीसरा चरण 28 अक्टूबर (48 सीटें)
नरकटियागंज, बगहा, लौरिया, नौतन, चनपटिया, बेतिया, सिकटा, रक्सौल, सुगौला, हरसिद्धि (सु.), गोविंदगंज, केसरिया, कल्याणपुर, मोतिहारी, बैकुंठपुर, बरौली, गोपालगंज, कुचायकोट, भोरे (सु.), हथुआ, सीवान, जीरादेई, दरौली (सु.), रघुनाथपुर, दरौंधा, बरहड़िया, गोरियाकोठी, महराजगंज, एकमा, मांझी, बनियापुर, तैरया, मढ़ौरा, छपरा, गरखा (सु.), महनार, वाल्मीकि नगर, रामनगर (सु.), राघोपुर व पातेपुर, अमनौर, परसा, सोनपुर, हाजीपुर, लालगंज, वैशाली, महुआ, राजापाकर(सु.).

चौथा चरण 1 नवंबर (42 सीटें)
चेरिया बरियारपुर, बछवारा, तेघड़ा, मटिहानी, साहेबपुर कमाल, बेगूसराय, बखरी (सु.), खगड़िया, बेलदौर, परबत्ता, लखीसराय, मुंगेर, बिहपुर, गोपालपुर, पीरपैंती (सु.), कहलगांव, भागलपुर, सुल्तानगंज, नाथनगर, मोकामा, बाढ़, बख्तियारपुर, दीघा, बांकीपुर, कुम्हरार, पटना साहिब, फतुहा, दानापुर, मनेर, अमरपुर, धोरैया (सु.) एवं बाका चौथे चरण में ही सुबह 7 बजे से 3 बजे तक जिन विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होने हैं, उनमें अलौली (सु.), सूर्यगढ़ा, तारापुर, जमालपुर, कटोरिया (सु.), बेलहर, सिकंदरा (सु.), जमुई, झाझा एवं चकाई विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं.

पांचवां चरण 9 नवंबर (35 सीटें)
संदेश, बड़हरा, आरा, अगिआंव (सु.), तरारी, जगदीशपुर, शाहपुर, हिसुआ, नवादा, वारसलीगंज, गया टाउन, बेलागंज, अतरी, वजीरगंज, शेखपुरा, बरबीघा, अस्थावां, बिहारशरीफ, राजगीर (सु.), इस्लामपुर, हिलसा, नालंदा, हरनौत, रजौली, गोविंदपुर, अरवल, कुर्था, जहानाबाद, घोसी, मकदुमपुर (सु.), बोधगया (सु.), फुलवारी (सु.), मसौढ़ी (सु.), पालीगंज व बिक्रम.

छठा चरण 20 नवंबर (26 सीटें)
ब्रह्मपुर, बक्सर, डुमरांव राजपुर (सु.), रामगढ़, मोहनिया (सु.), करगहर, नोखा, ओबरा एवं औरंगाबाद में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक, जबकि भभुआ, चेनपुर, चेनारी (सु.), सासाराम, दिनारा, डेहरी, काराकाट, गोह, नबीनगर, कुटुंबा (सु.), रफीगंज, गुरूआ, शेरघाटी, इमामगंज (सु.), बाराचट्टी (सु.) एवं टिकारी में सुबह 7 बजे से 3 बजे तक मतदान होगा.

आज की तारीख़ में माओवाद की राजनीति करने के मामले में बंगाल, ख़ासकर उसकी भावी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सबसे आगे हैं. बंगाल में सुरक्षाबलों का संयुक्त अभियान जारी है.

पश्चिम बंगाल

राजनीतिक उठापटक का दौर जारी

ममता का लालगढ़ में सभा करना, आंध्र में मारे गए माओवादी नेता आज़ाद की हत्या की जांच की मांग करना, ज्ञानेश्वरी ट्रेन हादसे को किसी बड़े षड्यंत्र से जोड़ना माओवाद के नाम पर जघन्य राजनीति नहीं तो क्या है? दोयम दर्जे की इस राजनीतिक कथा में ड्रामा, असंवेदनशीलता, निर्लज्जता या वैचारिक अश्लीलता सब कुछ है. तृणमूल के सांसद दिल्ली में गले में पोस्टर टांग कर माकपा कैडरों के शिविर नष्ट करने की मांग करते हैं और उनमें तस्वीरें होती हैं दंतेवाड़ा के नक्सलियों की.

बिमल राय

देश में माओवादियों के ख़िलाफ़ चल रही जंग को बंगाल की राजनीतिक उठापटक ने काफ़ी उलझा दिया है. आदिवासियों के हितैषियों एवं मानवाधिकारों के बड़े-बड़े झंडाबरदारों का मुखौटा उतर रहा है. बंगाल में हो रही इस हलचल का ख़ामियाज़ा देश के दूसरे हिस्सों को भी भुगतना पड़ रहा है. बिहार के लखीसराय में पुलिस के जवानों को बंधक बनाने की जो कार्रवाई हुई, उसका चस्का नक्सलियों को बंगाल में मिली कामयाबी से लगा. पिछले साल 20 अक्टूबर को माओवादियों ने सांकराइल थाने के ओसी अतींद्रनाथ दत्त को बंधक बना लिया था और उसके बदले सरकार को 20 महिला नक्सलियों को ज़मानत पर रिहा कराना पड़ा था.

आज की तारीख़ में माओवाद की राजनीति करने के मामले में बंगाल, ख़ासकर उसकी भावी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सबसे आगे हैं. बंगाल में सुरक्षाबलों का संयुक्त अभियान जारी है. अपने समर्थकों की लगातार हत्याओं की वजह से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कैडरों को भी माओवादियों से सीधे लोहा लेना पड़ रहा है. अब ममता इसे माकपाइयों का सशस्त्र शिविर कह रही हैं और केंद्र सरकार का अहम घटक होने के कारण गृहमंत्री पी चिदंबरम भी उनकी हां में हां मिला रहे हैं. अब यह बात छिपी नहीं रही कि ममता पूरी तरह माओवादियों के साथ हैं और उन्हीं के बूते पर पश्चिम मेदिनीपुर, बांकुड़ा एवं पुरुलिया ज़िलों के जंगलमहल में अपनी जड़ और ज़मीन मज़बूत करने में लगी हैं. ममता माकपा कैडरों के पास रखे गए हथियारों की बरामदगी की मांग कर रही हैं, पर दरअसल उन्हीं हथियारों के बूते ही माकपा सुरक्षाबलों की मदद करने के साथ ही नक्सल प्रभावित इलाक़ों में अपने अस्तित्व की जंग लड़ रही है. 3 सितंबर को लालगढ़ के पीराकाटा में पत्रकारों पर हुए कथित माकपाइयों के हमले पर बयान जारी करते हुए ममता ने एक बार फिर सुरक्षाबलों का अभियान रोकने की मांग की. उन्होंने धरमपुर से भागे लोगों की घर वापसी की तुलना नंदीग्राम दखल से की. मालूम हो कि माओवादियों के अत्याचार से धरमपुर के लोग भागकर कई महीनों से शिविरों में रह रहे थे.

ममता का लालगढ़ में सभा करना, आंध्र में मारे गए माओवादी नेता आज़ाद की हत्या की जांच की मांग करना, ज्ञानेश्वरी ट्रेन हादसे को किसी बड़े षड्यंत्र से जोड़ना माओवाद के नाम पर जघन्य राजनीति नहीं तो क्या है? दोयम दर्जे की इस राजनीतिक कथा में ड्रामा, असंवेदनशीलता, निर्लज्जता या वैचारिक अश्लीलता सब कुछ है. तृणमूल के सांसद दिल्ली में गले में पोस्टर टांग कर माकपा कैडरों के शिविर नष्ट करने की मांग करते हैं और उनमें तस्वीरें होती हैं दंतेवाड़ा के नक्सलियों की. कई तस्वीरें तो गूगल से नक्सल सर्च करने के बाद पहले ही पेज पर दिख जाती हैं. पी चिदंबरम की ओर से इस मसले पर मासिक प्रेस कांफ्रेंस में चर्चा करने को ममता बड़ी कामयाबी मानती हैं और अगले दिन राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करती हैं. आख़िर में वाममोर्चा के चेयरमैन विमान बोस को सफ़ाई देनी पड़ती है कि उक्त शिविर माओवादियों के अत्याचार से घर छोड़ने वाले लोगों के लिए बनाए गए हैं. मालूम हो कि संसदीय चुनावों के बाद से नक्सलियों ने 225 माकपा कैडरों का ख़ून किया है. ममता यह भी भूल गईं कि नक्सलियों के ख़िलाफ़ सुलग रहे गांव वालों के आक्रोश को भी उनकी इन हरकतों से कितना आघात लगेगा. यही नहीं, 2 सितंबर को तृणमूल की कोर कमेटी की बैठक में ममता शिविर के मामले को मुख्य एजेंडा बनाती हैं और नए पुलिस महानिदेशक से मिलने का कार्यक्रम तय करती हैं. ममता को मालूम है कि जंगलमहल में माकपा के 93 शिविर चल रहे हैं. वह 6 सितंबर को केशपुर अभियान, 9 को धरमपुर से लालगढ़ की यात्रा, 13 सितंबर को डीएम-एसपी कार्यालयों के सामने प्रदर्शन, 15 से सासन से भांगड़ तक पदयात्रा, 19 को नानूर और 25 को सिंगुर चलो अभियान का भी कार्यक्रम बनाती हैं. ममता के इन कार्यक्रमों में नक्सल और दलीय हिंसा से प्रभावित इलाक़े भी आते हैं. पिछला अनुभव यही बताता है कि जब-जब ममता के दौरे हुए हैं, ज़्यादातर इलाक़ों में बवाल हुआ है. यह समझने में कोई मुश्किल नहीं है कि आंदोलन करने के अपने संवैधानिक अधिकार के बहाने वह अगले विधानसभा चुनावों तक बंगाल में बवाल को ज़िंदा रखना चाहती हैं.

तृणमूल की मुखिया ममता के व्यस्त कार्यक्रमों की तर्ज पर बंगाल में रेल दुर्घटनाएं व लूटपाट की वारदातें भी नियमित रूप से हो रही हैं. रेलमंत्री होने के नाते उन्हें चिंतित होना चाहिए, पर उन्होंने कह दिया कि उनका घर बंगाल है, दिल्ली नहीं. अब जिन लोगों ने यह बयान सुना है, उन्हें टोकाटोकी नहीं करनी चाहिए, पर एक नज़र तो डाल ही लें. इस साल 28 मई को माओवादियों द्वारा की गई तोड़फोड़ के कारण पटरी से उतरी ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस के 148 यात्री मारे गए तो 19 जुलाई को वीरभूम ज़िले के साइथिया में उत्तरबंग एक्सप्रेस वनांचल एक्सप्रेस से जा भिड़ी और 66 लोग मौत की नींद सो गए. 30 अगस्त को बारुईपाड़ा में तकनीकी ख़राबी के कारण राजधानी का इंजन पटरी से उतर कर चलने लगा. लूटपाट की वारदातों ने भी रेलवे को सुर्ख़ियों में रखा है. 2 अगस्त को बंगाल-झारखंड सीमा पर बारविल-हावड़ा जनशताब्दी एक्सप्रेस की तीन एसी कारों में लूटपाट की गई. 6 अगस्त को दिल्ली जा रही लालकिला एक्सप्रेस में बिहार के वंशीपुर और भलुई के बीच यात्रियों को अपने सामान और नकदी से हाथ धोना पड़ा. बीती 3 सितंबर को गोरखपुर जा रही मौर्य एक्सप्रेस को बंगाल के कुल्टी में लूट लिया गया. इनमें बंगाल एवं बिहार के बाहर हुई दुर्घटनाएं और लूट की वारदातें शामिल नहीं हैं. इस तरह अपने राज्य में एक रेलमंत्री के तौर पर ममता की नाकामयाबी साफ़ झलकती है.

राजनीतिक चक्की में पिसते हैं गुर्जंत जैसे लोग

माओवाद से तो नहीं, पर ममता की मौजूदा राजनीतिक शैली से जुड़ा एक और मामला ज़ोर-शोर से उछला. चपेट में आया पंजाब के संगरूर ज़िले का ट्रक चालक गुर्जंत सिंह. गड्डी, गंतव्य और ढाबे के बीच सिमटी उसकी दुनिया में जैसे भूचाल आ गया. उसे क्या पता था कि उस पर बंगाल की भावी मुख्यमंत्री की हत्या का आरोप लगेगा. वह तो ममता बनर्जी को जानता तक नहीं था. पंजाब से प्लास्टिक दाना लेकर चला था और तामलुक में एक ढाबे पर रोटी तड़का खाने के बाद अपनी गड्डी दाएं-बाएं कर रहा था. तभी लालगढ़ से लौट रहीं ममता का काफ़िला गुज़रा और सबसे पिछली एस्कार्ट गाड़ी में टक्कर लगी. ब्रेक फेल होने के कारण हुए इस हादसे से ममता की कार को भी हल्का झटका लगा और बवाल हो गया. इससे ममता कथित तौर पर घायल भी हो गईं. संसद और आंदोलन छोड़कर कई दिनों तक बिस्तर पर पड़ी रहीं. आज़ाद मामले पर दिए गए बयान से संसद में हंगामा होता रहा और ममता अपने घर में स्वास्थ्य लाभ करती रहीं. पी चिदंबरम को सफ़ाई देनी पड़ी कि आज़ाद मामले पर सरकार के रुख़ में कोई तब्दीली नहीं हुई है. प्रणव दादा ने गुलदस्ता भेजकर ममता के जल्दी स्वस्थ होने की कामना की. हालांकि ममता को कौन सी बीमारी हुई थी, किसी को पता नहीं चला. वैसे राजनीतिक हलके में माना गया कि ममता आज़ाद मामले पर हुए बवाल के शांत होने का इंतज़ार कर रही थीं. ममता अपने लालगढ़ दौरे से पहले कह चुकी थीं कि उनकी जान को ख़तरा है. यह एक संयोग ही था कि बेचारा गुर्जंत चपेट में आ गया. पहले तो पुलिस ने ख़तरनाक तरीक़े से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया, पर तामलुक के तृणमूल सांसद शिशिर अधिकारी के कहने पर उसके ख़िलाफ़ हत्या के प्रयास की धारा लगाई गई और मामला सीआईडी के सुपुर्द किया गया. सीआईडी की चुस्ती का आलम यह था कि गुर्जंत को 12 दिन पुलिस लॉकअप में सड़ना पड़ा, क्योंकि सीआईडी ट्रक के ब्रेक फेल होने संबंधी तकनीकी रिपोर्ट नहीं सौंप पाई. यह वही सीआईडी है, जिसके क़ब्ज़े से सिलीगुड़ी के पास पिंटेल विलेज से गोरखालीग के अध्यक्ष मदन तामांग का हत्यारा निकोल तामांग भाग निकला था. वह अब तक गिरफ़्तार नहीं हुआ है और उसकी गिरफ़्तारी के लिए इनाम का ऐलान किया गया है. गुर्जंत के मामले में कोलकाता से लेकर पंजाब तक सिख समुदाय में क्षोभ की लहर दौड़ गई. कई हलकों से अपीलें की गईं, पर मामला एक भावी मुख्यमंत्री से जुड़ा था, सो क़ानून ने अपना रास्ता अख़्तियार किया. कोलकाता की श्री गुरुसिंह सभा के दलजिंदर सिंह की अपील कि गुर्जंत को बलि का बकरा न बनाया जाए, को सुनने वाला कौन है. बलि का बकरा तो हमेशा से आम आदमी ही बनता आ रहा है. वह चाहे गुर्जंत हो या माओवादियों की करतूत से ज्ञानेश्वरी हादसे में मारे गए 148 लोग.

आंध्र में माओवादी आज़ाद के मारे जाने के मामले की जांच की मांग कर ममता ने केंद्र को भी सांसत में डाला, पर उनके बचाव में प्रणव मुखर्जी आगे आते हैं और ऐलान करते हैं कि तृणमूल की मुखिया होने के नाते उन्हें अपने स्वतंत्र विचार रखने की आज़ादी है. मालूम हो कि चिदंबरम ने अपना रुख़ एकदम साफ़ रखा है, इसलिए लीपापोती के लिए प्रणव को मोर्चा संभालना पड़ा. प्रणव ने जो कहा, उसे चिदंबरम के हवाले से नहीं कहलाया जा सकता था. कांग्रेस के लिए ममता अहम हो सकती हैं, पर जिस सरकार के मुखिया नक्सलियों को आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा ख़तरा क़रार दे चुके हों, उस सरकार की एक मंत्री अगर इतना अलग विचार रखती हैं तो फ़र्क़ कैसे नहीं पड़ेगा? इसी साल 28 मई को ज्ञानेश्वरी ट्रेन को पटरी से उतार कर 148 लोगों की हत्या करने वाले नक्सलियों के प्रति उमड़ा प्रेम क्या शर्मनाक नहीं है? रेलवे को भगवान भरोसे छोड़कर बंगाल की राजनीति में पूरी तरह रम जाने वाली ममता यह कैसी राजनीति कर रही हैं? एक महिला होने के नाते 148 परिवारों की चीत्कार को वह इतनी जल्दी कैसे भुला सकती हैं? लेकिन ममता को तो अगले साल मिलने वाली मुख्यमंत्री की कुर्सी दिख रही है और उन्होंने इसके लिए नैतिकता की सारी सीमाएं लांघ दी हैं. पिछले 27 अगस्त को ज्ञानेश्वरी मामले का एक संदिग्ध अभियुक्त उमाकांत महतो मुठभेड़ में मारा जाता है और ममता इस पर शक़ ही नहीं करतीं, बल्कि बयान जारी करती हैं कि वाममोर्चा सरकार ने उसकी हत्या सबूत मिटाने के लिए कराई है. इस संबंध में एक टीवी फुटेज भी दिखाई जाती है कि उसकी हत्या माकपा कैडरों ने की है, पर आख़िर में उसका सत्यापन नहीं हो पाता.

सोचने की बात यह है कि बंगाल में यह सब तब हो रहा है, जब माओवादियों के पैर उखड़ रहे हैं. राधानगर की महिलाओं ने जो बिगुल बजाया था, उसकी गूंज नए-नए इलाक़ों तक पहुंच रही है. राधानगर में ही लोगों ने माओवादी कालू महतो को पकड़ कर सुरक्षाबलों को सौंपा. माओवादी आत्मसमर्पण करने लगे हैं. बेलपहाड़ी के माओवादी कैडर भैरव महतो ने हाल में आत्मसमर्पण किया है और यह सिलसिला जारी है. माओवादियों के प्रति नरम रुख़ अपना रहे नीतीश कुमार जैसे राजनेताओं के हश्र से भी सबक लेना चाहिए, जिनके दामन पर लखीसराय बंधक कांड का दाग लग गया. अब इसमें कोई संदेह नहीं कि माओवादियों का बस एक ही दर्शन है हिंसा और ख़ूनख़राबा, जिन्हें एक सामूहिक राजनीतिक एजेंडे के साथ कड़े हाथों से निपटाया जाना चाहिए.

feedback@chauthiduniya.com

1901 में भारत में 1916 शहर थे जो 1991 में बढकर 3768 हो गए. नब्बे वर्षों के दरम्यान देश में छोटे-बड़े शहरों की संख्या तिगुनी रफ्तार से बढी है, जबकि इन शहरों की आबादी में आठ गुना बढ़ोत्तरी हुई है.

शहरीकरण: कब चेतेंगे हम

दिल्ली में पिछली 26 अगस्त को बारिश हुई तो देश की राजधानी की पोल खुल गई. बारिश की वजह से शहर के 117 इलाक़ों में सड़क पर पानी जमा हो गया, आने-जाने का रास्ता बंद हो गया. ट्रैफिक थम गया. छह मकान ढह गए, जिसमें 4 साल के एक बच्चे की मौत हो गई. एक स्कूल बस सड़क में धंस गई. स्कूल बस में 35 बच्चे थे. सड़क धंसने की ख़बर दिल्ली के कई अन्य इलाक़ों से भी आई. एक दिन की बारिश में दिल्ली का हाल ऐसा है तो छोटे शहरों का हाल क्या होगा. यह तो सिर्फ़ बारिश की समस्या है. हमारे शहरों की समस्याओं की गाथा अनंत है. पीने का पानी, गंदगी, स्वास्थ्य सेवाएं, बिजली, ज़मीन, मकान एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं और हैं भी तो पर्याप्त नहीं हैं. अगर वर्तमान इतना दयनीय है तो भविष्य में क्या होगा?

रीतिका सोनाली

दुनिया में तेज़ी से हो रहे शहरीकरण के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ की हालिया रिपोर्ट के दो आंकड़े गौर करने योग्य हैं. पहला यह कि इस वर्ष के अंत तक विश्व की आधी आबादी शहरों में रहने लगेगी, जबकि भारत में 30 प्रतिशत लोग शहरी होंगे. दूसरा यह कि 2050 तक हिंदुस्तान की आधी आबादी महानगरों, नगरों एवं कस्बों में निवास करेगी और तब तक विश्व स्तर पर शहरीकरण का आंकड़ा 70 प्रतिशत पर पहुंच चुका होगा. दोनों तथ्य दिखा रहे हैं कि हमारे देश में शहरीकरण की रफ्तार शेष दुनिया से कुछ धीमी है. जब आर्थिक विकास की दर आठ और दस प्रतिशत के बीच चल रही हो और कृषि विकास में ठहराव आ गया हो, तब आबादी का स्थानांतरण गांवों से शहरों की ओर होना स्वाभाविक है. पर यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका अर्थ यही निकलेगा कि या तो गांवों में रोज़गार के पर्याप्त अवसर मौजूद हैं अथवा शहर के महंगे जीवनस्तर का बोझ उठाने की कुव्वत गांव वालों में है ही नहीं. महानगरों-बड़े शहरों के तेज़ी से हो रहे विस्तार और आसमान छूते मकान एवं ज़मीन के भाव का नाता प्राय: शहरी मध्य एवं उच्च वर्ग से ही है. रोज़ी-रोटी की तलाश में जबरन गांवों से शहर आने वाले ग़रीब की नसीब में तो झुग्गी-झोपड़ी, अवैध बस्ती या फुटपाथ ही है. शहरों में शिक्षा व स्वास्थ्य जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की आपूर्ति बेहतर होनी चाहिए, लेकिन शहरों में आकर भी ग़रीब की स्थिति पहले जैसी रहती है. मास्टर प्लान के अभाव और अमल के स्तर पर समस्याओं के चलते हमारे अधिकांश नगर स्लम में बदलते जा रहे हैं. पानी, बिजली, सीवर, सड़क आदि केवल गांवों की ही नहीं, महानगरों की भी समस्या है. इसी कारण गांवों की 24 प्रतिशत आबादी, जिसका खेती से कुछ लेना-देना नहीं है, तमाम कष्ट उठाकर भी वहां रह रही है. गांवों से शहर की ओर पलायन करने वाले पुरुषों की संख्या अधिक है, इसलिए गांवों में खेती का बोझ महिलाओं एवं बच्चों पर बढ़ता जा रहा है. लंगड़े विकास के बूते कोई देश दुनिया की आर्थिक महाशक्ति नहीं बन सकता.

1991 की जनसंख्या रिपोर्ट के मुताबिक़, 25.7 प्रतिशत जनसंख्या शहरी थी और यह अनुमान लगाया गया था कि वर्ष 2001 तक यह 28.4 प्रतिशत हो जाएगी, लेकिन 1991 के बाद देश की आर्थिक स्थिति को दुरुस्त करने के लिए सरकार द्वारा उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को प्रोत्साहित किए जाने से शहरीकरण की प्रक्रिया में रफ्तार आई और शहरों में बेतरतीब तरीके से भीड़ बढ़ने लगी. माना जाता है कि शहरी जनसंख्या में प्रतिवर्ष होने वाला 45 प्रतिशत का इज़ाफ़ा लोगों के प्रवासन की वजह से है. 1901 और 1981 के बीच भारत की ग्रामीण जनसंख्या ढाई फीसदी बढ़ी, जबकि शहरी जनसंख्या में 6 गुना बढ़ोत्तरी हुई. देश की 3,287,762 वर्ग किलोमीटर ज़मीन में केवल 43,600 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र शहरी है और बाकी ग्रामीण है. 1901 में भारत में 1916 शहर थे, जो 1991 में बढ़कर 3,768 हो गए. नब्बे वर्षों के दरम्यान देश में छोटे-बड़े शहरों की संख्या तिगुनी रफ्तार से बढ़ी है, जबकि इन शहरों की आबादी में आठ गुना बढ़ोत्तरी हुई है. इस दौरान शहरी आबादी 26 मिलियन से 217 मिलियन हो गई.

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, 10 मिलियन की जनसंख्या वाला शहर मेगा सिटी कहलाता है. 1995 तक भारत में 14 शहर मेगा सिटी में तब्दील हो गए और इसी क्रम में 2015 तक हैदराबाद एवं अन्य भी जुड़ जाएंगे. हमारे देश में 340 मिलियन लोग यानी जनसंख्या का 30 फीसदी हिस्सा शहरों में रहता है और अनुमान के मुताबिक़ 2030 तक 40 प्रतिशत जनसंख्या यानी 590 मिलियन लोग देश के शहरों में रहने लगेंगे. अगले बीस सालों में 180 मिलियन नौजवान देश की सर्विस वर्क फोर्स में शामिल हो जाएंगे और यह जनसमूह भी देश की शहरी जनता में तब्दील हो जाएगा. वर्ष 2030 में देश में 68 शहर होंगे, जिनकी जनसंख्या एक मिलियन से ज़्यादा होगी, अभी यह संख्या 42 है. शहरों की बढ़ती संख्या और शहरीकरण की तेज रफ्तार के बावजूद देश के शहर अभी भी मूलभूत गुणवत्ता की ज़िंदगी प्रदान करने में असमर्थ हैं. देश के शहरों में जलापूर्ति मात्र 105 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है, जबकि ज़रूरत कम से कम 150 लीटर है और आदर्श आपूर्ति मात्रा 220 लीटर प्रतिदिन होनी चाहिए. पाइप से सप्लाई होने वाला पानी केवल 74 प्रतिशत शहरी जनसंख्या तक पहुंच पाता है. शहर के सीवेज और सेप्टिक टैंक कवरेज का फ़ायदा केवल 63 प्रतिशत शहरी जनसंख्या को मिल रहा है. शहर में बने सीवेज में संसाधित सीवेज केवल तीस हैं, जबकि 100 प्रतिशत की ज़रूरत है. संपूर्ण जमा हुए कचरे में केवल 72 प्रतिशत सॉलिड वेस्ट को जमा किया जाता है, बाकी प्रदूषण फैलाने के काम आता है. बारिश या बाढ़ इत्यादि से शहर में घुसे पानी को हटाने के लिए सड़कों पर केवल बीस फीसदी नालियां ही काम कर रही हैं. पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए मास पब्लिक ट्रांजिट का इस्तेमाल केवल 30 प्रतिशत लोग ही कर पाते हैं, जबकि कम से कम 50 प्रतिशत लोगों को यह उपलब्ध होना चाहिए और आदर्श मानकों में 82 प्रतिशत होना चाहिए. शहर में वाहन संकुलन प्रति लेन किलोमीटर 170 है, जबकि ट्रैफिक की समस्या से बचने के लिए यह 112 होना चाहिए और आदर्श अवस्था में यह आंकड़ा 85 होना चाहिए. प्रति 1000 लोगों पर केवल दो हॉस्पिटल बेड हैं, जबकि सामान्यत: 4 और आदर्श अवस्था में 7 होने चाहिए. शहर में स्लम जनसंख्या 24 प्रतिशत है, जबकि यह शून्य होनी चाहिए. पार्क और ओपन एरिया स्क्वायर मीटर प्रति व्यक्ति 2.7 है, जबकि जनसंख्या के हिसाब से यह 9.0 होना चाहिए और आदर्श मानक में 16.0 होना चाहिए. शिक्षा के क्षेत्र में प्रति शिक्षक 48 विद्यार्थी हैं, जबकि सही शिक्षण व्यवस्था को कायम करने के लिए प्रति 16 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए.

2030 में शहरी जनसंख्या की अनुमानित वृद्धि के हिसाब से जलापूर्ति की मांग 2.3 गुना बढ़कर 189 मिलियन लीटर प्रतिदिन हो जाएगी. सीवेज से बहने वाला पानी भी 2.3 गुना बढ़ जाएगा यानी प्रतिदिन 151 मिलियन लीटर हो जाएगा. सॉलिड वेस्ट का जमाव 5 गुना बढ़ने के आसार हैं, यह 377 मिलियन टन प्रतिवर्ष हो जाएगा. देश के शहरों में कारों की संख्या 5.8 गुना बढ़ जाएगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का नंबर ऑफ पब्लिक ट्रिप प्रतिवर्ष 2.7 गुना बढ़ जाएगा. शहरों के विकास की मौजूदा हालत को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में बनने वाले नए शहरों और वर्तमान शहरों की स्थिति चरमरा जाएगी.

आमतौर पर एक प्रशिक्षित महानगरीय योजनाकार शहर की आर्थिक अवस्था, उसका भविष्य, परिवहन व्यवस्था, ज़रूरत, हाउसिंग आदि को ध्यान में रखते हुए योजना बनाता है, जिससे शहर का चतुर्मुखी विकास हो और विकास की गति निरंतर चलती रहे. हमारे देश में भूमि के इस्तेमाल को छोड़कर बाकी सारी प्लानिंग अनौपचारिक हो जाती है. शहर की जर्जर अवस्था का सबसे बड़ा कारण बेकार प्लानिंग है. हमारे शहरों की त्रासदी यह है कि शहर पहले बन जाते हैं, उनके लिए योजना बाद में बनाई जाती है. लोग घर बनाकर नई बस्तियों में रहने लगते हैं, फिर वहां सड़क, सीवेज, पानी, टेलीफोन और बिजली की व्यवस्था के बारे में सोचा जाता है. समस्या यह है कि हमारे योजनाकार प्रशिक्षित नहीं हैं. जो योजनाएं बनाई जाती हैं, वे स्थानीय स्तर पर आकार नहीं ले पाती हैं. प्रशिक्षित शहरी योजनाकारों की कमी की वजह से देश में शहरीकरण का काम सुस्त और दिशाविहीन है. देश के शहरों में हर आय स्तर के लोगों के लिए वहन करने योग्य घर बनाने का कार्य बिना किसी योजना कर दिया गया. लगभग 2,00,000 घर प्रतिवर्ष बनाए गए, जबकि ज़रूरत दो मिलियन घरों की है. यही वजह है कि मौजूदा समय में देश के शहरों में 17 मिलियन परिवार झुग्गियों में रहते हैं और आने वाले बीस वर्षों में यह संख्या दोगुनी होने का अनुमान है. भारत को हर वर्ष शिकागो जितना बड़ा एक शहर बसाने की ज़रूरत अगले बीस साल तक रहेगी, जिससे पर्याप्त व्यवसायिक और रिहायशी जगह बन सके.

एक अनुमान के मुताबिक़, वर्ष 2030 में 91 मिलियन मध्यमवर्गीय परिवार जनसंख्या में शामिल हो जाएंगे, जो 22 मिलियन परिवारों के मौजूदा आंकड़े से 300 प्रतिशत ज़्यादा है. इस शहरी वर्ग की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लगभग 2.5 बिलियन वर्ग मीटर रोड, 7,400 किलोमीटर सब-वे और ट्रांसपोर्टेशन का निर्माण करने की आवश्यकता है. 700-900 मिलियन स्क्वायर मीटर व्यवसायिक एवं रिहायशी जगह की ज़रूरत है. लेकिन क्या हम इसके लिए तैयार हैं? शायद नहीं, क्योंकि भारत विश्व में सबसे तेज़ी से शहरीकृत होने वाले देशों में भले शुमार हो, लेकिन हमारे पास शहरीकरण की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कोई कार्ययोजना नहीं है. शहरों के विकास के लिए न तो वहां रहने वाले लोगों की ज़रूरतों का ध्यान रखा जाता है, न ही वातावरण पर पड़ने वाले असर के बारे में कोई योजना बनाई जाती है. यही कारण है कि भारत के शहर तेज़ी से झुग्गियों में तब्दील होते जा रहे हैं. लेकिन अब शायद इस ओर आंखें मूंद कर नहीं रहा जा सकता. केंद्र हो या राज्य सरकार अथवा स्थानीय संस्थाएं, उन्हें इस ओर ध्यान देना ही होगा, अन्यथा शहरों की उत्पादक आबादी, जो देश की आर्थिक प्रगति की सबसे बड़ी वाहक है, के लिए समस्याएं लगातार बढ़ती जाएंगी और यह देश की सेहत के लिए अच्छा नहीं है.

ritika@chauthiduniya.com

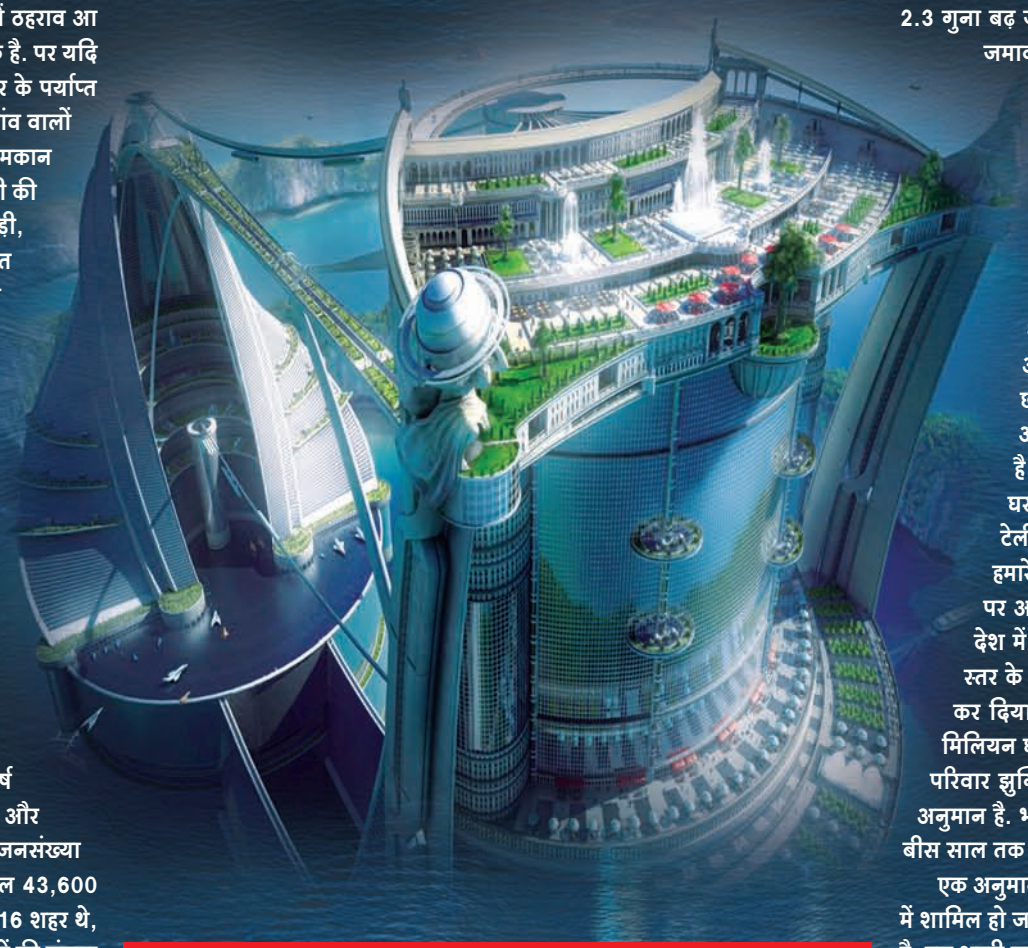

1991 की जनसंख्या रिपोर्ट के मुताबिक़, 25.7 प्रतिशत जनसंख्या शहरी थी और यह अनुमान लगाया गया था कि वर्ष 2001 तक यह 28.4 प्रतिशत हो जाएगी, लेकिन 1991 के बाद देश की आर्थिक स्थिति को दुरुस्त करने के लिए सरकार द्वारा उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को प्रोत्साहित किए जाने से शहरीकरण की प्रक्रिया में रफ्तार आई और शहरों में बेतरतीब तरीके से भीड़ बढ़ने लगी. माना जाता है कि शहरी जनसंख्या में प्रतिवर्ष होने वाला 45 प्रतिशत का इज़ाफ़ा लोगों के प्रवासन की वजह से है.

कॉमनवेल्थ गेम्स के चलते दिल्ली में सामाजिक कल्याण विभाग ने भिखारियों की संख्या कम करने के लिए मुहिम छेड़ी. ग़ैर सरकारी संगठनों को यह ज़िम्मा दिया गया.

लालबत्ती पर लुटता बचपन

कुमार सुशांत

राजू की उम्र महज़ 5 साल है. नन्हें–नन्हें हाथ–पैर, मासूम चेहरा, नन्हीं आंखें और शरीर पर मैले–कुचैले कपड़े पहने राजू दिल्ली के बाराखंभा चौराहे पर बैठा सिग्नल लाल होने का इंतज़ार कर रहा है. अचानक सिग्नल लाल होता है, गाड़ियां रुकती हैं. झट से वह उठकर गाड़ियों के बीच में जाकर तमाशा दिखाने लगता है. लोहे की रॉड्स के बीच से अपने शरीर को मुश्किल से एक से दूसरे पार निकालता है. उसका चेहरा शरीर पर आए ज़ख्म के दर्द को साफ बयां करता है, लेकिन वह कमर हिलाते हुए जल्दी से गाड़ी में बैठे बाबुओं–साहबों से पैसे मांगना शुरू करता है. उसे महज़ दो–चार रुपये मिलते हैं. इतने में सिग्नल हरा हो जाता है और वह निराश होकर बचते हुए भागता है और बगल में बैठकर अगली लालबत्ती का इंतज़ार करने लगता है. बाराखंभा रेडलाइट पर अकेले राजू ही नहीं, बल्कि उसकी मां, बुआ और छोटे–छोटे भाई–बहन यानी पूरा परिवार इसी तरह रोटी के जुगाड़ में लगा रहता है. आज हज़ारों परिवार ऐसे हैं, जिनकी शाम की रोटी इन लालबत्तियों पर तमाशे करके ही चलती है.

राजू से हमने घंटों बातचीत की. पूरी तरह घुल–मिल जाने पर राजू से उसकी पढ़ाई के बारे में पूछा तो वह मासूमियत भरी नज़रों से तुतलाते हुए बताता है, मां से अक्सर कहता हूं कि मुझे भी पढ़ना है, कॉपी–कलम दो. इस पर वह डांट देती है. कहती है कि खाकर सो जाओ, सुबह रेडलाइट पर जाना है. इतने में राजू पूछ बैठता है, भैया, मां मुझे रोज़ क्यूं भेज देती है, क्यूं नहीं पढ़ने देती? राजू के इस सवाल का हमारे पास कोई जवाब नहीं था. राजू का बड़ा भाई अशोक कहता है कि हमारे माता–पिता भी तमाशे दिखाते थे. उसके बाद वह और अब उसके छोटे भाई–बहन करतब दिखाते हैं, जिन्हें प्रशिक्षण वह ख़ुद देता है. बात करते–करते उसकी आंखें नम हो जाती हैं. वह कहता है कि उसे अबोध छोटे भाई–बहनों को देखकर दु:ख भी होता है, लेकिन क्या करे? अगर ख़ुद तमाशा दिखाएगा तो लोग पैसा नहीं देंगे. छोटे–छोटे बच्चों के तमाशों को देखकर ही लोग हमदर्दीवश पैसे देते हैं, जिससे घर का चूल्हा जलता है. अशोक बताता है कि लालबत्तियों पर पुलिस ख़ूब परेशान करती है. कभी तमाशा दिखाते हुए पकड़ कर पीट देती है तो कभी हवालात में रात भर बंद कर देती है. नतीजतन तमाशा दिखाने के लिए वह स्थान बदलता रहता है. सरकार से मदद मिलने के नाम पर अशोक कहता है कि वह कई बार दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, किरण वालिया और मंगतराम सिंघल जैसे कई मंत्रियों के दफ्तर अपनी फ़रियाद लेकर गया, लेकिन कभी उसे वहां से भगा दिया गया तो कभी उसकी बात वहां तक पहुंच ही नहीं पाई, पर बाहर सरकारी बाबुओं ने आश्वासन ज़रूर दिए.

लेनसेट के 2008 में 20 देशों पर किए गए एक अध्ययन के मुताबिक़, भारत में तमाशबीन बच्चों की संख्या क़रीब 61 मिलियन से अधिक है. इनमें आधे से अधिक (क़रीब 51 फ़ीसदी) बच्चों की उम्र 5 साल से कम है. ऐसा नहीं कि करतब दिखाने वाले सभी बच्चों का यह पेशा वंशानुगत रहा है. चूंकि भीख मांगने पर उन्हें पुलिस द्वारा परेशान किया जाता है, इसीलिए ये बच्चे छोटे–मोटे करतब दिखाकर पैसा मांगते हैं. एक रिपोर्ट के मुताबिक़, केवल राजधानी दिल्ली में 60 हज़ार से ज़्यादा बाल भिखारी हैं. कॉमनवेल्थ गेम्स के चलते दिल्ली में सामाजिक कल्याण विभाग ने भिखारियों की संख्या कम करने के लिए मुहिम छेड़ी. ग़ैर सरकारी संगठनों को यह जिम्मा दिया गया. विभाग ने 1098 नंबर लांच किया, जिस पर कॉल करने पर ग़ैर सरकारी संगठन के अधिकारी आकर उन भिखारियों को हिरासत में ले लेते थे. पापी पेट का सवाल था. ट्रेंड बदला. इन बच्चों को अब आप लालबत्तियों पर भीख मांगते नहीं, बल्कि कार का शीशा साफ करते या फूल–किताबें बेचते पाएंगे. दलाल इन बच्चों का ख़ूब दोहन भी करते हैं. आश्रम रेडलाइट पर किताबें बेचने वाला 10 वर्षीय दीपक बताता है कि वह दिन भर में 500 से 600 रुपये तक की किताबें बेच लेता है. इसके बदले उसका मालिक प्रतिदिन 40 रुपये देता है. दीपक कहता है कि उसके मालिक ने आश्रम में ही एक कमरा लिया है, जहां उसके सत्रह–अट्ठारह दोस्त रहते हैं और वे भी दूसरी लालबत्तियों पर किताबें बेचते हैं.

सभी फोटो– *प्रभात पाण्डेय*

आश्चर्य है कि जिन मासूम बच्चों के हाथों में किताब और कलम होनी चाहिए, उन हाथों में आज दूसरों का मनोरंजन करने की ज़िम्मेदारी है. ग्रामीण इलाक़ों में तो हालत यह है कि लाखों बच्चों को किताब–पेंसिल तो दूर, पेट भर खाना भी नसीब नहीं होता. उनके अभिभावक ग़रीबी की वजह से ज़्यादा दिनों तक अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते. बच्चों के दर–बदर होते और लुटते बचपन के लिए उनके मां–बाप पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं, जो उन्हें दुनिया में लाकर उनके नसीब पर सड़कों पर छोड़ देते हैं. ज़िम्मेदार सरकार भी है, जो देश से ग़रीबी मिटाने समेत समस्यारहित राष्ट्र के निर्माण के वादे करती है. इन बच्चों को तमाशा करने या भीख मांगने से तो रोका जा सकता है, लेकिन इससे इनके पेट की भूख ख़त्म नहीं हो सकती. पेट की आग शांत करने के लिए ये कभी भीख मांगेंगे, कभी किताब बेचेंगे, कभी तमाशा दिखाएंगे तो कभी ग़लत राह का अनुसरण कर लेंगे. देश में इसी साल राइट टू एजूकेशन एक्ट लागू हो चुका है. प्रधानमंत्री समेत तमाम नेता देश की गली–गली में शिक्षा पहुंचाने का दावा करते हैं. पूरे देश की बात छोड़िए, केवल राजधानी दिल्ली की बाराखंभा रेडलाइट का उदाहरण ले लीजिए, जहां दिन भर सरेआम मासूम बच्चे आपको तमाशा करते नज़र आ जाएंगे.

बाराखंभा के आसपास का कनॉट प्लेस दिल्ली का सबसे बड़ा पॉश इलाक़ा है. दिन भर न जाने कितने नेताओं की गाड़ियां इस इलाक़े से होकर गुज़रती हैं. मीडिया–कैमरे के सामने ग़रीबी मिटाने, शिक्षा देने और बेरोज़गारी दूर करने जैसे तमाम वादे करने वाले इन नेताओं को जब फोन और लैपटाप से फुर्सत मिलती है तो वे मासूम चेहरों की तरफ़ देख 1–2 रुपया उछाल कर आगे बढ़ जाते हैं. सवाल उठता है कि क्या संविधान ने इन बच्चों को जीने का यही अधिकार दिया है? क्या इन्हें शिक्षा पाने का अधिकार नहीं है? अगर देश के नेताओं को सरेआम लालबत्तियों पर तमाशा करते बच्चे नज़र नहीं आते हैं तो फिर गली–गली में शिक्षा के प्रसार–प्रचार की क्या गारंटी है?

kumarsushant@chauthiduniya.com

आंकड़ों में बाल श्रमिक

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने हाल में स्वीकारा है कि भारत में 37 फ़ीसदी लोग ग़रीबी रेखा से नीचे रहते हैं. अभिभावकों की इसी ग़रीबी की वजह से बाल मज़दूरी का जन्म होता है. बाल मजदूरी आज भी पूरे देश के लिए चिंता का विषय है. वैश्विक तौर पर भारत में सबसे ज़्यादा बाल मज़दूर हैं. सरकार ने 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए काम करना ग़ैरक़ानूनी बताया है, लेकिन हक़ीक़त में बहुत सारे कारख़ाने, फैक्ट्रियां, दुकाने, गैरेज, कृषि या अन्य व्यापार हैं, जहां खुलेआम बच्चों से मज़दूरी कराई जा रही है. 21 नवंबर, 2005 को एक एनजीओ कार्यकर्ता ने श्रम विभाग के सहयोग से दिल्ली के सीलमपुर स्थित 100 से अधिक अवैध कारख़ानों में छापेमारी कर 480 से अधिक बाल श्रमिकों को मुक्त कराया. उसके बाद बाल श्रमिकों से संबंधित ग़ैर सरकारी संगठनों ने दिल्ली सरकार के साथ संगठित होकर इस मामले पर कार्रवाई की योजना बनाई. 1997 में कांचीपुरम में किए गए एक शोध से खुलासा हुआ कि ज़िले में केवल सिल्क बुनने के व्यवसाय से क़रीब 60,000 से ज़्यादा बच्चे जुड़े रहे. जबकि 2007 में रूरल इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एजूकेशन की सार्थक पहल के बाद इनकी संख्या घटकर क़रीब 4,000 से नीचे पहुंच गई. भारत में स्ट्रीट चिल्ड्रेंस की संख्या भी सबसे ज़्यादा है. एक आंकड़े के मुताबिक़, देश में क़रीब 18 मिलियन से अधिक स्ट्रीट चिल्ड्रेन हैं. वैसे तो देश में बच्चों की भुखमरी, ग़रीबी की विकट स्थिति पर अनगिनत अध्ययन और रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं, लेकिन नेशनल फेमिली हेल्थ सर्वे द्वारा 2005–06 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 8 सालों में बच्चों के पोषण संबंधी समस्या में कोई सुधार नहीं हो पाया है. सर्वे के मुताबिक़, भारत में 3 साल से कम उम्र के क़रीब 46 फ़ीसदी बच्चे सामान्य से कम वज़न के हैं. आंकड़े यह भी बताते हैं कि मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में बच्चों की आधी से ज़्यादा आबादी कुपोषण की शिकार है. वैसे बाल मज़दूरी की समस्या केवल हमारे देश की ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व की है. यूनीसेफ के मुताबिक़, पूरे विश्व में 5 से 14 साल के क़रीब 158 मिलियन बच्चे बालश्रम के शिकार हैं. इसमें घरेलू कामकाज से संबद्ध बच्चे शामिल नहीं हैं. सीएसीएल की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 70 से 80 लाख बाल श्रमिक हैं. एक आंकड़े पर ग़ौर करें तो एशिया में बच्चों की आबादी का 22 फ़ीसदी, अफ्रीका में 32 फ़ीसदी, लैटिन अमेरिका में 17 फ़ीसदी एवं यूएस, कनाडा, यूरोप और दूसरे धनी देशों में एक-एक फ़ीसदी हिस्सा मज़दूरी करने के लिए मजबूर है.

ग्रामीण पर्यटन राजस्थान की नई पहचान बनता जा रहा है. शेखावाटी इस मामले में भी उदाहरण बनता जा रहा है.

शेखावाटी का चेहरा बदल रहा है

वीरों और धनकुबेरों की भूमि शेखावाटी बदल रही है. शेखावाटी के झुंझुनू, चुरु और सीकर ज़िलों में बदलाव की बयार महसूस की जा सकती है. अर्द्ध रेतीली ज़मीन पर विकास की बहती धारा साफ देखी जा सकती है. ऐसा विकास, जो किसी सरकारी दान का मोहताज नहीं है. वह विकास, जो नीति निर्माताओं के लिए एक से बढ़कर एक उदाहरण पेश कर रहा है. ये उदाहरण देश के उन नौकरशाहों के मुंह पर तमाचा भी हैं, जो बिना सोचे-समझे बेकार की नीतियां बनाने की सलाह देने में माहिर हैं.

झुंझुनू ज़िले की ही एक तहसील है नवलगढ़. नवलगढ़ का एमआर मोरारका फाउंडेशन इस क्षेत्र के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए सतत प्रयास कर रहा है. जैविक खेती में नित नए प्रयोग हो रहे हैं. नई तकनीकें, जो पूर्णत: प्राकृतिक होती हैं, ईजाद की जा रही हैं. फाउंडेशन की ओर से किसानों, महिलाओं, लड़कियों एवं विकलांगों की बेहतरी के लिए अलग-अलग कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं. फाउंडेशन के प्रयासों का ही नतीजा है कि आज यहां के किसानों को क़र्ज़ लेकर किसी मल्टीनेशनल कंपनी से रासायनिक खाद ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. वजह, किसान ख़ुद जैविक खाद बना रहे हैं. केचुआ (वर्मी) और गोबर से बनी खाद. गोमूत्र, नीम, हल्दी एवं लहसुन से हर्बल स्प्रे बना लेते हैं.

जैविक खेती से उपजा अन्न आज उनकी आर्थिक स्थिति को लगातार मज़बूत बना रहा है. मोरारका फाउंडेशन इन किसानों को न सिर्फ़ जैविक खेती का प्रशिक्षण दे रहा है, बल्कि किसानों द्वारा पैदा किए गए जैविक अनाज के लिए बाज़ार भी उपलब्ध करा रहा है. नतीजतन, किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य भी मिल रहा है.

अब यहां की ग़रीब महिलाओं को किसी बैंक या महाजन से क़र्ज़ नहीं लेना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने ख़ुद ही स्वयं सहायता समूह बना लिया है. दस से बारह तक के समूह में महिलाएं काम करती हैं. छोटे-मोटे काम, जैसे बंधेज बनाना या फल-सब्जी बेचना. ज़रूरत पड़ने पर समूह से ही क़र्ज़ मिल जाता है. ग़रीब महिलाएं जो कभी खेतों से लकड़ियां चुनकर अपना चूल्हा जलाती थीं, आज रसोई गैस पर खाना बनाती हैं. 4-5 महिलाएं एक साथ एक केंद्र पर पहुंच कर सांझा गैस रसोई योजना का लाभ उठा रही हैं. ईंधन का मासिक ख़र्च जो पहले 1200 से लेकर 1500 रुपये तक था (लकड़ी और कंडों की कीमत जोड़कर), अब सिर्फ़ तीन या साढ़े तीन सौ रुपये आता है. यह योजना ग्रामीण महिलाओं के लिए रोज़गार के अवसर के रूप में भी उभरी है. राजपूत घरों की लड़कियां जो घर से बाहर निकल कर काम नहीं कर सकतीं, अब घर में ही डाटा एंट्री ऑपरेटर बनकर किसानों की मदद कर रही हैं. इन लड़कियों को मोरारका फाउंडेशन ने कंप्यूटर ट्रेनिंग देकर घर से ही काम करने में सक्षम बना दिया है. आज ये लड़कियां अबला नहीं, वीरबालाएं बन चुकी हैं.

झुंझुनू ज़िले की ही एक तहसील है नवलगढ़. नवलगढ़ का एमआर मोरारका फाउंडेशन इस क्षेत्र के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए सतत प्रयास कर रहा है. जैविक खेती में नित नए प्रयोग हो रहे हैं.

गंगा-यमुना को साफ करने के नाम पर सरकार अरबों रुपये बहा चुकी है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला. हालत यह है कि कुछ क्षेत्रों में आज गंगा का पानी पीने तो क्या, सिंचाई के लायक भी नहीं रहा. दूसरी ओर फाउंडेशन ने दूषित जल को साफ बनाकर फिर से सिंचाई लायक बनाने का एक कारगर तरीक़ा निकाला है. यह तकनीक अन्य तकनीकों के मुक़ाबले न सिर्फ़ सस्ती है, बल्कि प्राकृतिक है और इकोफ्रेंडली भी. अन्य तकनीक (खासकर विदेशी) में इस तरह के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने में जहां 50 से 60 लाख रुपये का ख़र्च आता है, वहीं प्राकृतिक तरीक़े से बनने वाला यह प्लांट महज़ 5-6 लाख रुपये में तैयार हो जाता है और इस प्लांट में बिजली की खपत भी न के बराबर है. फाउंडेशन ने विकलांगों को रोज़गार देने के उद्देश्य से उनके बीच सौर ऊर्जा चालित लालटेन का वितरण किया है. कालू भाट एवं राधेश्याम जैसे विकलांग और ग़रीब युवकों के लिए ये सोलर लालटेन रोज़गार का ज़रिया बन गई हैं. वे इन लालटेनों को दिन में चार्ज कर लेते हैं और गांव वाले अपनी ज़रूरत के हिसाब से इन्हें किराए पर ले जाते हैं. किराया भी मामूली है. छात्रों के लिए 5 रुपये प्रति रात और अन्य के लिए 10 रुपये. शादी-समारोह के अवसर पर भी लोग सौर लालटेन किराए पर ले जाते हैं. इस तरह इन विकलांग युवकों की ज़िंदगी भी रफ्तार पकड़ने लगी है.

ग्रामीण पर्यटन राजस्थान की नई पहचान बनता जा रहा है. शेखावाटी इस मामले में भी उदाहरण बनता जा रहा है. फाउंडेशन ने पूरे राजस्थान में लगभग 500 ग्रामीण परिवारों को ग्रामीण पर्यटन के लिए प्रशिक्षित किया है. नवलगढ़ का सिगनौर ऐसा ही एक गांव है. गांव के तीन किसान परिवार इस योजना के तहत चुने गए हैं, जो अपने घर में आने वाले मेहमानों का स्वागत करते हैं, उनके खाने-पीने से लेकर घूमने तक का इंतज़ाम करते हैं. बदले में इन परिवारों को उचित पैसा भी मिलता है. इस तरह ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देकर मोरारका फाउंडेशन ग्रामीण परिवारों को रोज़गार के अवसर भी उपलब्ध करा रहा है. फाउंडेशन के इन सारे प्रयासों को देखने के बाद यह निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि शेखावाटी विकास की नई इबारत लिखने के साथ-साथ विकास की नई परिभाषा भी लिख रहा है. और यह भी तय है कि आने वाले समय में पूरे देश की तकदीर बदलने के लिए हमारे नीति निर्माताओं को विकास की इस नई परिभाषा को ही पढ़ना होगा, अपनाना होगा.

शशि शेखर
shashishekhar@chauthiduniya.com

सभी फोटो- *प्रभात पाण्डेय*

कोर्टिसोल स्टेरायड हार्मोन है. कोर्टिसोल की जांच पेशाब और लार से की जाती है, लेकिन यह जांच केवल दबाव के स्तर के बारे में बताती है.

सूचना का अधिकार
जानने का अधिकार जीने का अधिकार
चौथी दुनिया की पहल

इंदिरा आवास योजना ग़रीबों का हक़ है

यह सरकारी सच है. कई दिग्गज नेता यह मान चुके हैं कि केंद्र से चला एक रुपया गांवों तक पहुंचते–पहुंचते 25 पैसा हो जाता है. कुछ नेताओं ने तो यह भी कहा कि यह रक़म दस पैसे में बदल जाती है. ज़ाहिर है, ऐसी स्थिति में यह कल्पना कर पाना मुश्किल नहीं है कि ग़रीबों के लिए बनाई गई सरकारी योजनाओं का क्या हश्र होता होगा? ग़रीबों के लिए बनी ऐसी ही एक योजना है इंदिरा आवास योजना. बीपीएल रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए यह योजना बनाई गई थी, जिसके तहत एक ख़ास रक़म घर बनाने के लिए दी जाती है. इस योजना के तहत सिर्फ़ उन्हीं लोगों को सरकारी सहायता मिलती है, जिनका चयन पंचायत (सरपंच) करती है और सारी गड़बड़ी भी यहीं से शुरू हो जाती है. मुखिया–सरपंच लाभांवितों के चयन में खुलकर मनमानी करते हैं. चूंकि ग्रामसभा की बैठक नियमित होती नहीं, सो इनकी मनमानी का कारगर विरोध भी नहीं हो पाता. ऐसे में वे लोग जिन्हें वास्तव में इस योजना की ज़रूरत होती है, कई बार वंचित रह जाते हैं. अब सवाल यह है कि क्या मुखिया–सरपंच की मनमानी यूं ही चुपचाप सह लेनी चाहिए? बिल्कुल नहीं. आप सभी के पास सूचना का अधिकार क़ानून नामक एक ऐसा हथियार है, जिसकी मदद से आप अपना हक़ ले सकते हैं. पंचायत से लाभांवितों की सूची भी मांग सकते हैं.

इस अंक में इंदिरा आवास योजना से संबंधित एक आवेदन प्रकाशित किया जा रहा है. इस आवेदन के ज़रिए आप योजना से संबंधित हर पहलू का विवरण मांग सकते हैं. जैसे, क्या आप इस योजना के लिए हक़दार हैं या नहीं? अगर नहीं हैं तो क्यों नहीं हैं या जिन लोगों को इस योजना का लाभ मिला है, क्या वे सचमुच इस योजना के हक़दार थे? लाभार्थियों का चयन कैसे किया गया? ग्रामसभा की किस बैठक में किया गया? क्या ग्रामसभा ने लाभार्थियों के चयन को अपनी स्वीकृति दी थी? हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी इस आवेदन का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे और दूसरे लोगों को भी इसके इस्तेमाल के लिए प्रेरित करेंगे.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

यदि आपने सूचना क़ानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार क़ानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं या हमें पत्र लिख सकते हैं. हमारा पता है :

चौथी दुनिया

एफ–2, सेक्टर–11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश, पिन –201301
ई–मेल : rti@chauthiduniya.com

आवेदन का प्रारूप

(इंदिरा आवास योजना का विवरण)

सेवा में, **दिनांक.....**

लोक सूचना अधिकारी,
(विभाग का नाम)
(विभाग का पता)

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन

महोदय,

मेरा नाम------ है. मैं -----पंचायत के-----गांव का निवासी हूं. मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है. इसके बावजूद मुझे इंदिरा आवास योजना के तहत घर आवंटित नहीं किया गया है. इस संबंध में मुझे सूचना का अधिकार क़ानून के तहत निम्न सूचनाएं उपलब्ध कराएं:

1. सरकार के रिकॉर्ड के अनुसार क्या मैं इंदिरा आवास योजना का हक़दार हूं? यदि नहीं तो क्यों?
2. यदि हां, तो अब तक मुझे इंदिरा आवास योजना का आवंटन क्यों नहीं किया गया है? मुझे इंदिरा आवास योजना का लाभ मिले, यह सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी किन अधिकारियों–कर्मचारियों की है? उनका नाम और पदनाम बताएं.
3. मेरी ग्राम पंचायत में पिछले पांच सालों में कुल कितने लोगों को इस योजना के तहत घर आवंटित किए गए हैं? उनकी सूची निम्नलिखित विवरण के साथ उपलब्ध कराएं:
   (क) लाभार्थी का नाम.
   (ख) आवंटन की तारीख़.
   (ग) किस आधार पर आवंटन किया गया.
   (घ) जिस ग्रामसभा में लाभार्थी का चयन किया गया, उस ग्रामसभा की उपस्थिति रजिस्टर की प्रमाणित प्रति दें.
4. क्या उपरोक्त सभी आवंटन बीपीएल सूची के आधार पर किए गए हैं? उपरोक्त पंचायत की बीपीएल सूची की प्रमाणित प्रति दें.
5. इंदिरा आवास योजना के आवंटन से संबंधित सभी शासनादेशों/निर्देशों/नियमों की प्रमाणित प्रतियां दें.

मैं आवेदन शुल्क के रूप में दस रुपये अलग से जमा कर रहा/रही हूं.

भवदीय

नाम.....
पता.....

ज़रा हट के

बबली बन गई बंटी

इस युग में जो न हो, वही कम है. केरल के कोल्लम में एक ऐसी अजीबोग़रीब घटना प्रकाश में आई है, जिसे पढ़कर आप भी चौंक जाएंगे. एक महिला पुरुष बनकर कंपनी को करोड़ों रुपये का चूना लगाती रही और अधिकारियों को इसकी भनक तक नहीं लगी. बाद में इस 29 वर्षीय महिला को गिरफ़्तार कर लिया गया. आरोप है कि इसने कई महीनों तक पुरुष बनकर नौकरी की और कंपनी को धोख़ा दिया. रानी नामक यह महिला श्रीकांत के नाम से एक मार्बल विक्रेता के यहां कलेक्शन एजेंट के तौर पर काम करती रही. वह इतनी सफ़ाई से काम करती थी कि उस पर किसी को शक़ भी नहीं हुआ. उसकी असलियत का पता तब चला, जब पुलिस ने उसे पैसों के गबन के आरोप में गिरफ़्तार किया.

ग़रीब परिवार से ताल्लुक रखने वाली रानी ने अप्रैल में नौकरी शुरू की थी. उस वक़्त वह पैंट–कमीज़ पहन कर यानी पुरुष बनकर नौकरी करने आई. उसने अपने बालों को भी सलीके से ऐसा बना लिया कि उसे पहचानना मुश्किल था. इतना ही नहीं, रानी ने नौकरी पाने के लिए फ़र्ज़ी पहचानपत्र भी दिया. पहचानपत्र में उसका नाम श्रीकांत था. उसने अपनी पढ़ाई से जुड़े कई सर्टिफिकेट भी दिखाए, जिनमें उसका नाम श्रीकांत और लिंग पुरुष बताया गया था. रानी का घपला तब पकड़ में आया, जब ओणम की छुट्टियों के बाद वह काम पर नहीं पहुंची. कंपनी ने जब उसके बारे में पूछताछ की तो पता चला कि श्रीकांत ने कंपनी के नाम पर काफ़ी बड़ी राशि का कलेक्शन कर लिया था, लेकिन उसे जमा नहीं कराया. तब उसके ख़िलाफ़ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई. पुलिस ने उसका पता लगाया और उसे उसके घर से गिरफ़्तार कर लिया. उसके बाद रानी को अस्पताल ले जाया गया, जहां लिंग जांच में साबित हो गया कि वह पुरुष नहीं, महिला है.

बाल खोलेगा राज़

विशेषज्ञ अब बाल से जीवन के राज़ खोलेंगे. बाल देखकर वे बता देंगे कि आप कितने दबाव में हैं. इतना ही नहीं, हार्ट अटैक संबंधी बीमारियों के बारे में भी बाल बहुत कुछ बता देंगे. इसका ख़ुलासा इजरायल में हुए एक शोध में किया गया है. शोधकर्ताओं ने बाल में स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल के स्तर को मापने के दौरान पाया कि इससे यह भी पूर्वानुमान लगाया जा सकता है कि आपको हार्ट अटैक पड़ने वाला है या नहीं. कोर्टिसोल स्टेरायड हार्मोन है. कोर्टिसोल की जांच पेशाब और लार से की जाती है, लेकिन यह जांच केवल दबाव के स्तर के बारे में बताती है. वह भी तब, जब जांच का नमूना लिया गया हो.

इजरायल के वेस्टर्न ओनटैरियो यूनिवर्सिटी के डॉ. गिडेन कोरेन एवं डॉ. वैन यूम ने बाल में मौजूद कोर्टिसोल को मापने के बारे में सोचा. कोरेन ने कहा कि हम जानते हैं कि मानसिक दबाव किसी के लिए ठीक नहीं है, लेकिन इसे मापना आसान नहीं है. उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि बाल औसतन एक माह में एक सेंटीमीटर तक बढ़ता है. अगर हम नमूने के लिए छह सेंटीमीटर लंबे बाल लेते हैं तो इससे हम छह महीने के लिए दबाव के स्तर का निर्धारण कर सकते हैं. टीम ने इजरायल के मेयर मेडिकल सेंटर में 54 पुरुषों पर शोध किया. सभी को हार्ट अटैक का दौरा पड़ चुका था. उनका और कंट्रोल ग्रुप का हेयर सैंपल लिया गया. उन दोनों से लिए गए सैंपल से पाया गया कि जितने भी हार्ट अटैक के मरीज़ थे, उनमें कोर्टिसोल की मात्रा अधिक थी. दबाव आज आधुनिक जीवन का हिस्सा बन चुका है. यह जीवन के सभी हिस्सों और स्वास्थ्य को प्रभावित करता है. इस तरह की उलझन को सुलझाने के लिए शोध और अभ्यास की ज़रूरत है, क्योंकि दबाव जीवनशैली को प्रभावित करता है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

राशिफल

दिल्ली, 20 सितंबर–26 सितंबर 2010

मेष (21 मार्च से 20 अप्रैल)
स्वास्थ्य के लिहाज़ से लंबे समय से चल रही बीमारियों से मुक्ति मिलेगी. नौकरीपेशा वर्ग के लिए इस सप्ताह कुछ मानसिक परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं. अध्यापन, लेखन, बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े लोगों को करियर में नए अवसर मिल सकते हैं.

वृष (21 अप्रैल से 20 मई)
अचानक कहीं यात्रा करनी पड़ सकती है. साथ ही अपने सामान के प्रति सचेत रहें. दमा, अस्थमा और दिल के मरीजों के लिए परेशानियां हो सकती हैं. छात्रों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के योग हैं.

मिथुन (21 मई से 20 जून)
निजी संबंधों में विश्वास की कमी तनाव का कारण बन सकती है. परिजनों से भी किसी बात को लेकर वैचारिक मतभेद हो सकते हैं. पुराने दुश्मनों से बचकर रहें, वरना आर्थिक हानि हो सकती है. धन की समस्या बनी रहेगी.

कर्क (21 जून से 20 जुलाई)
भाग्य के सहयोग से नए मौक़े आपके हाथ आएंगे और आप उसे भुनाने में कामयाब हो सकते हैं. जीवनसाथी का स्वास्थ्य चिंता का कारण बन सकता है, मानसिक परेशानियां भी दु:ख दे सकती हैं.

सिंह (21 जुलाई से 20 अगस्त)
खानपान का स्तर ऊंचा रहेगा और सामाजिक समारोहों में भाग लेने का मौका मिलेगा. इस हफ्ते आमदनी अठन्नी, ख़र्चा रुपैया वाली स्थिति रहेगी. मित्र–परिजनों को रकम उधार देनी पड़ सकती है. इस हफ्ते खुशनुमा एहसास लेकर कोई ज़िंदगी में आएगा.

कन्या (21 अगस्त से 20 सितंबर)
मानसिक एवं शारीरिक चिंताएं परेशान कर सकती हैं. अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें और खाने–पीने का उचित ध्यान रखें. लंबी दूरी की यात्राओं से परहेज़ करें तो बेहतर है. वाहन चलाने में सावधानी अपेक्षित है, अन्यथा दुर्घटना हो सकती है.

तुला (21 सितंबर से 20 अक्टूबर)
अपने शौक को करियर बनाने की इच्छा रखने वाले युवाओं को अभी और प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है. इस सप्ताह आप कोई मकान या नई गाड़ी आदि की खरीददारी भी कर सकते हैं. पिछले कुछ समय से चली आ रही उलझनें ख़त्म होंगी.

वृश्चिक (21 अक्टूबर से 20 नवंबर)
पेट और दिल की बीमारियां थोड़ा परेशान कर सकती हैं, लेकिन इसके बाद स्थितियों में सुधार होगा. नए कार्यों में भी प्रगति होगी, लेकिन जल्दबाज़ी में लिया गया कोई निर्णय भविष्य में परेशानी का कारण बन सकता है.

धनु (21 नवंबर से 20 दिसंबर)
यह सप्ताह परेशानियों से राहत दिलाने वाला हो सकता है. लंबे समय से चली आ रही स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से निजात मिलेगी. अपने खाने–पीने का उचित खयाल रखें. कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों का सहयोग हासिल होगा और वरिष्ठों की नज़र में आपका कद बढ़ सकता है.

मकर (21 दिसंबर से 20 जनवरी)
यह सप्ताह परेशानियों से राहत दिलाने वाला हो सकता है. लंबे समय से चली आ रही स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से निजात मिलेगी. अपने खाने–पीने का उचित खयाल रखें. कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों का सहयोग हासिल होगा.

कुंभ (21 जनवरी से 20 फरवरी)
व्यापारियों के लिए यह समय आगे की योजना बनाने हेतु उचित है. इनकम टैक्स को ध्यान में रखकर योजना बनाने का लाभ दिखाई देगा. खानपान और वाहन चलाते समय सावधानी अपेक्षित है. पुराने संबंधों की वजह से नए संबंधों में तनाव आ सकता है.

मीन (21 फरवरी से 20 मार्च)
व्यापारियों के लिए यह समय आगे की योजना बनाने हेतु उचित है. इनकम टैक्स को ध्यान में रखकर योजना बनाने का लाभ दिखाई देगा. खानपान और वाहन चलाते समय सावधानी अपेक्षित है. पुराने संबंधों की वजह से नए संबंधों में तनाव आ सकता है.

पंडित सुदर्शन
feedback@chauthiduniya.com

हमारी राष्ट्रीय क्रिकेट टीम पर मैच फिक्सिंग के आरोप सालों से लगते रहे हैं. सच्चाई यह है कि मैच फिक्सिंग के आरोप झेल रहे हमारे खिलाड़ी अकेले नहीं हैं.

मैच फिक्सिंग स्कैंडल

पाकिस्तानी समाज का आईना

न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड की साख़ पर सवालिया निशान लगाते हुए यह बताया गया कि इस टेबलॉयड ने कई बार ऐसी ख़बरें छापी हैं, जिसे प्रमाणित करने के लिए इसके पास कोई सबूत नहीं होते. अदालती मुक़दमों में इसे कई बार मुंह की खानी पड़ी है. लेकिन वे यह बताना भूल गए कि दस में से नौ मौक़ों पर यह टेबलॉयड अपना लक्ष्य साधने में कामयाब रहा है.

एक नया दिन और एक नया स्कैंडल. इंग्लैंड के टेबलॉयड न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड द्वारा किए गए स्टिंग ऑपरेशन को देशी मीडिया में जितनी तवज्जो मिली, उसे देखकर यही लगा कि पाकिस्तान में सब कुछ ठीकठाक चल रहा है. मानो बाढ़ जैसी कोई समस्या है ही नहीं, लाखों लोगों के विस्थापित होने का वाकया तो जैसे कभी हुआ ही नहीं. मानो पाकिस्तान में यह भ्रष्टाचार की पहली घटना हो. अख़बार की ख़बरों में, संपादकों के नाम पत्र में और टेलीविज़न पर चलने वाले टॉक शोज में चल रही चर्चाओं को देखकर ऐसा लगा कि जैसे शरीफ लोगों के देश पाकिस्तान में इससे पहले कभी किसी पर कोई आरोप लगा ही नहीं, किसी ने अपनी हैसियत का दुरुपयोग कर अवैध कमाई करके अपनी जेब नहीं भरी. लेकिन जैसे-जैसे यह मामला तूल पकड़ता गया और दोषी खिलाड़ियों को निकाल बाहर करने की मांग जोर पकड़ती गई, कुछ लोग उन्हें बचाने के तरीक़े भी तलाश करने लगे. यही हमारी सबसे बड़ी ग़लती है. विदेशों में हम पर जैसे ही कोई आरोप लगता है, उल्टा आरोप लगाने की हमें जैसे आदत पड़ चुकी है. विदेश से ही डॉ. ओवैस नामक मेरे एक दोस्त ने मुझे एक ईमेल भेजा, मैं उसे यहां पेश कर रहा हूं, मेरा विश्वास है कि हमारे क्रिकेटर दोषी नहीं हैं, न ही वे ऐसे किसी अनैतिक काम में शामिल हैं. यह सारा वाकया अपनी ग़लतियां छुपाने की अंग्रेजों की साज़िश भर है. इंग्लैंड टीम के एक खिलाड़ी ने एक पाक खिलाड़ी को धक्का दिया, उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन कोई इसकी चर्चा नहीं कर रहा. हर कोई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही बातें कर रहा है. इससे यह मालूम चलता है कि अंग्रेज हमसे कितनी नफरत करते हैं.

एक प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल पर कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए दो लोकप्रिय एंकरों ने भी ऐसी ही दलीलें पेश कीं. उन्होंने न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड की साख पर सवालिया निशान लगाते हुए यह बताया कि इस टेबलॉयड ने कई बार ऐसी ख़बरें छापी हैं, जिसे प्रमाणित करने के लिए इसके पास कोई सबूत नहीं होते. अदालती मुक़दमों में इसे कई बार मुंह की खानी पड़ी है. लेकिन वे यह बताना भूल गए कि दस में से नौ मौक़ों पर यह टेबलॉयड अपना लक्ष्य साधने में कामयाब रहा है. कई बार ऐसा हुआ है, जब राजनीतिज्ञों की निजी ज़िंदगी से जुड़े मामले उजागर होने के बाद उन्हें अपने पदों से इस्तीफ़ा देना पड़ा है. इसमें कोई संदेह नहीं कि नतीजों पर पहुंचने के मामले में हम अनावश्यक जल्दबाज़ी में होते हैं, लेकिन क्रिकेट खिलाड़ियों से जुड़े इस मामले में मेरा तर्क यह है कि लॉर्ड्स के मैदान से बाहर कोई भला यह अनुमान कैसे लगा सकता है कि कोई खास गेंदबाज़ अपने किस ओवर की कौन सी गेंद नो बॉल फेंकेगा. स्पष्ट शब्दों में कहें तो यह नामुमकिन जैसा है. इसके अलावा स्टिंग ऑपरेशन करने वाले पत्रकार ने जो फुटेज उपलब्ध कराए हैं, उनमें एक संदेहास्पद चरित्र के व्यक्ति को कैमरे के सामने 1,50,000 पाउंड की राशि लेते हुए दिखाया गया है. उसके आधार पर यही कहा जा सकता है कि इतना धुआं बिना आग के नहीं फैल सकता. फिर ख़बर चाहे कितनी भी सनसनीखेज क्यों न हो, लेकिन इंग्लैंड का कोई अख़बार बिना किसी सबूत के उसे छापकर अदालती मुक़दमों को आमंत्रित करने का ख़तरा क्यों मोल लेगा? मुझे सबसे ज़्यादा दुःख युवा गेंदबाज़ मोहम्मद आमिर को लेकर होता है. असाधारण रूप से प्रतिभाशाली 18 वर्षीय बाएं हाथ का यह गेंदबाज़ आज अपनी आंखों के सामने अपना करियर गर्त में जाते हुए देखने को विवश है. यह स्पष्ट है कि आमिर केवल पैसे के लालच में ही इस गोरखधंधे में शामिल नहीं हुआ, बल्कि इसमें टीम के साथी खिलाड़ियों की भी बड़ी भूमिका है. जब वरिष्ठ खिलाड़ियों ने उसे यह बताया कि एकाध नो बॉल फेंक देने से कोई आफत नहीं आ जाएगी और लगे हाथ कुछेक करोड़ रुपये की कमाई भी हो जाएगी तो वह ख़ुशी-ख़ुशी उनका साथ देने के लिए तैयार हो गया होगा. आमिर के इस किस्से से मुझे अपने कॉलेज के दिन याद आने लगते हैं, जब मैंने अपने वरिष्ठों को देखकर सिगरेट पीनी शुरू कर दी थी, लेकिन सिगरेट पीने के जुर्म में आप जेल नहीं जाते, बस कब्र में जल्दी पहुंचने का रास्ता ही तैयार होता है. एक बात और है. दिखावे की ज़िंदगी जीते-जीते हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि किसी संस्था या व्यक्तियों के एक समूह को हम समाज से अलग करके नहीं देख सकते, समाज के अन्य हिस्सों के मुक़ाबले नैतिकता और मूल्यों के मामलों में उनसे ऊंचे स्तर की मांग नहीं कर सकते. जब हर कोई, यदि वह इस हालत में है, अपने फ़ायदे के लिए व्यवस्था का दोहन करने में लगा है तो हम अपने क्रिकेटरों से ईमानदारी और शुचितापूर्ण व्यवहार की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? यह तर्क कि खिलाड़ियों को खेलने के लिए करोड़ों रुपये मिलते हैं, में कोई दम नहीं है, क्योंकि राजनीतिज्ञों से लेकर सैन्य अधिकारियों, न्यायाधीशों, बैंक अधिकारियों, उद्योगपतियों, पुलिस अधिकारियों एवं नौकरशाहों में कोई ऐसा नहीं है, जो भूखों मर रहा हो. ये क्रिकेट खिलाड़ी भी इसी वातावरण में पले-बढ़े हैं, जहां भ्रष्टाचार अपवाद नहीं रह गया है, बल्कि व्यवस्था का एक हिस्सा बन चुका है. यदि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने की हैसियत का फ़ायदा उठाते हुए इन युवा खिलाड़ियों ने कुछ अवैध पैसा कमा लिया तो हम इस पर आश्चर्यचकित होने का दिखावा क्यों कर रहे हैं?

फिर स्टारडम के अपने ख़तरे होते हैं. कुछ खिलाड़ी ही स्टारडम के साथ आने वाली चमक-दमक को झेल पाते हैं और अपने करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में कामयाब हो पाते हैं. अधिकांश ऐसे हैं, जो रास्ते में ही भटक जाते हैं. शीर्ष स्तर के खिलाड़ी भी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के दबाव को ज़्यादा झेल नहीं पाते. तीस की उम्र पार करते-करते उनका शरीर भी जवाब देने लगता है और वे संन्यास लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं. युवा खिलाड़ियों की फौज टीम में उनकी जगह लेने के लिए हमेशा तैयार रहती है और टीम में बने रहने की जद्दोजहद हमेशा चलती रहती है. अधिकतर युवा खिलाड़ी निम्न-मध्यवर्गीय पृष्ठभूमि से आते हैं. वे न तो ज़्यादा शिक्षित होते हैं और न ही बैट एवं बॉल के साथ उनकी योग्यता के अलावा उनके पास और कोई प्रतिभा होती है. उबड़-खाबड़ मैदानों और तंग गलियों में क्रिकेट का ककहरा सीखने वाले इन युवाओं को यह अच्छी तरह पता होता है कि ग़रीबी क्या होती है. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में क़दम रखने के बाद भी यदि वे गंदगी और जिल्लत की अपनी पुरानी जड़ों को तलाशने की कोशिश करने लगें तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? मैं दोषी खिलाड़ियों का बचाव करने की कोशिश नहीं कर रहा, केवल उन कारणों को तलाश रहा हूं, जिन्होंने उन्हें ऐसा करने की हालत में पहुंचा दिया.

हमारी राष्ट्रीय क्रिकेट टीम पर मैच फिक्सिंग के आरोप सालों से लगते रहे हैं. सच्चाई यह है कि मैच फिक्सिंग के आरोप झेल रहे हमारे खिलाड़ी अकेले नहीं हैं. भारत, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीकी टीम के खिलाड़ी भी ऐसे आरोप झेलते रहे हैं. लेकिन पाकिस्तानी टीम ऐसे स्कैंडलों को लेकर सबसे ज़्यादा विवादों में रही है. जैसे ही ऐसे आरोपों को हवा मिलती है, पहले के ख़राब प्रदर्शनों को नए नज़रिए से देखा जाने लगता है. क्या सिडनी टेस्ट मैच फिक्स था? यह चर्चा तब भी चली थी, जब मुक़ाबले के दौरान लगातार पिछड़ती रही ऑस्ट्रेलियाई टीम ने आश्चर्यजनक रूप से हमें हरा दिया था. यदि यह मान लें तो इसके बाद इंग्लैंड दौरे पर टीम ने बार-बार ऐसा प्रदर्शन किया, जिस पर संदेह किया जा सकता है. मैच फिक्सिंग के साथ यही समस्या होती है, लोग पुराने नतीजों पर भी सवालिया निशान खड़े करने लगते हैं. जहां शंका की गुंजाइश नहीं होती, वहां भी नए प्रश्न खड़े हो जाते हैं. इससे पहले जब कभी भी ऐसा हुआ तो अधिकारियों ने ऐसे मामलों से या तो मुंह मोड़ लिया या उन पर पर्दा डालने की कोशिश करने लगे. पक्के सबूत मिलने पर भी खिलाड़ियों को जुर्माना लगाकर या चेतावनी देकर छोड़ दिया गया. यदि खिलाड़ी टीम के लिए महत्वपूर्ण है तो उसके निलंबन को भी माफ कर दिया गया. इसका नतीजा यह हुआ कि खिलाड़ी बेफिक्र होकर ऐसा करने लगे. उन्हें पता था कि पकड़े जाने पर भी जांच समितियां उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी और उनकी प्रतिष्ठा बरक़रार रहेगी. टीम अनुशासन को लेकर हमारे क्रिकेट प्रशासकों का रवैया बेहद ही निराशाजनक रहा है. वरिष्ठ खिलाड़ियों की हर हरकत को नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है और वे क्रिकेट बोर्ड को अपनी बातें मानने के लिए मजबूर करने में कामयाब हो जाते हैं. लेकिन क्रिकेट के ये कर्ताधर्ता भी उसी व्यवस्था का हिस्सा हैं, जहां भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ क़दम उठाने के बजाय उस ओर से आंखें मूंद ली जाती हैं. जब सारा देश और सारा समाज ही भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हो तो फिर क्रिकेट इससे अछूता कैसे रह सकता है.

आई हुसैन
feedback@chauthiduniya.com
(लेखक पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हैं)

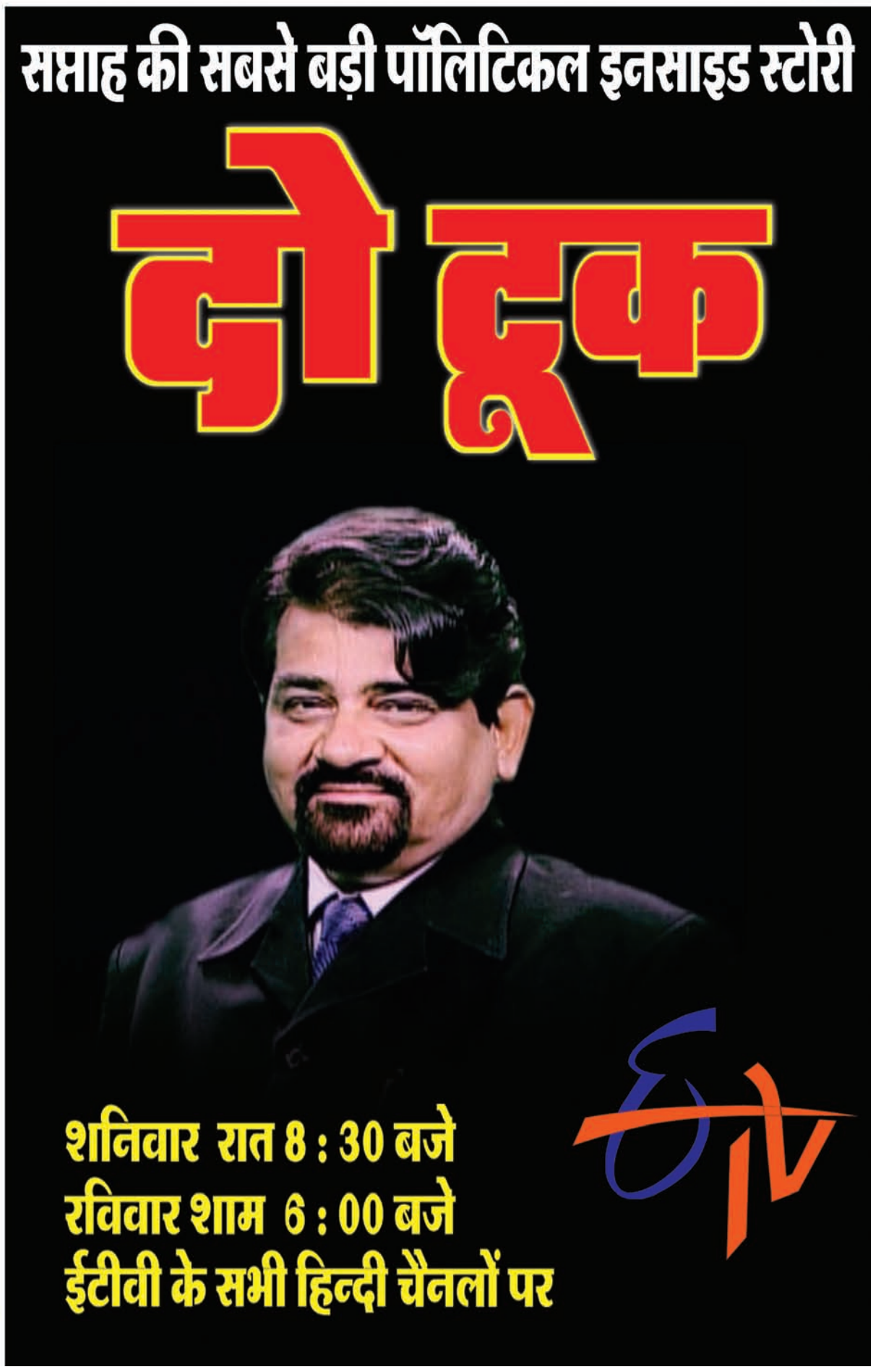

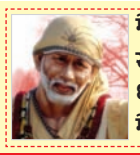

मैं भगवान से शक्ति मांगने लगी सही रास्ते पर जाने की. हमारे घर में धार्मिक माहौल नहीं था और न ही मैं किसी भगवान को मानती थी.

साई की महिमा का अनुभव

मैं आज अपने जीवन का एक ऐसा अनुभव आपके साथ बांटना चाहती हूं, जिसमें साई बाबा की कृपा की वजह से मैं संभल पाई. मैं जीवन की ऐसी भंवर में फंसी थी, जिसमें आज बहुत से पढ़े-लिखे युवक-युवती घिरे रहते हैं. इस अनुभव को आपके साथ बांटने और जीवन में आए बदलाव को आप तक पहुंचाने की प्रेरणा भी मुझे साई बाबा से ही मिली है. मैं अपने परिवार की सबसे छोटी बेटी हूं. पिता सरकारी नौकरी में हैं. घर में सब ठीक है, लेकिन मैं बचपन से ही थोड़ा अलग स्वभाव की थी. अपने बलबूते पर बड़ा बनना चाहती थी. मैंने एमबीए करने के बाद एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी कर ली. एमबीए के दौरान मेरे सहपाठी के साथ मेरा प्रेम हुआ. नौकरी मिलने पर मुझे एहसास हुआ कि साथ घूमने-फिरने तक तो ठीक था, लेकिन एक जीवनसाथी के रूप में मुझे कुछ और चाहिए था. उसके साथ मैं पूरा जीवन नहीं बिता सकती थी. उसे भी कुछ साल मेरी तरह ख़ुद को स्थापित करने के लिए संघर्ष करना था. इन्हीं बातों में हमारा ब्रेकअप हो गया. मैं दु:खी हुई, रिश्ता टूटने का दर्द था, क्योंकि किसी साथी के हमेशा साथ होने की आदत पड़ चुकी थी, वह मुझे सालने लगी. इसी दौरान मेरे बॉस, जो मुझसे क़रीब 8-9 साल बड़े थे, मुझे ज़्यादा तवज्जो देने लगे. शायद उन्हें मेरे अकेलेपन का एहसास हो गया था. उनकी क्रिएटीविटी और मैनेजमेंट स्किल ने मुझे बहुत प्रभावित किया. वह मेरे लिए आइडल मैन बनते जा रहे थे. फिर एक दिन मैं ऑफिस में लेट हो गई. उन्होंने कहा कि वह उसी तरफ़ जा रहे हैं, मुझे छोड़ देंगे. मुझे उनके साथ बैठना अच्छा लगा. वह अपने बारे में बताने लगे कि शादीशुदा हैं, पत्नी और एक बहुत प्यारी बच्ची है. उनकी बातों से साफ़ लग रहा था कि वह अपनी पत्नी और बच्ची से बहुत प्यार करते हैं. तभी उनका मोबाइल बजा, लाइन पर उनकी पत्नी थीं. उन्होंने बहुत प्यार से उनसे बात की, लेकिन वहां से ज़ोर-ज़ोर से चीखने-चिल्लाने की आवाज आ रही थी. यह बहुत धैर्य से उनसे बात कर रहे थे, लेकिन न जाने वह किस बात पर चीखती ही जा रही थीं. फिर उधर से उन्होंने फोन पटक दिया.

मेरे पूछने पर कि वह इतना नाराज़ क्यों थीं, ऐसे लगा जैसे उनके सब्र का बांध ही टूट गया. मैं उनकी दर्दभरी कहानी सुनती रही. जो यहां कहने का कोई तात्पर्य नहीं, क्योंकि आज मैं जानती हूं कि वह सब सच नहीं था. दो घंटे बाद मैंने पाया कि हम भावना में बह गए. घर छोड़ते वक्त उन्होंने मुझसे कहा, सॉरी, जो भी आज हुआ, उसे भूल जाना. मैं अपने जीवन की गंदगी में तुम्हें नहीं घसीटना चाहता. एक तरफ प्रेम की भावना दूसरी तरफ उनकी पत्नी के प्रति नफ़रत और गुस्सा था. अगले दिन मैंने पाया कि बॉस उदास और कटे-कटे से थे. मैंने बॉस से कहा, मैं आपको लंच पर ले चलती हूं. उन्होंने मना कर दिया. मुझे दु:ख हुआ, लेकिन चुप रही. शाम को बॉस का एसएमएस आया कि डिनर पर चलो. मेरी खुशी का पारावार न रहा. एक दिन उन्होंने मुझे प्रपोज किया. मैं हैरान रह गई. उन्होंने मुझे तलाक के पेपर दिखाए और बताया कि शादी के छह महीने के अंदर ही उनकी मुश्किलें शुरू हो चुकी थीं. अकेलापन और बच्चों का प्यार उन्हें यह कदम उठाने से रोके हुए था. मुझसे मिलकर उन्हें भरोसा हो गया कि वह मेरे साथ पूरा जीवन गुज़ार पाएंगे. मैंने खुशी से हां कर दी.

यह सिलसिला लगभग छह महीने चला. धीरे-धीरे मैंने महसूस किया कि वह बदलने लगे. जब भी तलाक का मुद्दा उठाती, टाल जाते. हद तो तब हो गई, जब एक दिन उनकी पत्नी के बारे में मैंने कुछ कहा तो उन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया. उन्होंने मुझसे माफी मांगी. मैं सामान्य हो गई. मैं भगवान से शक्ति मांगने लगी सही रास्ते पर जाने की. हमारे घर में धार्मिक माहौल नहीं था और न ही मैं किसी भगवान को मानती थी. इसी दुविधा में अचानक मैंने टीवी पर साई की महिमा कार्यक्रम देखा. मुझे लगा कि मुझे रास्ता दिखाने के लिए ही यह बना है. मैंने फोन किया. ऑसिम जी से मिलने का समय बहुत मुश्किल से मिला. मैं और मेरी बहन मिलने गए. बहन की कोई अपनी समस्या थी. चलते-चलते मैंने अकेले मिलने का समय मांगा, उन्होंने दे दिया. ऑसिम जी से अकेले मुलाकात कर मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया. अचरज की बात यह कि अपनी बात कहते-कहते समझ में आने लगा कि मैं कहां ग़लत थी. ऑसिम जी ने सिर्फ़ एक ही बात कही, उसे छोड़ दो, मुश्किल होगा. समय लगेगा, लेकिन विश्वास बनाए रखना. उन्होंने मुझे साई सच्चरित्र पढ़ने के लिए दी और कहा, ग्यारह दिन में इसे पढ़ लो. मैं एक अंजाने विश्वास और ख़ुशी से भर गई. ऐसे लगा, कोई अलौकिक शक्ति मेरे साथ है. मेरा आत्मविश्वास बढ़ने लगा. मैंने उससे मिलना कम कर दिया, दूसरी नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया. जब अकेलापन लगता तो साई सच्चरित्र पढ़ती. थोड़ी राहत मिलती. धीरे-धीरे मैं मज़बूत होने लगी. मुझे दूसरी नौकरी मिल गई थी. जब मैंने इस्तीफ़ा दिया तो वह हैरान हो गया. मुझे रात को डिनर पर बुलाया. यह मेरी सबसे बड़ी परीक्षा थी. मैं कमज़ोर पड़ रही थी. मैंने ऑसिम जी से मिलने की कोशिश की. उनसे मिलते ही मुझे एक बार फिर शक्ति मिल गई. उन्होंने सिर्फ़ यह कहा, घबराओ नहीं, थोड़ा सा समय और लगेगा, लेकिन तुम हारना नहीं. तीन महीने के अंदर-अंदर तुम्हें कोई मिलेगा, जो जीवन भर के लिए होगा. मैं हैरान रह गई. मैंने कहा कि मैं इस वक़्त किसी से प्यार करने की सोच भी नहीं सकती. उन्होंने बहुत प्यार से मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, जाओ बाबा साथ हैं. न जाने क्या था उस दिन, मैं बहुत सामान्य होकर वहां से निकली और उससे मिली. उसकी हालत ख़राब थी. कहने लगा कि मत जाओ, लेकिन अब मैं उस मासूमियत के पार देखना सीख चुकी थी. मैंने उसे समझाया कि अपनी पत्नी और बच्चों के पास जाओ और साई सच्चरित्र उसे देकर लौट आई. वहां से लौटना मेरे जीवन की सबसे बड़ी जीत थी. चार महीने गुज़र चुके हैं. मैं नई नौकरी में बहुत खुश हूं. उसके फोन-एसएमएस लगातार आते हैं, लेकिन मैं इन सबसे निर्लिप्त रहती हूं. आपको एक बात बताना तो भूल ही गई, ऑसिम जी के कहे अनुसार ही लगभग एक महीने पहले हमारे ऑफिस में एक नए कर्मचारी की ज्वाइनिंग हुई. वह भी टूटे हुए रिश्ते से बाहर निकल रहा है. हम दोनों दोस्त हैं, एक दूसरे के दर्द को समझते हैं. बाबा के एहसास ने मुझे आज में जीना सिखाया और आज अभी मैं खुश हूं तो कल तो खुश हो ही जाऊंगी.

ओम साई राम.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

कृष्ण की नगरी में आपका अपना घर!

Giriraj Sai Hills

Sai Vihar Township

Spiritual home... away from home

- Fully Furnished and Spacious studio Apartments.
- One Bedroom Apartments.
- Two bedroom Apartments.
- Fully Furnished Villas.

STARTING FROM RS. 9.65 LAKHS*

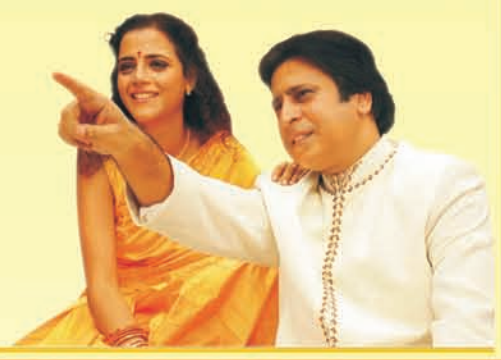

AUM Infrastructure & Developers
Tel./Fax : 011-46594226/27
Email: info@ssbf.in
Website: www.girirajsaihills.in

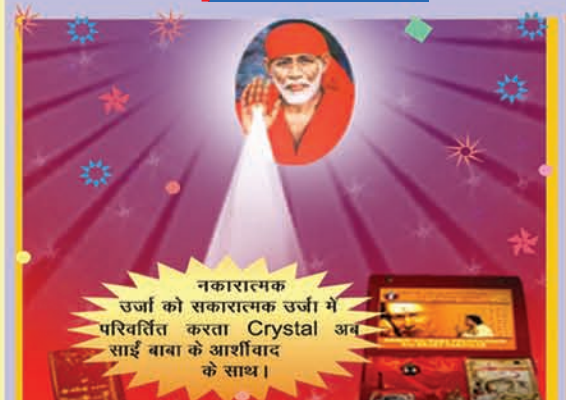

This Festival Season gift it to your loved ones....
011-46567351/52

संपर्क करें:
शिरडी साई बाबा फाउन्डेशन
252- H, LGF कैलाश प्लाज़ा, मेन रोड, सन्तनगर,
ईस्ट अफ् कैलास, नई दिल्ली-110065
Tel./Fax: 91-11-46567351/52
web: www.ssbf.in

SSBF

ग्यारह वचन

१. जो शिरडी आएगा। आपद दूर भगाएगा।
२. चढ़े समाधि की सीढ़ी पर। पैर तले दु:ख की पीढ़ी पर।
३. त्याग शरीर चला जाऊँगा। भक्त हेतु दौडा आऊँगा।
४. मन में रखना दृढ़ विश्वास। करे समाधी पूरी आस।
५. मुझे सदा जीवित ही जानो। अनुभव करो सत्य पहचानो।
६. मेरी शरण आ खाली जाए। हो कोई तो मुझे बताए।
७. जैसा भाव रहा जिस मन का। वैसा रुप हुआ मेरे मन का।
८. भार तुम्हारा मुझ पर होगा। वचन न मेरा झूठा होगा।
९. आ सहायता लो भरपूर। जो माँगा वह नही है दूर।
१०. मुझ में लीन वचन मन काया। उसका ऋण न कभी चुकाया।
११. धन्य धन्य व भक्त अनन्य। मेरी शरण तज जिसे न अन्य।

संपर्क करें:
शिरडी साई बाबा फाउन्डेशन
252-H, LGF कैलाश प्लाज़ा, सन्तनगर, ईस्ट अफ् कैलास, मेन रोड, नई दिल्ली-110065.
Tel./Fax: 91-11-46567351/52
web: www.ssbf.in

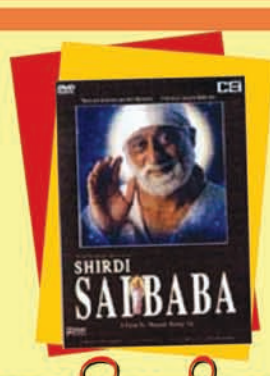

पहली बार शिरडी साई बाबा फीचर फिल्म अब कॉमिक्स के रूप में

क्रमश:

सभी साई भक्तों को विनम्रता से सूचित किया जाता है कि आप अपने साई अनुभव, साई उत्सवों आदि की विस्तृत सूचना, फाउंडेशन में सदस्यता के लिए info@ssbf.in पर मेल या 011-46567351/52 पर संपर्क कर सकते हैं.

उत्सव सरीखे जश्न का यह मौक़ा होता है वरिष्ठ लेखक एवं हंस के संपादक राजेंद्र यादव के जन्मदिन का. मैं नब्बे के दशक की शुरुआत में दिल्ली आया.

बयासी साल का ज़िंदादिल जवान

अनंत विजय

दिल्ली के साहित्य प्रेमियों को हर साल 28 अगस्त का इंतज़ार रहता है. साहित्यकारों को तो खासतौर पर. हर साल यह दिन दिल्ली में एक उत्सव की तरह मनाया जाता है. दिल्ली के सारे साहित्यकार एक जगह इकट्ठा होते हैं, जमकर खाते-पीते हैं. महानगर की इस भागदौड़ और आपाधापी की ज़िंदगी में कई लोग तो ऐसे भी होते हैं, जो साल भर बाद इस दिन ही मिलते हैं. उत्सव सरीखे जश्न का यह मौक़ा होता है वरिष्ठ लेखक एवं हंस के संपादक राजेंद्र यादव के जन्मदिन का. मैं नब्बे के दशक की शुरुआत में दिल्ली आया. शुरुआत के कुछ वर्ष छोड़ दें तो तबसे लेकर तक़रीबन हर साल यादव जी के जन्मदिन के जश्न का गवाह रहा हूं. एक बार तो बिन बुलाए भी पहुंच गया. कई लोगों से मैं पहली बार राजेंद्र यादव के जन्मदिन के मौक़े पर ही मिला. हिंदी के वरिष्ठतम लेखकों में से एक श्रीलाल शुक्ल जी से मेरी पहली मुलाक़ात राजेंद्र जी के जन्मदिन के मौक़े पर हुई थी. उस वर्ष राजेंद्र जी का जन्मदिन कवि उपेंद्र कुमार के पार्क स्ट्रीट के सरकारी बंगले पर ही मनाया गया था. श्रीलाल जी से मुलाक़ात और साहित्यकार के अलावा उनके सतरंगे व्यक्तित्व से परिचित होना मेरे लिए एक सुखद आश्चर्य की तरह था. यादव जी के जन्मदिन के मौक़े पर ही मैंने प्रभाष जोशी को उनका पांव छूते देखा. ख़ैर ये अवांतर प्रसंग हैं, जिन पर फिर कभी विस्तार से चर्चा होगी.

इस बार अपने जन्मदिन से कुछ रोज पहले राजेंद्र जी की तबियत इतनी बिगड़ गई थी कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था. पता चला था कि शरीर में शुगर

यादव जी का जन्मदिन बेहद क़रीबी लोगों के साथ मनाया जाए. अजय नावरिया को उनकी इस मुहिम में साथ मिला उत्साह और ऊर्जा से लबरेज पत्रकार गीताश्री का. नियत समय पर हम लोग दिल्ली के रायसीना रोड स्थित प्रेस क्लब में इकट्ठा हुए. तीस-चालीस आमंत्रित लोगों के साथ राजेंद्र जी ने केक काटा. सबने हैप्पी बर्थ डे टू यू गाया, तालियां बजीं. लेकिन सबसे दिलचस्प रहा राजेंद्र जी के दोस्त डॉक्टर सक्सेना का गिफ्ट. सक्सेना जी ने यादव जी को एक ढोल दिया, जिसके एक ओर चिपका था- दलित, दूसरी ओर मुसलमान और तीसरी ओर स्त्री. संदेश यह था कि राजेंद्र जी साहित्य में दलित, मुसलमान और स्त्रियों की समस्याओं का ढोल पीटते हैं तो अब उनके गले में असल में ही ढोल डाल दिया जाए.

की कमी हो गई. अस्पताल से भरपूर मिठास लेकर यादव जी घर लौटे थे. मेरी इस दौरान लगातार बात होती रही. मैं लगातार पूछता रहा कि इस बार जन्मदिन का जश्न कहां हो रहा है, लेकिन यादव जी टालते रहे. फिर एक दिन फोन किया और जश्न-ए-जन्मदिन के बारे में पूछताछ की तो पता चला कि वह तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में भर्ती हैं. जब और हालचाल जानने की कोशिश में बात आगे बढ़ी तो राजेंद्र जी ने बताया कि वह कुछ टेस्ट के लिए भर्ती हुए हैं, चिंता की बात नहीं है. बातचीत करने के बाद लगा कि शायद इस बार यादव जी का जन्मदिन न मनाया जाए, लेकिन सत्ताइस अगस्त की शाम को लेखक अजय नावरिया का एक संदेश प्राप्त हुआ, राजेंद्र यादव जी अपनी ज़िंदगी के 82वें साल में प्रवेश कर रहे हैं, इस मौक़े पर प्रेस क्लब में होने वाले आयोजन में आप आमंत्रित हैं. संदेश के बाद अजय नावरिया ने फोन भी किया. पता चला कि आयोजकों ने यह तय किया है कि इस बार यादव जी का जन्मदिन बेहद क़रीबी लोगों के साथ मनाया जाए. अजय नावरिया को उनकी इस मुहिम में साथ मिला उत्साह और ऊर्जा से लबरेज पत्रकार गीताश्री का. नियत समय पर हम लोग दिल्ली के रायसीना रोड स्थित प्रेस क्लब में इकट्ठा हुए. तीस-चालीस आमंत्रित लोगों के साथ राजेंद्र जी ने केक काटा. सबने हैप्पी बर्थ डे टू यू गाया, तालियां बजीं. लेकिन सबसे दिलचस्प रहा राजेंद्र जी के दोस्त डॉक्टर सक्सेना का गिफ्ट. सक्सेना जी ने यादव जी को एक ढोल दिया, जिसके एक ओर चिपका था- दलित, दूसरी ओर मुसलमान और तीसरी ओर स्त्री. संदेश यह था कि राजेंद्र जी साहित्य में दलित, मुसलमान और स्त्रियों की समस्याओं का ढोल पीटते हैं तो अब उनके गले में असल में ही ढोल डाल दिया जाए. डॉक्टर सक्सेना इसके पहले भी राजेंद्र जी को बेहद अजूबे गिफ्ट देते रहे हैं. इसके पहले उन्होंने एक ऐसा मुखौटा भेंट किया था, जिसमें दस सिर लगे थे यानी एक लेखक के दस चेहरे. उसके पहले वह हुक्का भेंटकर सबको चौंका चुके थे. जिस तरह से सबको यादव जी के जन्मदिन का इंतज़ार रहता है, उसी तरह हर किसी की यह जानने में भी दिलचस्पी रहती है कि डॉक्टर सक्सेना इस बार क्या भेंट लेकर आने वाले हैं.

बेहद आत्मीयता से फिर खाने-पीने का दौर शुरू हुआ. गीताश्री एक बेहतरीन होस्ट की तरह सबके खाने-पीने का ध्यान रख रही थीं. जैसे ही उन्हें यह जानकारी मिलती कि कोई बग़ैर खाए जाने की बात कर रहा है, किसी को उसके पीछे लगा देतीं और तब तक निश्चिंत होकर नहीं बैठती थीं, जब तक कि वह खाना खा नहीं लेता. इस आयोजन में निर्मला जैन, भारत भारद्वाज, असगर वजाहत, पंकज विष्ट, साधना अग्रवाल के अलावा वरिष्ठ पत्रकार शाजी जमां, आशुतोष, अजीत अंजुम, परवेज अहमद और श्रीनंद झा भी मौजूद थे. अशोक वाजपेयी थोड़ी देर से ज़रूर पहुंचे, लेकिन अंत तक डटे रहे. यहां भी अशोक जी के साथ एक मजेदार वाकया हुआ. वह राजेंद्र जी एवं निर्मला जैन के साथ बैठे बातें कर रहे थे. अचानक डॉक्टर सक्सेना अशोक जी के पास पहुंचे और कहा, अशोक जी, जनसत्ता का आपका कॉलम बहुत अच्छा रहता है, आपकी भाषा बेहद शानदार है. यहां तक तो अशोक जी के चेहरे पर वही भाव थे, जो अपनी प्रशंसा सुनकर किसी भी व्यक्ति के चेहरे पर हो सकती है. लेकिन इसके बाद डॉक्टर सक्सेना ने जो कहा, उससे अशोक जी के चेहरे की चमक ग़ायब हो गई. डॉक्टर सक्सेना ने उनकी भाषा की प्रशंसा करते-करते यह कह डाला कि आपकी भाषा में वही रवानगी और ताज़गी है, जो किसी जमाने में शिवानी के लेखन में महसूस की जा सकती थी. यह अगर सक्सेना जी का व्यंग्य था तो बेहद शानदार था और अगर अनजाने में गंभीरतापूर्वक यह बात कही गई थी तो अशोक जी कभी-कभार में इसकी ख़बर ज़रूर लेंगे.

सभी लोग यादव जी से मजे ले रहे थे और उन्हें बयासी साल का होने पर बधाई दे रहे थे. राजेंद्र जी भी इस बेहद आत्मीय आयोजन से प्रसन्न दिख रहे थे. अपने साथी लेखकों से चुटकी भी ले रहे थे. यादव जी की जो एक ख़ूबी है, वह यह है कि उनके साथ रहकर साहित्यिक, ग़ैर साहित्यिक, बच्चा, बूढ़ा, जवान कोई भी बोर नहीं हो सकता. यादव जी जैसे बयासी साल के जवान और गीताश्री जैसी ज़िंदादिल होस्ट ने उस जश्न-ए-सालगिरह को एक यादगार लम्हा बना दिया. अंत में मैं इतना ही कह सकता हूं कि तुम जियो हज़ारों साल, साल के दिन हों पचास हज़ार.

(लेखक आईबीएन-7 से जुड़े हैं)

anant.ibn@gmail.com

पुस्तक अंश मुन्नी मोबाइल

गतांक से आगे

प्रदीप सौरभ

बक्सर गंगा के किनारे बसा है. इसीलिए गंगा यहां के लोगों के जीवन में हर तरह से रची-बसी है. गंगा इस इलाक़े की जीवनदायिनी है. बक्सर में उद्योग-धंधे तो हैं नहीं. गंगा के कारण इलाके की ज़मीन बेहद उपजाऊ है. खेती-किसानी मुख्य पेशा है. आजादी के बाद एक टेक्सटाइल मिल लगी थी. रंगदारी वसूली के चलते वह बंद हो गई. अब मिल परिसर में लंबी-लंबी घास उग आई है. चोर-सिपाही खेलते वक़्त बच्चे इस मिल का छिपने-छिपाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. भौगोलिक रूप से बक्सर पटना और बनारस के बीचोबीच बसा है. प्रशासनिक और राजनीतिक मजबूरी ने उसे बिहार से जोड़े रखा है. सांस्कृतिक तौर पर वह बनारस से ही ऊर्जा लेता है. रोजमर्रा की ज़िंदगी में बनारस का इस कदर दख़ल है कि बेटी ब्याहने की बात हो या फिर बहू लाने की, लोग बनारस की ही ओर ताकते हैं. उच्च शिक्षा का मसला हो या कोई बड़ी चीज खरीदने का सवाल, पटना उनके लिए दिल्ली की तरह हमेशा से दूर रहा है.

यह बात दीगर है कि बक्सर में किला मैदान में 1764 के युद्ध के बाद अंग्रेजों के लिए दिल्ली नजदीक हो गई थी. बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली के नवाब शाहआलम की संयुक्त सेना की अंग्रेज हेक्टर मुनरो की फौज के साथ जंग हुई थी. मीर कासिम की मंशा थी कि संयुक्त सेना के हमले के बाद बंगाल को फिर क़ब्ज़े में कर लिया जाएगा, लेकिन हुआ उल्टा. मुगलों की संयुक्त सेना को हार का सामना करना पड़ा. इसी के बाद बंगाल का सारा राजस्व अंग्रेजों ने अपने क़ब्ज़े में कर लिया. इसके बाद धीरे-धीरे अंग्रेज दिल्ली की ओर बढ़े और 1803 में वे दिल्ली में

क़ाबिज़ हो गए. इस हार ने बक्सर के लोगों के हौसले को जो पस्त किया तो फिर उन्हें सिर उठाने में लगभग एक सौ साल लग गए. गोबर पट्टी में एक बार फिर 1857 में जब अंग्रेजों के ख़िलाफ़ विद्रोह हुआ तो बक्सर में बाबू कुंवर सिंह की तलवार अंग्रेजों के ख़िलाफ फिर चमकी. उन्होंने अंग्रेजों को एहसास दिला दिया था कि जब तक मेरे ख़ून का एक कतरा भी धड़कता है, तब तक शाहाबाद के इलाक़े में उनकी मुख़ालफ़त का झंडा फहराता रहेगा. बक्सर के लोग लड़े और लड़ते ही रहे. इसीलिए वे और मोर्चों पर तरक़्क़ी नहीं कर पाए. एक बार पिछड़े तो पिछड़ते ही गए. बक्सर की लड़ाकू प्रवृत्ति ने सरकारों को उसके नज़दीक नहीं आने दिया. गंगा मैया की कृपा के कारण वे जीते रहे. गंगा की बाढ़ का प्रकोप कभी बक्सर में नहीं बरपा. सूखा भी कभी नहीं पड़ा.

मुन्नी की ससुराल रामो मझरिया में है. उसका मायका भी गांव के हिसाब से बहुत दूर नहीं है. बस-टैंपो से एक घंटा लगता है. मायका इटाड़ी थाना के अंतर्गत गोपीनाथपुर गांव में है. उसका बचपन यहीं गुजरा है. गांव की एक-एक गली में उसकी और उसकी सहेलियों-फूलकली, सुधिया, प्रेम कुमारी और धर्मशीला की शैतानियों की छाप है. उनकी शैतानियों से खेत-खलिहान और बाग-बगीचे भी नहीं अछूते रहे.

बस चली जा रही थी. गांव में अब उसकी बचपन की कोई सहेली नहीं बची थी. सबकी शादियां हो चुकी थीं. अकेली धर्मशीला की शादी अब तक नहीं हो पाई थी. धर्मशीला उसके चाचा बटेसर के लड़के रमेश से फंसी थी. बचपन से ही दोनों खेत और खलिहान में छिपकर मिलते थे. मुन्नी और उसकी सहेलियां छुप-छुपकर उनकी चुम्माचाटी देखती रहती थीं. उसे मुहब्बत का नाम नहीं दिया जा सकता था. दोनों के बीच मौजमस्ती ही नज़दीकी की वजह थी.

अगले अंक में जारी...

शिवोहम: कला और अध्यात्म का अनोखा संगम

सोनिका गुप्ता

कला का अर्थ है सृजन करना. कला जीवन को सत्यम् शिवम् सुंदरम् से समन्वित करती है. इसके द्वारा ही बुद्धि और आत्मा का सत्य स्वरूप झलकता है. कला व्यक्ति के मन में बनी स्वार्थ, परिवार, क्षेत्र, धर्म, भाषा एवं जाति आदि की सीमाएं मिटाकर विस्तार और व्यापकता प्रदान करती है. कला में मानव मन में संवेदनाएं उभारने, प्रवृत्तियों को ढालने, चिंतन को मोड़ने एवं अभिरुचि को दिशा देने की अद्भुत क्षमता है. कला और अध्यात्म के बीच एक अनोखा रिश्ता है. कला अपनी अंदरूनी भावनाओं को प्रदर्शित करने का एक जरिया है, अध्यात्म के साथ इसका मेल इसे एक पारलौकिक स्वरूप प्रदान करता है.

कुछ दिनों पहले ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स सोसायटी की गैलरी में अध्यात्म से जुड़ी तस्वीरें देखने को मिलीं. शिवोहम में सृष्टि के निर्माण और उससे जुड़े कई गूढ़ एवं दार्शनिक वेदांशों को पेंटिंग के माध्यम से बताया गया. प्रदर्शनी में डिज़ायर, आराधना, आत्मबोध, सत्यार्थ प्रकाश एवं मृगतृष्णा जैसी पेंटिंग्स में अध्यात्म के गूढ़ चक्र को विषय बनाया गया है. वहीं लव एंड पीस, मीरा, समर्पण, एक राधा-एक मीरा में प्रेम और सौहार्द्र के स्वरूप को दिखाने की कोशिश की गई है. रंगों की कलात्मकता के अलावा इसमें ऑयल पेंटिंग का भी ख़ूब इस्तेमाल किया गया है. शिवोहम की कलाकार वर्षा वैश्य ने पेंटिंग की विशेषता बताते हुए कहा कि आज की चकाचौंध भरी जीवनशैली में हर कोई शांति चाहता है.

उसी को ध्यान में रखकर उक्त पेंटिंग्स बनाई गई हैं. इनमें रंगों का बहुत ही सुंदर ढंग से प्रयोग किया गया है. पेंटिंग के माध्यम से यह बताया गया है कि जीवन में एक दिव्य शैली आज भी मौजूद है, केवल उसे सामने लाने और अपनाने की ज़रूरत है. शिव-पार्वती के संबंधों को भी बहुत ही अद्भुत ढंग से दर्शाया गया. पेंटिंग मीरा में भी यही दिखाया गया कि इंसान ख़ुद ही दु:ख का रास्ता तय करता है, क्योंकि वह सुख की तलाश में इधर-उधर भटकता रहता है. प्रेम और सत्य ही इंसान को शांति दे सकते हैं.

अध्यात्म केंद्रित कलाकृतियों के बारे में पूछने पर वर्षा ने बताया कि आधुनिक जीवनशैली ऐसी होती जा रही है, जिसमें नकारात्मक भावों की प्रधानता है. चारों ओर फैली हिंसा, ग़रीबी, बदहाली आदि के चलते निराशावादी सोच को बढ़ावा मिलता है. ऐसे में अध्यात्म आधारित कलाकृतियां सुकून देती हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं. राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय जगत में अध्यात्म की ओर बढ़ते रुझान के चलते ऐसी कलाकृतियां हमेशा लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करती हैं. कलाकारों की नई पीढ़ी अक्सर प्रतिष्ठित नामों की नकल करती रह जाती है और उनकी कृतियों में इस व्यापकता की कमी स्पष्ट नज़र आती है. शिवोहम इससे अलग है, क्योंकि इसकी कृतियों में अध्यात्म की गहराई है और कला की व्यापकता भी.

sonika@chauthiduniya.com

नए हाथों का हुनर

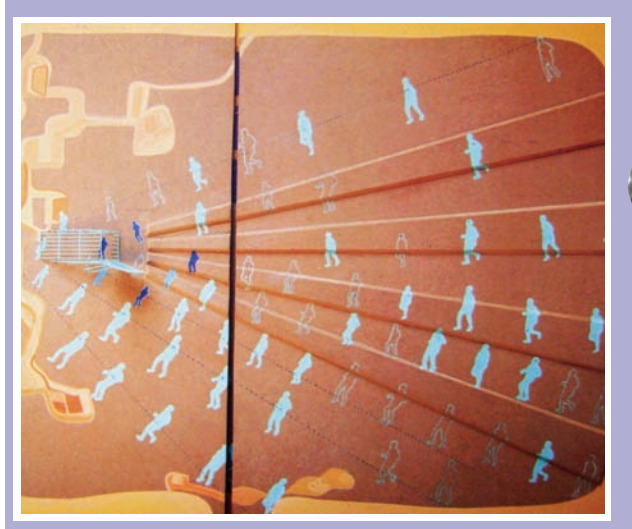

सुंदर कलाकृति वही है, जो मन को भा जाए. पिछले दिनों संपन्न हुई एक प्रदर्शनी में ऐसी ही कलाकृतियों के माध्यम से पांच प्रतिभाशाली युवा कलाकारों वंदना धसमाना, श्रुति शर्मा, राहुल, नरेंद्र सिंह एवं मानसी शर्मा ने बहुत प्रभावित किया. वंदना की नई एवं आकर्षक पेंटिंग स्टाइल, श्रुति के उत्सव चित्रण, राहुल की अद्भुत फाइबर ग्लास की कृतियों, मानसी के प्रकृति चित्रण और नरेंद्र द्वारा वेल्डिंग तकनीक से बनाई गई मेटल की बेहद आकर्षक मूर्तियों ने कलाप्रेमियों का मन मोह लिया. सभी के प्रयास बेहद प्रशंसनीय रहे.

धीर
dhir@chauthiduniya.com

इस नई सीरीज के एलसीडी प्रोजेक्टर इस बात के प्रतीक हैं कि कंपनी ने भारत के संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है.

वायरस से सावधानी बरतें

कंप्यूटर वायरस छोटा सा प्रोग्राम है, जो कंप्यूटर में ख़ुद-बख़ुद इंस्टॉल हो जाता है. साथ ही अपनी कई कॉपी बनाकर सिस्टम में छोड़ देता है. विश्व में पहला कंप्यूटर वायरस 1986 में पाकिस्तान के लाहौर में फारुख अली ब्रदर्स द्वारा बनाया गया, इसका नाम ब्रेन दिया गया था. इसके बाद बहुत सारे वायरस बनने लगे, जिन्हें सबसे पहले इस्तेमाल होने वाली फ्लॉपी डिस्क द्वारा बांटा जाने लगा.

दुष्प्रभाव

- वायरस के संपर्क में आने से कंप्यूटर धीमा हो जाता है और कभी-कभी ख़राब भी हो जाता है.
- कंप्यूटर वायरस सीधा स्टोरेज डिवाइस यानी हार्डडिस्क, पेन ड्राइव एवं फ्लॉपी आदि को निशाना बनाता है और उसमें बैड सेक्टर (हानिकारक प्रभाग) बना देता है, जिसके कारण जो भी डाटा हार्डडिस्क में होता है, वह करप्ट यानी क्षतिग्रस्त हो जाता है.
- कभी-कभी वायरस पूरे कंप्यूटर में फैल जाता है, जिसके कारण कंप्यूटर काम करना बंद कर देता है या हैंग हो जाता है. किसी भी ड्राइव को खोलने पर एक्सेस डिनायड एरर आ जाता है, प्रिंट कमांड देने पर भी काम नहीं करता है, बार-बार कंप्यूटर री-स्टार्ट होता है.
- जब बहुत खतरनाक वायरस होता है, तब एंटी वायरस को डिसेबल कर देता है. जब तक वायरस रहता है, तब तक एंटी वायरस काम नहीं करता.
- किसी वायरस में साउंड दिया हो, तब अचानक अपने आप ही आवाज़ करने लगता है, डेस्कटॉप पर अपने आप ही आइकन बन जाते हैं. बहुत सारे मेन्यू ऑप्शन ग़ायब हो जाते हैं, प्रोग्राम फाइल में जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, वे करप्ट हो जाते हैं.
- एक्जीक्यूटेबल फाइल करप्ट हो जाती है, अचानक डिस्क ड्राइव का साइज बढ़ जाता है. अंतत: ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो जाता है.
- उपयोगी विंडो फंक्शन को डिसेबल कर देता है: Ctrl+Alt+Del, Folder option etc:, विंडोज सिस्टम फाइल करप्ट हो जाती है, जैसे: explorer.exe, svchost.exe, win logon.exe, rundll32.exe
- वायरस से सिस्टम बैंक करप्ट हो जाता है, जिससे सिस्टम स्टार्ट नहीं होता है. बार-बार मेमोरी एरर मैसेज आता है, प्रोग्राम नॉट रेस्पांडिंग आ जाता है.

इंटरनेट से आने वाले वायरस

इंटरनेट से आने वाले वायरस ऑपरेटिंग सिस्टम को भारी मात्रा में क्षति पहुंचा कर उसे करप्ट कर देते हैं. वॉर्म और ट्रोजन हॉर्स वायरस कंप्यूटर को ज़्यादा क्षति पहुंचाए बिना कुछ ख़ास हिस्सों पर हमला करता है. यह वायरस हार्ड डिस्क में बची सारी जगह को अपनी प्रतिलिपि बनाकर भर देता है. आपके ईमेल से ईमेल आईडी की कांटेक्ट लिस्ट को अपने आप ही कॉपी बनाकर भेज देता है. हार्ड डिस्क को अपने आप फार्मेट कर देता है, जिससे उसमें पड़े प्रोग्राम डिलीट हो जाते हैं. पाइरेटेड सॉफ्टवेयर में भी वायरस होते हैं, जिसे इंस्टॉल करने पर कंप्यूटर में वायरस आ सकते हैं, जो सिक्यूरिटी को कमज़ोर बना देते हैं.

कैसे हटाएं

कंप्यूटर वायरस से बचना आसान है, अगर यूजर थोड़ी सी समझदारी और सावधानी बरतें.

- कंप्यूटर में इंटरनेट का कनेक्शन लगा हो तो डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट इनेबल रखें, जिससे कंप्यूटर ख़ुद-बख़ुद माइक्रोसॉफ्ट से जुड़कर ज़रूरी सर्विस और फाइल इंस्टॉल कर सके.
- फायर वॉल को हमेशा ऑन रखें. हमेशा अच्छे एंटी वायरस का प्रयोग करें, जैसे एंटी वायरस को हमेशा ऑन रखें, वायरस डाटा बेस हमेशा अपडेट करें.
- यदि निजी कंप्यूटर इंटरनेट से न जुड़ा हो, तब उस एंटी वायरस की वेबसाइट पर जाकर वायरस डाटा बेस इंस्टॉलर फाइल को डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लें, यह प्रक्रिया हफ्ते में कम से कम दो बार करें.
- हर दिन कंप्यूटर को अपने एंटी वायरस से स्कैन करें और इफेक्टेड फाइल को डिलीट करें.
- एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस अपने सिस्टम में लगाने से पहले उसे स्कैन कर लें, तब इस्तेमाल करें.
- इंटरनेट से जुड़ने से पहले अपने सिस्टम के एंटी वायरस का इंटरनेट सिक्योरिटी ऑन रखें और वेब ब्राउजिंग संभल कर करें.
- इंटरनेट से वैसी अटैचमेंट फाइल डाउनलोड न करें, जिसका एक्सटेंशन .exe, .com हो.

इंटरनेट पर उपलब्ध फ्री एंटी वायरस

- एवास्ट एंटी वायरस.
- एवीजी फ्री.
- एवाया एंटी वायरस.
- बीट डिफेंडर.
- क्लैमविन.
- कोमोडो इंटरनेट सिक्योरिटी.
- इम्यूनेट प्रोटेक्ट.
- माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी एशेनशियल्स.
- छीसी टूल्स एंटी वायरस.
- राइजिंग एंटी वायरस.
- स्पाइवेयर टर्मिनेटर.
- एसेट एनओडी-32.
- कास्परस्काई.
- ट्रेंड माइक्रो.

मोबाइल वायरस

आजकल मल्टीमीडिया मोबाइल फोन का प्रचलन ज़ोरों पर है. ऐसे मोबाइल फोन में मेमोरी कार्ड का प्रयोग होता है, जिसमें मल्टीमीडिया फाइल्स संरक्षित होती हैं. इन मेमोरी कार्ड में डाटा दो तरह से संरक्षित किया जाता है, कंप्यूटर द्वारा और ब्लुटुथ द्वारा. जब कोई भी डाटा कंप्यूटर द्वारा मेमोरी कार्ड में डाला जाता है तो उसके साथ कंप्यूटर में पहले से पड़ा वायरस मेमोरी कार्ड में ख़ुद-बख़ुद चला जाता है और जब मेमोरी कार्ड फोन में लगाकर इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें कई प्रकार के ऑटो और मालफंक्शनिंग होने लगती है. अगर ब्लुटुथ के ज़रिए डाटा ट्रांसफर करते हैं तो दूसरी फाइलों के साथ वायरस भी छिप कर आ जाता है. इससे भी मोबाइल फोन की मालफंक्शनिंग होने लगती है.

मोबाइल वायरस के दुष्प्रभाव

- फोन कॉल अपने आप बिना कोई बटन दबाए रिसीव होना.
- मोबाइल हैंग होना, अपने आप बंद हो जाना.
- कांटेक्ट में शामिल किसी भी नंबर पर अपने आप एसएमएस चला जाना.
- मोबाइल में कांटेक्ट की एड्रेस बुक डिलीट हो जाना.
- कुछ जाने-पहचाने मोबाइल वायरस हैं जैसे केबीर, डट्स, स्कल्स और कॉमवैरियर.

इन ख़तरनाक वायरस से बचने के लिए मोबाइल में भी एंटी वायरस डालते हैं.

कुछ मोबाइल एंटी वायरस

- एफ-सेक्योर एंटी वायरस.
- सिमैंटेक सिक्योरिटी.
- एफबी-4 वायरस गार्ड.
- कैस्पर स्काई.

कुछ मल्टीमीडिया मोबाइल फोन सेट ऐसे होते हैं, जिनमें माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने ख़ास तरह का एंटी वायरस बनाया है. जैसे बुगार्ड मोबाइल एंटी वायरस, एफ-सेक्योर मोबाइल एंटी वायरस, सिमैंटेक एवं एयरसैनर एंटी वायरस फॉर विंडोज मोबाइल, ट्रेंड माइक्रो मोबाइल सिक्योरिटी आदि.

अब तक के सबसे ख़तरनाक कंप्यूटर वायरस

पहला वायरस बनने के बाद कई प्रकार के वायरस बनाए गए, जिससे विश्व में काफ़ी नुक़सान हो चुका है. इन वायरस के नाम अज़ीबोग़रीब होते हैं, जैसे कोई संदेश- हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी न्यू ईयर, यू हैव वन, नीड हेल्प, व्यक्ति, वस्तु या जगह का नाम आदि.

- जेरूसेलम-1987 में आया यह पहला एमएस डॉस वायरस है.
- मॉरिस (इंटरनेट वॉर्म)-1998 में इस वायरस से केवल अमेरिका में 6000 कंप्यूटर सिस्टम को नुक़सान पहुंच चुका है, जिससे 96 मिलियन डॉलर का नुक़सान हुआ.
- सोलर सनराइज-इसने 1998 में अमेरिका के 500 सैन्य, सरकारी और निजी क्षेत्र के कंप्यूटरों को अपने क़ब्ज़े ले लिया था.
- मेलिसा-1999 में आया यह वायरस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड-97 और वर्ड-2000 पर मल्टीप्लाई हो जाता है, इससे लगभग 300 से 600 मिलियन डॉलर का नुक़सान पूरे विश्व में हो चुका है.
- आई लव यू-मई 2000 में आया यह वायरस 10-15 बिलियन डॉलर का नुक़सान कर चुका है.
- द कोड रेड वॉर्म-जुलाई 2001 में आए इस वायरस से 2.6 बिलियन डॉलर का नुक़सान हुआ.
- निमदा-11 सितंबर 2001 के बाद आया यह वायरस हज़ारों कंप्यूटरों को नुक़सान पहुंचाता है और पांच अलग तरीक़ों से प्रभावित करता है.
- एसक्यूएल स्लैमर- 2003 में आया यह वायरस एक बिलियन डॉलर से ज़्यादा का नुक़सान पहुंचा चुका है.
- ब्लास्टर-2003 में आया यह वायरस 2 से 10 बिलियन डॉलर का नुक़सान कर चुका है.
- बैगल-2004 में आए इस वायरस से दस मिलियन डॉलर का नुक़सान हुआ.
- मायडूम-2004 में आए इस वायरस ने पूरे विश्व में इस्तेमाल हो रहे इंटरनेट पर पचास प्रतिशत का लोड डालकर ग्लोबल इंटरनेट परफार्मेंस को नुक़सान पहुंचाते हुए दस प्रतिशत धीमा कर दिया था.

रीतिका सोनाली
ritika@chauthiduniya.com

वोल्टेज कम-ज़्यादा हो तो भी इनकी फंक्शनिंग में कोई फ़र्क़ नहीं पड़ेगा.

पैनासोनिक का नया प्रोजेक्टर

इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी पैनासोनिक ने गो फॉर प्योर प्रोजेक्शन की टैग लाइन के साथ दो नए प्रोजेक्टर मॉडल बाज़ार में उतारे हैं. प्रोजेक्टर मॉडल पीटी-एलबी 1-ईए और पीटी-एलबी 2-ईए प्रोजेक्ट होने वाले मैटर की शुद्धता के मानकों पर पूरी तरह से ख़रे उतरते हैं, यह रोजाना की ज़रूरतों को पूरा करने वाले हैं. बेहतरीन कलर प्रोजेक्शन, पोर्टबिलिटी और विश्वसनीयता पर कंपनी ने विशेष ध्यान दिया है. यह डिजाइन ख़ासतौर पर भारतीय बाज़ार को ध्यान में रखकर बनाया गया है. इसका रंग सफेद है, जो जापान में सायरो के नाम से जाना जाता है. पीटी-एलबी 1-इए और पीटी-एलबी 2-इए की चमक बरकरार रखने के लिए 2200 और 2600 ल्यूमेंस लगे हैं. इन्हें इस तरह निर्मित किया गया है कि ये एशिया में शिक्षा, कारपोरेट, एसओएचओ, गेमिंग और फूड एंड फन आउटलेट पर आसानी से इस्तेमाल किए जा सकें. 2.3 किलोग्राम के उक्त प्रोजेक्टर आसानी से इधर-उधर ले जाने लायक हैं. इनका ऑप्टिकल वेट अल्ट्रा पोर्टेबिलिटी प्रदान करता है.

पैनासोनिक के मार्केटिंग डायरेक्टर मनीष शर्मा के अनुसार, इस नई सीरीज के एलसीडी प्रोजेक्टर इस बात के प्रतीक हैं कि कंपनी ने भारत के संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय टेक्नोलाजी का इस्तेमाल किया है. ख़ास बात यह है कि ये बिना किसी रुकावट के काम करेंगे. अगर वोल्टेज कम-ज़्यादा हो तो भी इनकी फंक्शनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ये प्रोजेक्टर बिजनेस प्रेजेंटेशन या मनोरंजन से संबंधित कार्यक्रमों के प्रस्तुतिकरण में नई जान डाल देंगे. यह इंटरनल कूलिंग सिस्टम की ख़ूबियों से भरपूर हैं, जो इसे लगातार काम के दौरान भी ठंडा रखेगा. इसमें मल्टी प्रोजेक्टर कंट्रोल और मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर लगा है, जिसे सारे पैनासोनिक यूजर्स मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं.

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

डोपिंग टेस्ट में असफल होने के बाद रिचा मिश्रा ने बताया कि उनका पहले कई बार परीक्षण किया जा चुका है, लेकिन कभी भी उनका सैंपल पॉजीटिव नहीं पाया गया.

सरकार और नाडा है डोपिंग का ज़िम्मेदार

आदित्य पूजन

राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारी में हो रही देरी, सुरसा के मुंह की तरह बढ़ते बजट और दूसरे देशों के शीर्ष एथलीटों द्वारा इसमें भाग न लेने की खबरों के बीच भी एक आम भारतीय की उम्मीदें परवान चढ़ रही थीं, वह यह कि कड़ी प्रतियोगिता के अभाव में शायद भारत ज्यादा पदक अपने नाम करने में कामयाब हो जाए. इसकी वजह यह थी कि यदि शीर्ष खिलाड़ी इससे दूर रहे तो अपनी सरजमीं पर आयोजित हो रहे इन खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा हो सकता है, लेकिन एक सप्ताह के भीतर कम से कम नौ खिलाड़ियों के डोपिंग टेस्ट में असफल होने के बाद ये सारी उम्मीदें धराशायी होने लगी हैं. बीती एक सितंबर को चार पहलवानों राजीव तोमर, मौसम खत्री, सुमित और गुरशरणप्रीत कौर के साथ-साथ गोला फेंक खिलाड़ी सौरव विज को डोपिंग टेस्ट में असफल घोषित किए जाने के पांच दिनों बाद ही तीन तैराक रिचा मिश्रा, ज्योत्सना पनसारे और अमर मुरलीधरन भी टेस्ट में फेल रहीं. नतीजतन इन सभी खिलाड़ियों के राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल होने पर रोक लगा दी गई. मुरलीधरन को छोड़ बाकी सभी इन खेलों की विभिन्न स्पर्धाओं में भारतीय टीम का हिस्सा थे, लेकिन सरकार की अकर्मण्यता और नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी (नाडा) के गैर जिम्मेदार रवैये के चलते अब ये खिलाड़ी राष्ट्रमंडल खेलों में शरीक नहीं हो पाएंगे. खेल की शुरुआत से ठीक पहले इस मामले के प्रकाश में आने से भारत की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है. साथ ही इन खिलाड़ियों के भाग न लेने से इन खेलों में भारत की संभावनाओं पर असर पड़ने से भी इंकार नहीं किया जा सकता. इसके अलावा इस प्रकरण से एक सवाल यह भी पैदा होता है कि आखिर डोपिंग का यह भूत भारत को बार-बार अपनी आगोश में क्यों लेता है?

120 किलोग्राम वर्ग की कुश्ती स्पर्धा के लिए टीम में शामिल किए गए राजीव तोमर ओलंपिक खेलों में शिरकत कर चुके हैं. इसी साल 29 अगस्त को उन्हें राष्ट्रपति द्वारा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, लेकिन इसके तीन दिनों बाद ही उन्हें डोपिंग टेस्ट में दोषी करार दिया गया. इसी तरह रिचा मिश्रा महिला तैराकी की नेशनल चैंपियन हैं. इस साल हुई नेशनल एक्वेटिक चैंपियनशिप में उन्होंने तीन स्वर्ण पदक जीते थे, लेकिन रिचा भी डोपिंग की बाधा पार नहीं कर पाईं. मौसम खत्री 96 और सुमित 74 किलोग्राम वर्ग में भारतीय टीम में शामिल थे, जबकि महिला पहलवान गुरशरणप्रीत कौर 72 किलोग्राम वर्ग स्पर्धा के लिए टीम का हिस्सा थीं. इनमें से अधिकांश खिलाड़ी ऐसे हैं, जिन्हें राष्ट्रमंडल खेलों में पदक का दावेदार माना जा रहा था. इन सभी को एक ही प्रतिबंधित दवा मिथाइल हेक्सामाइन के सेवन का दोषी पाया गया, जो खिलाड़ियों द्वारा डाइट सप्लीमेंट के रूप में इस्तेमाल की जाती है. गौरतलब है कि मिथाइल हेक्सामाइन को एक जनवरी, 2010 को वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी (वाडा) द्वारा प्रतिबंधित दवाओं की श्रेणी में शामिल किया गया, लेकिन नाडा ने इसकी सूचना न तो खिलाड़ियों को दी, न ही कोचों और खेलसंघों को. अब आलम यह है कि देश का गौरव बढ़ाने के लिए खून-पसीना बहा रहे ये खिलाड़ी इस प्रतिष्ठित खेल आयोजन से बाहर रहने को मजबूर हैं. इनकी अनुपस्थिति इन खेलों में भारत की पदक तालिका पर असर डाल सकती है, लेकिन इससे बड़ा सवाल यह है कि अनिश्चय के भंवर में गोते खा रहे इन खिलाड़ियों के भविष्य के लिए जिम्मेदार कौन है?

खेल मंत्री एमएस गिल भले अब यह बयान दे रहे हों कि डोपिंग को लेकर सरकार संजीदा है, लेकिन सच्चाई यही है कि उनके नाकारा अधिकारियों और गैर जिम्मेदार कोचों के चलते भारत को बार-बार शर्मसार होना पड़ता है. पिछले एक दशक में न जाने कितनी बार डोपिंग के दंश से भारतीय खेल जगत आहत हुआ है. पिछले साल छह भारोत्तोलकों के डोपिंग टेस्ट में पकड़े जाने के बाद भारतीय भारोत्तोलन संघ पर 50 हजार डॉलर का जुर्माना आरोपित किया गया था, लेकिन खेल अधिकारियों और सरकार के निराशावादी रवैये के चलते इस पर फिर भी लगाम नहीं कसी जा सकी. सच तो यह है कि अधिकांश खिलाड़ियों को प्रतिबंधित दवाओं के बारे में पूरी जानकारी ही नहीं होती. वे अपने कोच के दिशानिर्देश के अनुरूप काम करते हैं, लेकिन भारतीय खेलों के साथ समस्या यह है कि देश में स्तरीय कोच ही उपलब्ध नहीं हैं. अधिकांश कोच ऐसे हैं, जिनके पास कोचिंग का कोई प्रशिक्षण नहीं है. वे कोचिंग के घिसे-पिटे और पुराने तरीके अख्तियार करते हैं, जिसका खामियाजा खिलाड़ियों को भुगतना पड़ता है.

डोपिंग टेस्ट में असफल होने के बाद रिचा मिश्रा ने बताया कि उनका पहले कई बार परीक्षण किया जा चुका है, लेकिन कभी भी उनका सैंपल पॉजीटिव नहीं पाया गया. पहलवान राजीव तोमर के साथ रिचा ने भी मांग की कि उनके नमूनों को किसी विदेशी लेबोरेटरी में भेजकर दोबारा परीक्षण कराया जाना चाहिए, लेकिन खेल अधिकारियों ने इससे इंकार कर दिया. उनका दावा है कि देश में मौजूद परीक्षण केंद्रों की विश्वसनीयता पर कोई सवाल नहीं खड़े किए जा सकते. कई बार ऐसी खबरें आई हैं, जिनमें यह बताया गया है कि कोच ही खिलाड़ियों को प्रतिबंधित दवाओं के सेवन के लिए प्रेरित करते हैं. ऐसे खिलाड़ी जूनियर स्तर पर तो किसी तरह बच निकलते हैं, लेकिन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनकी गलती पकड़ में आ जाती है. सरकार को इन सब बातों की पूरी जानकारी है, लेकिन वह इस ओर कोई ध्यान नहीं देती. देश के खेल प्रशासकों का हाल कुछ ऐसा है कि खेल और खिलाड़ियों की भलाई से ज्यादा उन्हें अपनी भलाई की चिंता रहती है. लेकिन ऐसा कब तक चलता रहेगा? कब तक भारतीय खिलाड़ी अधिकारियों के गैर जिम्मेदार रवैये का शिकार होते रहेंगे और सरकार कब चेतेगी? अब वह समय आ चुका है कि डोपिंग से बचाव के लिए खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ को उचित प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाए. साथ ही प्रतिबंधित दवाओं से संबंधित सारी जानकारी उन्हें मुहैया कराई जाए. देश में नमूनों की जांच के लिए स्तरीय प्रयोगशालाएं बनाई जाएं, ताकि खिलाड़ियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो. इसके बाद भी यदि कोई खिलाड़ी इन दवाओं के सेवन के आरोप में पकड़ा जाता है तो सरकार को चाहिए कि उसे तत्काल आजीवन प्रतिबंधित कर दे. जब ऐसा होगा, तभी भारतीय खेल और खिलाड़ियों की अस्मिता बरकरार रहेगी.

aditya@chauthiduniya.com

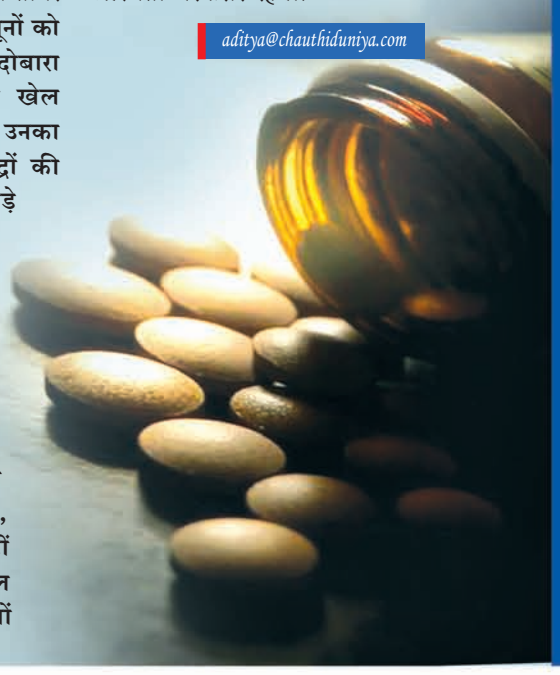

e देश का पहला इंटरनेट टीवी

तीन महीने में रचा इतिहास

- हिन्दी की सबसे पॉपुलर वेबसाइट
- हर महीने 12,00,000 से ज़्यादा पाठक
- हर दिन 40,000 से ज़्यादा पाठक
- स्पेशल प्रोग्राम-भारत का राजनीतिक इतिहास
- समाचार-राजनीति, खेल, पर्यावरण, मनोरंजन
- संगीत और फ़िल्मों पर विशेष कार्यक्रम
- साई की महिमा

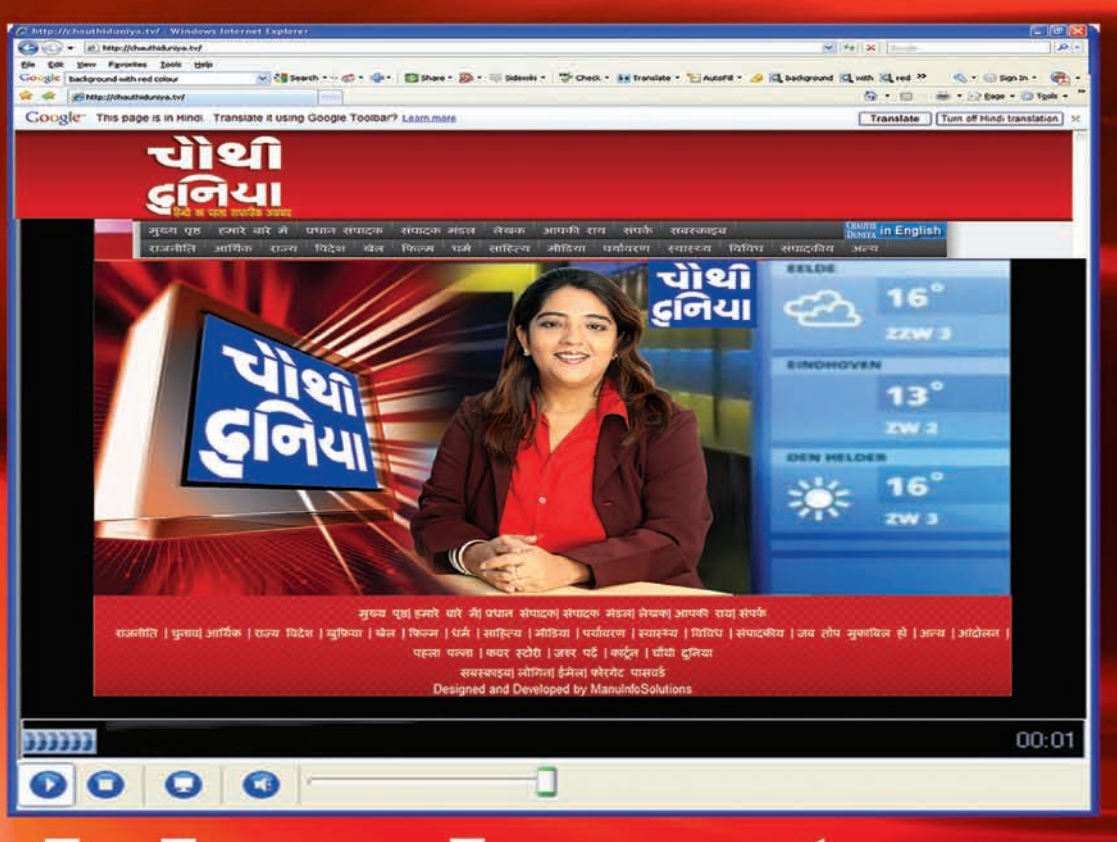

www.chauthiduniya.tv

एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. 45843/86

चौथी दुनिया

दिल्ली, 20 सितंबर–26 सितंबर 2010

अपनी सिफ़ारिशों में समिति ने मुख्य रूप से थिएटर्स में कैमरा एवं अन्य कैप्चर डिवाइसेज ले जाने से संबंधित नियमों को कड़ा बनाने की बात कही है.

फिल्म पाइरेसी एक बड़ी समस्या

सचिव एवं अध्यक्ष उदय वर्मा ने अपनी रिपोर्ट सूचना और प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी को सौंप दी है. समिति ने लगातार बढ़ रही पाइरेसी के कारणों का पता लगाने और उस पर शोध करने के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार की है. रिपोर्ट में पाइरेसी रोकने के लिए आवश्यक नियमों और उत्तरदायी तत्वों का भी उल्लेख किया गया है. अपनी सिफ़ारिशों में समिति ने मुख्य रूप से थिएटर्स में कैमरा एवं अन्य कैप्चर डिवाइसेज ले जाने से संबंधित नियमों को कड़ा बनाने की बात कही है. साथ ही समिति ने सिफ़ारिश की है कि ऐसे उपाय किए जाने चाहिए, जिनसे पाइरेसी का धंधा महंगा हो जाए, इससे ख़ुद-बख़ुद पाइरेटेड सीडी के दाम बढ़ेंगे और ख़रीददार हतोत्साहित होंगे. समिति की प्रमुख सिफ़ारिशें इस प्रकार हैं-फिल्मों के प्रदर्शन के दौरान सिनेमाहॉलों से पाइरेसी रोकने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से थिएटर एवं मल्टीप्लेक्स संचालकों पर होनी चाहिए. समिति का मानना है कि इन शर्तों को थिएटरों और मल्टीप्लेक्सों को लाइसेंस दिए जाने के समय एग्रीमेंट में शामिल किया जाना चाहिए. इसके अलावा समिति ने सिफ़ारिश की है कि छोटे कस्बों में लेखकों, वितरकों, निर्माताओं एवं थिएटर-मल्टीप्लेक्स संचालकों को एकजुट करके इस समस्या का समाधान खोजा जाना चाहिए. साथ ही पारंपरिक थिएटरों को डिजिटल थिएटरों में बदलने एवं सही डीवीडी जारी करने की भी ज़रूरत है.

priyanka @chauthiduniya.com

प्रियंका प्रियम तिवारी

भारत ऑनलाइन फिल्म पाइरेसी का एक बड़ा अड्डा है. यहां ग़ैरक़ानूनी डाउन लोडिंग करने में देश की राजधानी दिल्ली, वित्तीय केंद्र मुंबई और आईटी हब बेंगलुरू सबसे आगे हैं. भारत में मोशन पिक्चर डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन द्वारा प्रमाणित इंटरनेट पाइरेसी रिपोर्ट के अनुसार, भारत में ब्रॉडबैंड नेटवर्क सब्सक्राइबर की संख्या पर ग़ौर करें तो यहां सबसे ज़्यादा फिल्म पाइरेसी होती है. फिल्म डाउनलोडिंग में अमेरिका पहले नंबर पर है, जबकि ब्रिटेन और कनाडा के बाद भारत पूरे विश्व में चौथे नंबर पर है. विशाल भारद्वाज की कमीने बिट्टॉरेंट सॉफ्टवेयर से 3,50,000 बार डाउनलोड हुई है. इसमें एक तिहाई बार भारत में ही डाउनलोड हुई. इस साल अप्रैल से सितंबर तक की अवधि में भारत ग़ैरक़ानूनी पी2पी एक्टिविटी में विश्व में दसवें स्थान पर रहा है. इंटरनेट कंपनी एनविजनल की इंटरनेट पाइरेसी लैंडस्केप रिपोर्ट के अनुसार, भारत में ऑनलाइन पाइरेसी बिट्टॉरेंट व साइबरलॉकर और वेब आधारित फाइल होस्ट जैसे रैपिडशेयर या हॉटफाइल जैसे फाइल शेयरिंग नेटवर्क से होता है. वीडियो स्ट्रीमिंग साइट भी ख़ूब प्रचलित हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल बिट्टॉरेंट और सायबरलॉकर्स से कम होता है. वीडियो स्ट्रीमिंग साइट हैं यूट्यूब, जस्ट इन डॉट टीवी, यूस्ट्रीम डॉट टीवी. 2008 में आई एर्नस्ट एंड यंग की रिपोर्ट के अनुसार, जालसाज़ी और और पाइरेसी से इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को 16,000 करोड़ रुपये का नुक़सान प्रतिवर्ष होता है. भारत में मीडिया और इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भविष्य में काफ़ी फलने-फूलने वाला क्षेत्र है. यह प्रतिवर्ष ग्यारह बिलियन डॉलर की कमाई करता है और इसमें प्रतिवर्ष अट्ठारह प्रतिशत की वृद्धि होती है. अगर पाइरेसी को रोक दिया जाए तो इसमें भारी इज़ाफ़ा होने की संभावना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कमाई हो सकती है. इस पर नज़र रखते हुए हाल ही में पाइरेसी पर गठित समिति के विशेष

त्रिशा की उदासी

ऐसा लगता है कि बॉलीवुड की हीरोइनों और विवादों का चोली-दामन का साथ है. त्रिशा कृष्णन इन दिनों काफ़ी चर्चा में हैं. वजह उनकी कोई फिल्म नहीं, बल्कि नशीली दवाओं के मामले में उनका नाम आना है. दक्षिण की इस ख़ूबसूरत अभिनेत्री ने कुछ दिनों पहले ही बॉलीवुड में एंट्री ली है. अक्षय कुमार के साथ फिल्म खट्टा मीठा में मुख्य भूमिका अदा कर चुकी त्रिशा पहले भी एक एमएमएस को लेकर विवादों में थीं. त्रिशा की यह फिल्म फ्लॉप गई, उन्हें कुछ ख़ास पब्लिसिटी नहीं मिली. वजह जो भी हो पर त्रिशा आजकल मीडिया की सुर्ख़ियों में हैं. पर त्रिशा इस पब्लिसिटी से बेहद अपसेट हैं. उनके दु:ख की वजह यह है कि इस मामले में उनका नाम आने से उनकी छवि ख़राब हो रही है, जिसका उनके करियर पर भी असर पड़ सकता है.

एक तमिल चैनल पर दिखाई गई ख़बर में सिडनी के एक व्यक्ति, अफ्रीकी मूल के एक डिजाइनर और एक नाइजीरियन ड्रग्स सप्लायर से उनके निकटतम संबंध बताए गए हैं. इस ख़बर पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए त्रिशा ख़ुद को निर्दोष बताती हैं. वह कहती हैं कि जब यह ख़बर आ रही थी, तब वह कोडकनाल में शूटिंग में व्यस्त थीं. ख़बरों में बताया जा रहा था कि उक्त तीनों व्यक्ति उनके निकटतम मित्र हैं, जबकि सच यह है कि वह उन्हें जानती तक नहीं. वह कहती हैं कि उन्हें यह नहीं पता कि कैसे उस ड्रग सप्लायर को उनका नंबर मिला. वैसे भी किसी का नंबर किसी के पास होने से यह साबित नहीं होता कि वह किसी अपराध में लिप्त है. त्रिशा इस ख़बर से आहत हैं. उन्होंने मीडिया पर गुस्सा उतारते हुए कहा कि उक्त चैनल ने यह ख़बर अपनी पब्लिसिटी के लिए क्रिएट किया है. वह उस ख़बरिया चैनल पर क़ानूनी कार्रवाई करने के मूड में भी हैं. जो भी हो, त्रिशा आप कितनी बेगुनाह हैं, यह तो कार्यवाही के बाद पता चलेगा, लेकिन बॉलीवुड में आते ही फिल्म में लीड किरदार करने के बाद ही विवादों में उलझने से आपके करियर पर असर पड़ सकता है.

प्रीव्यू

आक्रोश

फिल्में समाज का आईना होती हैं. जो भी घटनाएं हमारे आसपास घटती हैं, समाज में जो कुछ भी चल रहा होता है, फिल्म निर्माण की दिशा भी उसी के अनुरूप चलती है. समाज में तेजी से फैलती ऑनर किलिंग की प्रवृत्ति पर फिल्म आक्रोश का निर्माण हुआ है. बिग स्क्रीन इंटरटेनमेंट और जी मोशन के बैनर तले बनी इस फिल्म के प्रोड्यूसर कुमार मंगत हैं. फिल्म का निर्देशन प्रियदर्शन ने किया है, जबकि संगीत इरशाद कामली ने दिया है. फिल्म के मुख्य कलाकार हैं अजय देवगन, अक्षय खन्ना, बिपाशा बसु, परेश रावल, राइमा सेन, अमिता पाठक और उर्वशी शर्मा.

यह एक्शन थ्रिलर फिल्म ऑनर किलिंग यानी इज़्ज़त के नाम पर हत्या विषय पर आधारित है. तथ्यों के अनुसार, भारत में हर साल इज़्ज़त के नाम पर तीन हज़ार हत्याएं होती हैं. यह फिल्म ऑनर किलिंग के लगातार बढ़ते मामलों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाती है.

फिल्म का टाइटल इस तथ्य से प्रेरित है कि आक्रोश की असली आवाज़ सन्नाटे में दबी होती है. वह सन्नाटा किसी भी अपराध या घुटन का हो सकता है. आदिवासियों पर होने वाले अत्याचारों पर बनी इस पूरी फिल्म में ओमपुरी लहानिया भीखू के रोल में हैं, जो चुप ही रहता है, लेकिन उसके हावभाव उसके आक्रोश को ख़ुद ही अभिव्यक्त करते हैं. लहानिया भीखू पर उसकी पत्नी की हत्या का इल्जाम लगाया जाता है. भास्कर कुलकर्णी यानी नसीरुद्दीन शाह को उसका सरकारी वकील बनाया जाता है. कुलकर्णी वकालत के पेशे में नए हैं. उनका यह पहला केस है, इसलिए वह

ख़ुद काफ़ी डरे हुए होते हैं. दूसरी ओर समाज के दुर्व्यवहार से दु:खी लहानिया अपनी पत्नी की हत्या के बारे में कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है. कुलकर्णी जब भी लहानिया के सामने आते हैं, वह ख़ामोश हो जाता है. धीरे-धीरे कुलकर्णी इस केस में रुचि लेने लगते हैं. उन्हें लगने लगता है कि लहानिया ने हत्या की ही नहीं है. एक्शन-थ्रिल से भरपूर इस फिल्म में अजय देवगन और अक्षय खन्ना दोनों ही सीबीआई अफसर की भूमिका निभा रहे हैं, जो ऑनर किलिंग के बढ़ते मामलों की तह में जाकर उनका पर्दाफ़ाश करते हैं. लंबे समय से स्क्रीन से गायब अक्षय खन्ना इस फिल्म में एक सशक्त भूमिका में नज़र आएंगे. यह फिल्म आगामी एक अक्टूबर को रिलीज होगी.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

बिहार झारखंड

दिल्ली, 20 सितंबर–26 सितंबर 2010 www.chauthiduniya.com

पैसा दो टिकट लो

सरोज सिंह

इसे सत्ता पाने का जुनून कह लीजिए या फिर पैसे की ताक़त का एहसास कराने का घमंड. चुनावी टिकट के लिए पिछले दिनों पटना में धन्नासेठों ने अपनी थैलियां खोल दीं. पिछले चुनावों में जब इस तरह के एक–दो किस्से सामने आए तो लोगों ने इसे सुनी–सुनाई बात बता गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन इस बार तो कहानी ही दूसरी है. दल छोटा हो या बड़ा, चुनावी टिकट के लिए धनपति कोई भी क़ीमत देने को तैयार दिखे. हालांकि इसका पूरा फ़ायदा टिकट के दलालों ने उठाया और कुछ खास इलाक़ों के टिकटों के दाम तो करोड़ों में पहुंच गए. इस चैनल से कुछ धन्नासेठ तो टिकट का सुख पा गए, पर कुछ को निराश होना पड़ा, क्योंकि उनकी बोली कम पड़ गई या फिर क़िस्मत ने उनका साथ नहीं दिया. टिकट में पैसे के इस कथित खेल का खामियाजा ज़मीन से जुड़े उन नेताओं को भुगतना पड़ा, जो खाली हाथ महीनों से पार्टी कार्यालय के चक्कर लगाते रहे, लेकिन टिकट कोई धनकुबेर ले उड़ा.

चुनाव में धनबल का प्रभाव हमेशा महसूस किया जाता रहा है, पर इस बार तो लगता है कि कुछ धन्नासेठों ने ठान ही लिया था कि उन्हें चुनाव का टिकट चाहिए, चाहे कोई भी क़ीमत क्यों न अदा करनी पड़े. धनपतियों की जिद के कारण ही इस बार टिकटों के दाम आसमान छूने लगे. दो धनपतियों की लड़ाई में पटना ज़िले की एक खास विधानसभा सीट का टिकट रेट करोड़ में चला गया. इसी तरह जमुई ज़िले की भी एक सीट के लिए पचास लाख रुपये तक की बोली लगी. वैशाली एवं किशनगंज की भी कुछ सीटों का रेट 25 लाख रुपये से ऊपर चला गया. आरा और सीतामढ़ी की भी एक–एक सीट पर पैसे का जोर है. हद तो यह हुई कि पहली बार सुरक्षित विधानसभा सीटों के लिए भी पैसा खर्च करने वाले पटना में घूमते मिले. ऐसे कुछ लोगों से बात करने पर पता चला कि वे पार्टी फंड में सहयोग करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते उन्हें टिकट दिया जाए. ऐसे लोग कई दलों में अपना प्रस्ताव लेकर घूमते नज़र आए. उनसे बात करने पर पता चला कि आलाकमान तक सीधी पहुंच न होने के कारण वे बिचौलियों का सहारा लेते हैं. पार्टी कार्यालयों में ऐसे कई बिचौलिए इस चुनावी मौसम में अपना बाज़ार लगाए दिखे. इन बिचौलियों द्वारा धनपतियों को यह आश्वासन दिया जाता है कि टिकट हर हाल में आपको ही मिलेगा, पर आपको अपनी थैली खोलनी होगी. दूसरी भाषा में कहें तो टिकट के ये दलाल इन धन्नासेठों से यह कहते हैं कि पार्टी फंड में आपको सहयोग करना पड़ेगा, तब हम आगे बात करेंगे. यह प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक अच्छी–खासी रक़म पहले ही ले ली जाती है. उसके बाद ये दलाल अपना काम शुरू करते हैं. ये लोग ऐसे लोगों से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, जो पार्टी के शीर्ष नेताओं के क़रीबी होते हैं. कभी जाति तो कभी रिश्ते का वास्ता देकर ये दलाल पहले कोशिश करते हैं कि बिना पैसा दिए ही टिकट की बात कर ली जाए और धन्नासेठों से मिला पैसा ख़ुद रख लिया जाए, लेकिन जब इन दलालों को लगता है कि नेताओं के क़रीबियों को बिना पैसा खिलाए बात नहीं बनेगी तो वे इस लाइन पर भी बात कर लेते हैं, मगर रक़म काफी कम बताई जाती है. टिकट के दलाल नेताओं के क़रीबियों को यह बताते हैं कि अगर आप हमारे उम्मीदवार को टिकट देंगे तो आपको पार्टी की तरफ से पैसे की मदद नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि पैसे के मामले में मेरा उम्मीदवार ख़ुद सक्षम है. हमें बताया गया कि पार्टी के आला नेताओं को इस तर्क के आधार पर मनाने में आसानी होती है कि अमुक प्रत्याशी के पीछे पार्टी को पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा. कई दौर की बातचीत के बाद जब लगता है कि नेताजी मान जाएंगे, तब धनपति प्रत्याशी को नेताजी से मिलवाया जाता है. मुलाकात के दौरान नेताजी ने धनपति प्रत्याशी से अगर कह दिया कि जाइए तैयारी कीजिए, तो यह मान लिया जाता है कि टिकट पक्का हो गया. उसके बाद टिकट के दलाल प्रत्याशी से तय की गई पूरी रक़म ले लेते हैं. टिकट के एक ऐसे ही दलाल ने बताया कि सारा कुछ चांस वाली बात है. कभी बात बन जाती है तो कभी नहीं बनती. हम लोग कोशिश करते हैं कि बाहर से आए ऐसे अमीर नेताओं को टिकट दिला दें, पर अंतिम फ़ैसला तो प्रत्याशी के भाग्य पर निर्भर करता है. यह मान कर चलिए कि हम प्रत्याशी को टिकट दिलाने के लिए सर्विस चार्ज लेते हैं. यह अलग बात है कि इस बार सर्विस चार्ज ज़्यादा है. इस दलाल ने बताया कि चुनाव के मौसम में यह पूरी गाड़ी भरोसे के पेट्रोल पर चलती है. अमीर टिकटार्थी हम पर भरोसा करते हैं और हम आगे के नेताओं पर भरोसा करते हैं. ज़रूरी नहीं कि सबको टिकट मिल ही जाता है, पर कुछ की लॉटरी तो निकल आती है. एक अन्य दलाल ने बताया कि हम लोगों का काम तो केवल प्रत्याशी की फरियाद सही जगह तक पहुंचाना है. बाकी काम तो इलाक़े का जातीय समीकरण, प्रत्याशी की क्षेत्र में छवि और उस क्षेत्र के दूसरे उम्मीदवारों की ताक़त पर निर्भर करता है. अगर सारा कुछ निशाने पर बैठ जाता है तो प्रत्याशी को टिकट मिल जाता है. यह अलग बात है कि प्रत्याशी टिकट मिलने का सारा श्रेय हम लोगों को देते हैं और टिकट के बदले तय रक़म देकर क्षेत्र चले जाते हैं. मतलब प्रत्याशी को टिकट से मतलब होता है और दलाल को पैसे से.

टिकट के लिए पैसे के खेल ने राजनेताओं को परेशान कर दिया है. राजद सांसद रामकृपाल यादव कहते हैं कि सत्ता के कुछ दलालों ने माहौल गंदा कर दिया है. उन्होंने बताया कि राजद को इस बीमारी से दूर रखा गया है और ज़मीन से जुड़े नेताओं एवं पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ताओं को ही टिकट दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि टिकट के आवेदन देने के लिए भी एक पैसा नहीं लिया गया.

टिकट के लिए पैसे के खेल ने राजनेताओं को परेशान कर दिया है. राजद सांसद रामकृपाल यादव कहते हैं कि सत्ता के कुछ दलालों ने माहौल गंदा कर दिया है. उन्होंने बताया कि राजद को इस बीमारी से दूर रखा गया है और ज़मीन से जुड़े नेताओं एवं पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ताओं को ही टिकट दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि टिकट के आवेदन देने के लिए भी एक पैसा नहीं लिया गया. लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस कहते हैं कि टिकटार्थियों को टिकट के दलालों से बचना चाहिए. लोजपा में टिकट के लिए पैसा नहीं, बल्कि उम्मीदवारों की योग्यता देखी जाती है. पारस ने कहा कि लोजपा ने पार्टी के प्रति समर्पित नेताओं का पूरा सम्मान कर उन्हें टिकट देने में प्राथमिकता दी है. लोजपा धनबल पर नहीं, जनबल पर भरोसा करती है. भाजपा के मीडिया प्रभारी संजय मयूख भी मानते हैं कि हर बार चुनाव के समय कुछ ऐसे लोग सक्रिय हो जाते हैं, जो कोशिश करते हैं कि पैसे की ताक़त से नेताओं का ईमान डिगा दिया जाए, पर भाजपा में ऐसे लोग हमेशा दुत्कारे गए हैं. भाजपा में टिकट वितरण की एक पूरी पारदर्शी प्रकिया है और हर बार की तरह इस बार भी सभी मापदंडों का पालन किया जा रहा है. राजनीति में धन के बढ़ते प्रभाव पर चिंता जताते हुए मयूख ने कहा कि सभी दलों को इस तरह की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करना चाहिए, ताकि ज़मीन से जुड़े एवं ईमानदार लोग राजनीति में आगे आ सकें. जदयू नेता सतीश यादव का कहना है कि टिकट के लिए पैसे की बात बकवास है. अगर ऐसा होता तो मेरे जैसा ग़रीब आदमी राबड़ी देवी के ख़िलाफ़ चुनाव नहीं लड़ पाता. यादव कहते हैं, हो सकता है कि कुछ पैसे वाले चाहते हों कि पैसे की ताक़त पर टिकट हथिया लिया जाए, पर जदयू में उनकी दाल न कभी गली और न आगे कभी गलेगी. कांग्रेस प्रवक्ता प्रेमचंद मिश्र का भी कहना है कि कांग्रेस हमेशा साफ़–सुथरी राजनीति की पक्षधर रही है, इसलिए हमारे यहां हमेशा पैसे वाले निराश होते रहे हैं.

लगभग सभी दलों की राय है कि राजनीति में पैसे का खेल ग़लत है और हर हाल में यह नहीं होना चाहिए, लेकिन पिछली बार की तुलना में इस बार इसका ज़ोर ज़्यादा दिखा. भले ही कुछ सीटों के लिए यह खेल खेला गया, भले ही पार्टी के शीर्ष नेताओं को अंधकार में रखा गया हो, पर पैसे की ताक़त ने ज़मीन से जुड़े कुछ नेताओं के सपनों को तो तोड़ ही दिया. अब इन्हें पांच साल और इंतजार करना पड़ेगा, पर यह ज़रूरी नहीं कि अगली बार इन्हें टिकट मिल ही जाए. क्योंकि हो न हो, 2015 में टिकट के दलालों का ग्राफ और ऊपर चला जाए और ये एक बार फिर मुंह ताकते रह जाएं.

feedback@chauthiduniya.com

दियारे में लोग बाढ़ के पानी से तबाह हैं तो शेष भाग सूखे के कारण हलकान हैं. कुल मिलाकर सारण प्रमंडल के तीनों ज़िलों के किसान प्रकृति के इस सुखाड़-दाहड़ की लीला से परेशान हैं.

हम बस एक सिपाही की तरह काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. इधर कई विरोधी दल नागेंद्र चंद्रवंशी के अगले क़दम के इंतजार में बैठे हैं.

चुनावी तड़का

विधायक जी नहीं बोल सकते क्या!

राहुल की सभा में उत्तर बिहार के कई ज़िलों के कांग्रेसी नेता एवं टिकटार्थी पूरे दल-बल के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे थे. सभा आयोजन के 24 घंटे पूर्व से ही समस्तीपुर शहर के सभी आवासीय होटल एवं रेस्ट हाउस कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं से फुल हो चुके थे. आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट की आस लगाए स्थानीय एवं दूसरे ज़िलों से आए दावेदारों ने शहर की मुख्य सड़कों को कांग्रेस समर्थित नारों एवं राहुल-सोनिया की तस्वीर वाले लैक्स और होर्डिंग से पाट दिया था. युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर था और राहुल ने यह कहकर उन्हें और ज़्यादा उत्साहित कर दिया कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी अधिक से अधिक युवाओं को चुनाव लड़ने का मौक़ा देगी. फिर क्या था, सभा ख़त्म होते ही कई युवा नेता अपने को भावी विधायक समझने लगे और उनका व्यवहार भी अचानक बदल गया. ऐसे ही एक नेता से जब होटल वाले ने पूछा कि अब रूम छोड़ना है क्या? बस इसी बात से उस नेता का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया. उसने होटल मैनेजर से कहा, नेताजी किसको बोलते हो, विधायक जी नहीं बोल सकते! इतना सुनते ही होटल मैनेजर के साथ नेताजी के समर्थक भी हक्का-बक्का रह गए.

इस बार ख़ुद के लिए क़ुर्बानी देंगे

राजद नेता एवं पूर्व विधायक शंकर प्रसाद टेकरीवाल के इशारे पर अपने राजनीतिक जीवन को होम करने वाले पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष एवं वरीय वैश्य नेता श्याम सुंदर साह को इस बार भी पार्टी के लिए क़ुर्बानी देनी पड़ सकती है, लेकिन राजद नेता साह इस बार किसी भी क़ीमत पर चुनाव लड़ेंगे और इस बार वह क़ुर्बानी पार्टी के लिए नहीं, बल्कि अपनी राजनीतिक सक्रियता बरक़रार रखने के लिए देंगे. उनका दावा है कि महसी विधानसभा सीट से अगर निर्दलीय भी चुनाव लड़ेंगे तो किसी दलीय उम्मीदवार से ज़्यादा ठसकदार साबित होंगे. साह मानते हैं कि उनको अपनों से दगा मिला, पर इससे वह सबक़ ज़रूर सीख गए हैं. अब तो मैदान में कूदना है, चाहे जो भी क़ीमत चुकानी पड़े.

दिल है कि मानता नहीं

राजनेता अपनी सुविधा के अनुसार आसानी से नियमों को बदल देते हैं. कोसी में जब बाढ़ आई तो नेताओं ने यह कहकर उस साल इफ्तार की दावत नहीं दी कि यह दुःख की घड़ी है. लोगों को भी लगा कि चलो नेताओं में इतनी संवेदना तो जगी, लेकिन इस बार तो इफ्तार पार्टियों की बाढ़ सी आ गई है. ऐसा होना लाज़िमी भी है. चुनाव का मौसम है और ऐसे में कोई मुसलमान भाइयों की सहानुभूति खोना नहीं चाहता. नीतीश कुमार ने राजगीर में तो लालू प्रसाद, सुशील मोदी एवं राम विलास पासवान ने पटना में शानदार इफ्तार पार्टी का आयोजन किया. ददन पहलवान भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने भी अपने आवास में भारी मजमा जुटाया, लेकिन विरोधियों को तो बस मौक़ा चाहिए. कहते फिर रहे हैं कि बाढ़ के कारण इफ्तार नहीं हुआ, पर आज जब पूरा बिहार सुखाग्रस्त घोषित हो चुका है तो चुनावी फायदे के लिए नेताओं का दिल मान नहीं रहा और इफ्तार की बाढ़ देखने को मिल रही है.

कल के दोस्त आज के दुश्मन

राजनीति में दोस्त कब दुश्मन और दुश्मन कब दोस्त बन जाते हैं, इसका इल्म राजनीतिज्ञों को पहले नहीं रहता है. इल्म जब तक होता है, तब तक विश्वास की डोर टूट चुकी होती है. ठीक इसी तरह का वाक़या परवत्ता विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिल रहा है. कल तक जदयू के रामानंद सिंह की जीत के लिए एड़ी-चोटी एक कर देने वाले जदयू प्रदेश कार्यसमिति सदस्य फुलेश्वर चौरसिया आज उनके ही नंबर वन दुश्मन बन बैठे हैं और उन्हें हराने के लिए अभी से इलाक़े का भ्रमण कर रहे हैं. सूबे के परिवहन मंत्री रामानंद सिंह को फुलेश्वर पटखनी दे पाएंगे या नहीं, यह तो वक्त बताएगा, लेकिन उनका कहना है कि इस बार चौरसिया बिरादरी के लोगों ने जदयू के शीर्ष नेताओं को आवेदन देकर यह स्पष्ट कर दिया है कि इस बार अगर रामानंद सिंह को टिकट दिया गया तो जदयू का बेड़ा इस विधानसभा क्षेत्र में गर्क हो जाएगा. इसलिए वह इस बार इस इलाक़े से टिकट के प्रबल दावेदार माने जाते हैं. बहरहाल फुलेश्वर पार्टी हाईकमान की नज़रें अपनी ओर इनायत कर पाते हैं या नहीं, यह तो आने वाले दिनों में ही स्पष्ट हो सकेगा, लेकिन इतना तय हो गया है कि राजनीति में न कोई किसी का दीर्घकालिक दोस्त होता है और न ही दुश्मन.

लवली की चुप्पी और कांग्रेसियों का दर्द

लवली आनंद की चुप्पी ने कांग्रेसियों की उलझनें बढ़ा दी हैं. वह किस सीट से चुनाव लड़ेंगी, यह साफ़ नहीं हो सका है, जिसके चलते उनके समर्थकों एवं पार्टी के अंदर संशय की स्थिति बनी हुई है. चर्चा है कि वह महिषी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि वह मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र की आलमनगर विधानसभा सीट से भी भाग्य आजमा सकती हैं. इस ऊहापोह में कई कांग्रेसियों के दिलों की धड़कन बढ़ी हुई नज़र आ रही है. राजद के रामकृपाल यादव और ददन पहलवान आदि नेताओं ने आनंद मोहन से जेल में मुलाकात की. सूबे के मुखिया नीतीश कुमार जब उनके घर पंचगछिया गए तो पुराने कांग्रेसियों को लगा कि उनके लिए मैदान साफ़ हो गया है, लेकिन राहुल गांधी के कार्यक्रम से स्पष्ट हो गया कि पूर्व सांसद आनंद मोहन एवं लवली का कांग्रेस में ठहराव हो गया है और अब इस इलाक़े के कांग्रेसियों की कमान इसी दंपत्ति के हाथों में रहेगी.

एयर कंडीशन का बुखार उतर गया

वोट की राजनीति जो न कराए. 24 घंटे एयर कंडीशन में रहने वाले मंत्री जी वोट के लिए सड़कों पर धूल फांकने लगे हैं. वृषिण पटेल लगभग पांच वर्षों तक शिक्षा मंत्री और ग्रामीण कार्यमंत्री के रूप में सत्ता का सुख भोगते रहे. पांच वर्षों तक मंत्री जी एयरकंडीशन बंगला, एयरकंडीशन कार्यालय एवं एयरकंडीशन स्कॉर्पियो गाड़ी से बाहर नहीं निकले. क्षेत्र के लोगों को घंटों इंतजार कराते थे और बात-बात पर शायरी कहकर काम को टाल देते थे. चुनाव का समय नजदीक आया तो मंत्री जी की नींद खुली. नींद खुलने के साथ ही उन्हें वीणा शाही के रूप में ऐसा झटका लगा कि वह चारों खाने चित्त हो गए. अपने ख़िलाफ़ वीणा शाही की उम्मीदवारी की संभावना देख मंत्री जी का एयरकंडीशन वाला बुखार उतर गया. अब नेता जी पटना से अपने चुनाव क्षेत्र वैशाली तो एयरकंडीशन गाड़ी से ही जाते हैं, लेकिन क्षेत्र में पहुंचते ही अपना रंग बदल देते हैं. ग्रामीण कार्यमंत्री वृषिण पटेल अब अपने निर्वाचन क्षेत्र में मोटरसाइकिल से घूमकर लोगों से वोट मांग रहे हैं. मंत्री जी के बदले स्वरूप को देखकर लोग दंग हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

झारखंड

सूबे को पटरी पर लाने की कवायद

जबसे झारखंड का गठन हुआ है, तबसे विकास यहां चर्चा का विषय बना हुआ है. विकास के नाम पर खुलेआम सरकारी रक़म की बंदरबांट होती है. राजनेताओं, नौकरशाहों, ठेकेदारों और बिचौलियों की चौकड़ी पर विकास राशियों के बंदरबांट के आरोप अक्सर लगते रहे हैं.

के शंकरनारायणन | एमओएच फारुक | सैय्यद सिब्ते रजी

सूबे के विभिन्न विभागों में घपलों और घोटालों की ख़बरें अक्सर उजागर होती रहती हैं. इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि दस वर्षों के दौरान एक भी चुनी हुई सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई. आयाराम-गयाराम की तर्ज पर लोकतांत्रिक सरकारों का कार्यकाल रहा. इस बीच विकास के मुद्दे गुम होते चले गए और अवसरवादी राजनीति परवान चढ़ती गई. नतीजतन अलग राज्य का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका.

अस्थिर और अस्थायी सरकारें स्वार्थपरक राजनीति के तहत येन-केन प्रकारेण सत्ता पर काबिज रहने की जुगत भिड़ाने में ही जुटी रही. सर्वांगीण विकास और सूबे को पटरी पर लाने की दिशा में कोई कारगर क़दम नहीं उठाया गया. नौकरशाह विधायिका पर हावी रहे. राजस्व लूट के मामले में झारखंड की चर्चा देश में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी हो रही है. ग़ौरतलब है कि झारखंड में उतना विकास नहीं हो सका, जितना छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में हुआ, जबकि तीनों राज्यों का गठन एक साथ ही हुआ था. मतलब यह कि झारखंड में विकास की गति इन दोनों राज्यों की अपेक्षा मंद है. फिलहाल दोनों राज्य कई मायनों में झारखंड से काफी आगे हैं, जबकि झारखंड सिर्फ़ खनिज संपदा में अव्वल है.

यहां गठबंधन की सरकारें बनती-बिगड़ती रहीं. राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की नीतियों और सिद्धांतों को दरकिनार कर क्षेत्रीय दलों ने सत्ता पर मजबूत पकड़ बना ली, पर गठबंधन की सरकार यहां टिक नहीं पाई. नतीजतन सूबे को तीसरी बार राष्ट्रपति शासन से रूबरू होना पड़ा. आंकड़े बताते हैं कि जो कार्य चुनी हुई सरकारों के कार्यकाल में नहीं हो पाया, वह कार्य राष्ट्रपति शासन में संभव हो पा रहा है. राज्यभवन के निर्देश पर नौकरशाह विकास को गति देने में जुटे हैं. कई लंबित पड़ी महत्वाकांक्षी योजनाओं को मूर्त रूप दिया जा रहा है. अगर पूर्व में लगे राष्ट्रपति शासनों पर गौर करें तो पूर्व राज्यपाल सैय्यद सिब्ते रजी और पूर्व राज्यपाल के शंकर नारायणन के कार्यकाल में झारखंड को पटरी पर लाने की दिशा में कई उल्लेखनीय कार्य किए गए, जो मील के पत्थर साबित हुए. कई कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने में भी सफलता मिली, लेकिन चुनी हुई सरकारों के कार्यकाल में उक्त सारी परियोजनाएं ठंडे बस्ते में चली गई थीं.

फिलहाल राज्यपाल एमओएच फारुक तीन माह पूरे कर चुके हैं. इस दौरान नौकरशाहों की कार्यशैली में काफी बदलाव नज़र आने लगा है. कभी बेलगाम कहे जाने वाले नौकरशाह अब नियंत्रित नज़र आ रहे हैं. सरकारी योजनाओं को अमलीजामा पहनाने में भी तेज़ी आई है. विधि व्यवस्था, भ्रष्टाचार, उग्रवादी गतिविधियां और विकास योजनाओं सहित कई मामलों में अपेक्षित सुधार नज़र आ रहा है. हाल में राज्यपाल ने महत्वपूर्ण नीतियां बनाने और उसे ज़मीन पर उतारने की दिशा में क़दम बढ़ाया है. इसके तहत भूमि अधिग्रहण नीति में सुधार कर इसे और अधिक लचीला बनाने का निर्णय लिया गया है. जल्द ही नई भूमि अधिग्रहण नीति घोषित होने की संभावना है. ग़ौरतलब है कि झारखंड में औद्योगिक विकास की सबसे बड़ी बाधा भूमि अधिग्रहण की रही है. सूबे में इस वजह से पिछले दस वर्षों में एक भी उद्योग नहीं लग पाया. कई छोटी-बड़ी विकास योजनाएं शुरू नहीं हो पाई हैं. नए स्कूल-कॉलेज और तकनीकी संस्थान नहीं खुले. नई भूमि अधिग्रहण नीति से एक ओर राज्य में विकास योजनाएं गति पकड़ेंगी, वहीं दूसरी ओर भू-स्वामियों को ज़मीन का उचित मुआवजा मिलेगा. यही नहीं, प्रस्तावित नीति के तहत ज़मीन का बाज़ार मूल्य भी ज़मीन मालिकों को मिलेगा. यह राष्ट्रपति शासन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी.

झारखंड में जन वितरण प्रणाली को दुरुस्त करने, खाद्यान्नों की कालाबाजारी रोकने, बीपीएल परिवारों को सुविधाएं देने और गरीबों के बीच अनाज वितरण सुनिश्चित कराने की दिशा में ठोस क़दम उठाए जा रहे हैं. राज्यपाल के सलाहकार सूबे में ध्वस्त हो चुकी व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कारगर उपाय तलाशने में जुटे हैं. राष्ट्रपति शासन के दौरान कई ऐसे घपलों-घोटालों के आरोपी गिरफ्त में आए, जो वर्षों से सरकारी खजाने को लूटकर अपनी तिजोरी भरने में लगे थे. निगरानी, सीबीआई एवं अन्य जांच एजेंसियों के कामों में भी गति आई है. फिलहाल राज्य में सूखे की मार से किसान त्रस्त हैं. राज्यपाल एमओएच फारुक ने प्रधानमंत्री, वित्तमंत्री और गृहमंत्री से झारखंड को तत्काल आर्थिक सहायता देने की मांग की है. राज्यपाल ने सूखा राहत कार्यों के लिए 35 सौ करोड़ रुपये आवंटित करने का अनुरोध किया है. राज्य में वैकल्पिक खेती, जलापूर्ति, खाद्यान्न सुरक्षा, मनरेगा और पीडीएस आदि में सुधार और केंद्र प्रायोजित विकास योजनाओं की निगरानी के लिए विशेष दिशानिर्देश दिए गए हैं. बहरहाल सूबे में सरकार गठन की संभावना बहुत कम है. ऐसे में चुनाव ही एकमात्र विकल्प माना जा रहा है, लेकिन राष्ट्रपति शासन के दौरान विकास कार्य जिस तरह गति पकड़ रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि बेपटरी हुए झारखंड को पटरी पर लाने के लिए राष्ट्रपति शासन ही बेहतर है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

अति पिछड़ों की नाराज़गी भारी पड़ सकती है

चुनावी वर्ष में कोई भी राजनीतिक दल विवादों में नहीं फंसना चाहता है. वैसे भी अगर कोई दल विवाद में फंसा तो समझो उसका बेड़ा गर्क. हमेशा विवादों में रहने वाले रोहतास ज़िला जदयू में एक बार फिर घमासान छिड़ी है. यह तूफान प्रदेश नेतृत्व द्वारा ज़िलाध्यक्ष नागेंद्र चंद्रवंशी को पद से हटाने के बाद सतह पर आया है. नागेंद्र अति पिछड़े चंद्रवंशी समाज से आते हैं. उन्होंने पिछले दो वर्षों से अति पिछड़ों में अच्छी पैठ बना रखी है. अब नेतृत्व ने अध्यक्ष को हटाकर एक संयोजक मंडल का गठन करके विंदा चंद्रवंशी को उसका संयोजक बना दिया है, लेकिन अति पिछड़ा वर्ग पार्टी की इस पहल को एक छलावा मात्र मान रहा है. शायद यही कारण है कि पार्टी के एक धड़े ने प्रदेश अध्यक्ष विजय चौधरी एवं विधान पार्षद रामधनी सिंह का पुतला दहन कर अपना विरोध जताया. ऐलान किया गया कि विधानसभा चुनाव में पार्टी नेतृत्व को इस फ़ैसले का ख़ामियाज़ा भुगतना पड़ेगा. अति पिछड़ा समाज के दर्जनों नेताओं ने प्रदेश नेतृत्व के इस क़दम का विरोध करके स्पष्ट कर दिया कि वे करारा जवाब देने के लिए तैयार हैं.

नागेंद्र चंद्रवंशी की मानें तो उनके ख़िलाफ़ की गई कार्रवाई असंवैधानिक एवं पार्टी के सिद्धांतों के विरुद्ध है, क्योंकि वह एक चुने हुए ज़िलाध्यक्ष थे, न कि मनोनीत. अगर कोई कार्रवाई करनी ही थी तो नए सिरे से चुनाव करा लिया जाता. मालूम हो कि पिछले महीने ज़िले के एक विधान पार्षद की पहल पर पार्टी के कुछ नेताओं ने ज़िला इकाई के समानांतर दूसरी इकाई गठित कर समता पार्टी के पूर्व ज़िलाध्यक्ष अमरेश चौधरी को उसका अध्यक्ष बना दिया था. इसके बाद ही यह विवाद सामने आया. पार्टी से जुड़े दो विधान पार्षदों एवं एक विधायक में से एक विधान पार्षद एक खेमे में और एक विधान पार्षद एवं एक विधायक दूसरे खेमे से जुड़कर राजनीति कर रहे थे. विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और रोहतास ज़िला जदयू की अंतर्कलह सतह पर आ गई है. यह कलह जदयू के सबसे बड़े वोट बैंक अति पिछड़ों से जुड़ी है. इसलिए चुनाव परिणाम में इस कलह का असर पड़ना स्वाभाविक है. पार्टी के राज्य परिषद सदस्य राजेश्वर राज ने कहा कि जो भी क़दम प्रदेश नेतृत्व ने उठाया है, उस पर टिप्पणी करने का हमें कोई हक़ नहीं. हम बस एक सिपाही की तरह काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. इधर कई विरोधी दल नागेंद्र चंद्रवंशी के अगले क़दम के इंतजार में बैठे हैं, ताकि उनके विरोध के बाद उठी चिंगारी में जदयू को जलाने के लिए कुछ और किया जा सके. फ़िलहाल पार्टी नेतृत्व द्वारा बनाया गया संयोजक मंडल बैठकें करके यह साबित करने में जुटा है कि पार्टी में कोई अंतर्कलह नहीं है, लेकिन एक अनुशंसा प्रदेश नेतृत्व को भेजी गई है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण नागेंद्र चंद्रवंशी को दल से निकाल दिया जाए. अब देखना यह है कि नागेंद्र पर प्रदेश नेतृत्व कौन सी कार्रवाई करता है और उसके बाद नागेंद्र का अगला क़दम क्या होता है. फ़िलहाल पूरे प्रकरण में अति पिछड़ों का एक बड़ा तबका जदयू से नाराज़ दिख रहा है. यह तबका आगामी विधानसभा चुनाव में अपना विरोध जताकर नतीजों को प्रभावित करने की तैयारी में है.

ममता चौहान
feedback@chauthiduniya.com

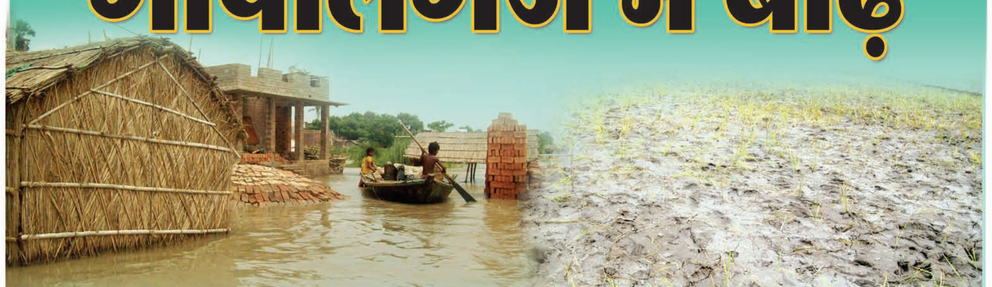

छपरा में सूखा गोपालगंज में बाढ़

विजयेंद्र कुमार

सारण प्रमंडल के ज़्यादातर लोगों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत कृषि है, लेकिन बाढ़ और सूखे के कारण किसानों की आर्थिक स्थिति दिनोंदिन कमजोर होती जा रही है. अधिसंख्य आबादी बरसात न होने के कारण सूखे की चपेट में है. खेतों में धान के पौधे सूखने लगे हैं, वहीं दूसरी ओर गोपालगंज प्रकृति के कहर से कराह रहा है. दियारे में लोग बाढ़ के पानी से तबाह हैं तो शेष भाग सूखे के कारण हलकान है. कुल मिलाकर सारण प्रमंडल के तीनों ज़िलों के किसान प्रकृति के इस सुखाड़-दाहड़ की लीला से परेशान हैं. प्रकृति की बेरुखी से लोगों की टूटती उम्मीदें अब सरकारी सहायता पर जा टिकी हैं.

गंडक में आई बाढ़ से अब तक तीन हज़ार एकड़ ज़मीन पर लगी फसलें बर्बाद हो गई हैं. सारण क्षेत्र के छपरा, सीवान एवं गोपालगंज के शेष हिस्से सूखे से त्रस्त हैं. यहां बरसात के शुरुआती दौर से ही सूखे की स्थिति बनी हुई है. अल्प वर्षा के बावजूद किसानों ने किसी तरह पूंजी लगाकर धान की रोपनी तो कर ली, मगर सूखे के कारण धान के पौधे सूखते जा रहे हैं. इसका असर उनकी आर्थिक स्थिति पर पड़ रहा है. समूचे क्षेत्र में सरकारी सिंचाई व्यवस्था ध्वस्त है. यहां की कृषि व्यवस्था निजी बोरिंग के सहारे टिकी है. उत्तर बिहार में वर्षों पूर्व से संचालित गंडक नहर परियोजना सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने में नाकाम साबित हो रही है. सारण प्रमंडल के 80 फीसदी लोगों की आजीविका का आधार खेती है, लेकिन तमाम सरकारी प्रयासों के बावजूद कृषि योग्य कुल भूमि के 20 फीसदी रकबे में ही सिंचाई की सुविधा पहुंच सकी है. सरकारी नलकूपों की हालत जर्जर है. रखरखाव के अभाव में अधिकांश सरकारी नलकूपों का अस्तित्व ख़त्म होने की कगार पर पहुंच चुका है.

सरकार किसानों को सूखे की स्थिति से निजात दिलाने, सरकारी नलकूपों को चलाने और बिजली उपलब्ध कराने के लिए लगातार घोषणाएं कर रही है, मगर सच्चाई यह है कि चालू नलकूपों के संचालन के लिए आपरेटरों की भारी कमी है. विभागीय अधिकारियों की मानें तो पूर्ण रूप से ठप्प पड़े नलकूपों की स्थिति सैकड़ों में है. ज़्यादातर नलकूपों में ईट-पत्थर भरे पड़े हैं. दूसरी तरफ सारण क्षेत्र में गंडक नहर योजना के अंतर्गत खेतों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रति वर्ष करोड़ों रुपये खर्च हो रहे हैं, बावजूद इसके कृषि योग्य भूमि तक सिंचाई की सुविधा नहीं पहुंच पाई है. फसलों की सिंचाई के समय नहरों में पानी का अभाव बना रहता है. नहरों के आउटलेट से निकलने वाले पानी को साइफन से होकर खेतों तक पहुंचाने का प्रबंध नहीं किया जा सका है, जिसके कारण अधिकांश पानी आसपास के निचले इलाक़ों में जमा हो जाता है. जलभराव के परिणामस्वरूप निचले इलाक़ों की फसलें बर्बाद हो जाती हैं, जबकि अधिकांश खेतों को सिंचाई करने के लिए पानी नहीं मिल पाता. प्रतिवर्ष सुखाड़ और दाहड़ की मार से त्रस्त इन ज़िलों के किसानों की स्थिति दिनोंदिन कमजोर होती जा रही है, जिसके चलते वे रोजी-रोटी के लिए बाहर पलायन करने को विवश हैं.

feedback@chauthiduniya.com

हम भी हैं जोश में

स्मृति

चुनावी सरगर्मी तेज़ होते ही सभी दल जीत की आस लिए मैदान में कूद पड़े हैं. हर दल ख़ुद को सबसे बेहतर बताने की कोशिश में जुटा है. दिलचस्प बात यह है कि चुनावी तैयारी में युवा बढ़-चढ़कर भाग ले रहे हैं यानी युवाओं की भागीदारी काफी मजबूत है. सभी दलों ने इस बार युवाओं को अधिक महत्व दिया. लिहाजा टिकट के मामले में भी युवा भाग्यशाली साबित होंगे. चुनावी मैदान में अब सभी दलों के युवा जोश के साथ एक दूसरे को धूल चटाने के लिए कमर कस रहे हैं. राजद के युवा नेता अरविंद कुमार सिंह उर्फ छोटू सिंह की मानें तो उनकी पार्टी में इस बार सबसे ज़्यादा प्राथमिकता युवाओं को ही दी जा रही है. नीतीश सरकार से नाखुश छोटू सिंह का दावा है कि इस बार उनकी पार्टी सत्ता में आएगी. उन्होंने कहा कि नीतीश ने जो घोटाले किए हैं, उनका भंडाफोड़ हो चुका है. बहुत शर्म की बात है कि बिहार में एक भी उद्योग नीतीश राज में नहीं खुल पाया. लालू प्रसाद के मुख्यमंत्री बनते ही युवाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण क़दम उठाया जाएगा. उनकी पढ़ाई के साथ कोई समझौता नहीं होगा. इंजीनियरिंग एवं मेडिकल कॉलेज खोलना पहली प्राथमिकता होगी. कांग्रेस पर अपना गुस्सा निकालते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में राहुल फैक्टर नहीं चल सकता, क्योंकि यहां सिर्फ़ लालू फैक्टर काम करता है. राहुल जैसे नेता बिहार के लोगों की पहुंच से बहुत दूर की चीज हैं.

लोजपा भी राजद की तरह युवाओं की मजबूत भागीदारी की पक्षधर है. लोजपा युवा अध्यक्ष नवीन शुक्ला का कहना है कि युवाओं की बदौलत ही पार्टी चलती है. वह कहते हैं कि नीतीश युवा विरोधी हैं. कांग्रेस के राहुल फैक्टर पर वह टिप्पणी करते हैं कि यहां सिर्फ़ ठगने का काम हो रहा है. यदि राहुल सही मायने में युवाओं के शुभचिंतक होते तो उन्हें बढ़ावा देते, लेकिन ऐसा नहीं है. एनसीपी युवा अध्यक्ष रोहित कुमार सिंह का कहना है कि एनसीपी युवाओं की पार्टी है. पांच हज़ार युवाओं को युवा-छात्र सम्मेलन में बुलाकर उन्होंने यह साबित कर दिया है कि उनकी पार्टी युवाओं का उत्थान कर रही है. रोहित की मानें तो एनसीपी नेता काम करते हैं तो सिर्फ़ युवाओं के लिए. कांग्रेस के राहुल फैक्टर पर उनके विचार भी बाकी दलों के नेताओं के समान हैं. उनका कहना है कि राहुल फैक्टर बिहार के लिए नहीं है, यहां सिर्फ़ एनसीपी युवा फैक्टर है. सत्ता में आने के बाद एनसीपी 30 प्रतिशत युवाओं को आरक्षण और 27 साल से लंबित बेरोज़गार भत्ता शुरू करना चाहती है. दूसरी तरफ कांग्रेस के युवा अध्यक्ष ललन यादव की मानें तो राहुल गांधी की टीम भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ लड़ेगी. बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ मोर्चा खोलना उनकी पहली प्राथमिकता होगी. ललन यादव का कहना है कि राहुल आज के युवाओं की प्रेरणा हैं. 7.5 लाख नए युवा सदस्य बने हैं. उन्होंने कहा कि वह चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं, ताकि युवाओं को हर क्षेत्र में हिस्सेदारी दी जाए. उन्होंने सभी पार्टियों के युवाओं को आमंत्रण दिया कि वे कांग्रेस के साथ आएं और अपने हक़ के लिए लड़ें.

कांग्रेस की पूर्व संगठन सचिव अर्पणा सिंह का मानना है कि राहुल गांधी ने बिहार के युवाओं के लिए तरक्की का रास्ता साफ़ कर दिया है. पार्टी के युवा पूरे जोश में हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि वे राहुल गांधी के बताए रास्ते पर चलकर बिहार के विकास में अपनी भागीदारी निभाएंगे. इसके विपरीत भाजपा के मीडिया प्रभारी एवं युवा नेता संजय मयूख का कहना है कि युवाओं का रुझान भाजपा की ओर है, क्योंकि भाजपा और जदयू की सरकार ने बेरोज़गारी हटाना अपना लक्ष्य मान लिया है. उन्होंने कहा कि रोज़गार की संभावनाएं बढ़ रही हैं, विश्वविद्यालयों की रौनक बढ़ी है. पठन-पाठन का काम जारी है, तकनीकी से लेकर विधि और प्रबंधन संस्थानों की स्थापना से भी युवाओं का रुझान बिहार की एनडीए सरकार की ओर बढ़ा है. राहुल बुलबुले के समान हैं, जो आते हैं और चले जाते हैं. उनका बिहार में कोई राजनीतिक प्रभाव नहीं है. उन्होंने बिहार को एक पिकनिक स्पॉट समझ लिया है, लेकिन राजनीति में पिकनिक का कोई स्थान नहीं होता.

जदयू भी युवा भागीदारी में पीछे नहीं है. फैसल रहमान ने कहा कि इस बार उनकी पार्टी में युवाओं की भूमिका ज़्यादा रहेगी. वह पार्टी से युवाओं के लिए 40 सीटें मांग कर रहे हैं. जदयू नेता सतीश यादव का मानना है कि युवा पार्टी को सबसे अधिक ताक़त देते हैं. यही वजह है कि नीतीश कुमार ने युवाओं के लिए ढेर सारे काम किए. आज बिहार का युवा दावे के साथ कह सकता है कि दूसरे राज्यों से कहीं अधिक सुविधा उसे बिहार में मिल रही है. जदयू के युवा नीतीश कुमार के साथ हैं और बिहार के विकास का रास्ता किसी भी क़ीमत पर बंद नहीं होने देंगे. खैर जितनी पार्टियां, उतनी बातें. इसका निष्कर्ष तो अब चुनाव के बाद ही निकलेगा, लेकिन एक बात तय है कि युवा पार्टी की जीत में अहम भूमिका निभाएंगे. देखना यह है कि जोश से भरपूर युवा आमने-सामने की लड़ाई में क्या गुल खिलाते हैं.

रोहित कुमार | ललन यादव | सतीश कुमार | संजय मयूख | फैसल रहमान | अरविंद कुमार सिंह

feedback@chauthiduniya.com

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. 45843/86

चौथी दुनिया

दिल्ली, 20 सितंबर–26 सितंबर 2010

अब पति के साथ मिलकर उन्होंने प्रोडक्शन हाउस शुरू किया है. इस प्रोडक्शन हाउस के तहत वह एक भोजपुरी फिल्म का निर्माण भी कर चुकी हैं.

सभागाछी गाछी है पर सभा नहीं

बिमलेश कुमार

वरों का यह अनूठा मेला अब अपनी चमक खोता जा रहा है. एक समय था, जब शादी करने और कराने वालों की यहां भीड़ लगी रहती थी. कहा तो यहां तक जाता है कि मेले में लोगों को पैर रखने के लिए जगह तक नहीं मिलती थी. लाखों की संख्या में लोग आते थे, लेकिन अब मुश्किल से एकाध हज़ार लोग ही मेले में पहुंचते हैं. यही वजह है कि ऐतिहासिक सभागाछी ख़त्म होने की कगार पर पहुंच गई है.

मधुबनी ज़िला मुख्यालय से महज़ छह किलोमीटर की दूरी पर स्थित है सौराठ गांव. यह गांव वैवाहिक सम्मेलन के कारण पूरे विश्व में प्रसिद्ध है. यह सम्मेलन सौराठ सभा के नाम से जाना जाता है. सौराठ सभा संभवत: विश्व में अपने ढंग का अनूठा वैवाहिक सम्मेलन है, जहां प्रति वर्ष मैथिल ब्राह्मण समुदाय के लड़के-लड़कियों की शादियां तय होती हैं, लेकिन अब यहां से शादी तय करना गुजरे जमाने की बात हो गई है. लोग यहां आना तक मुनासिब नहीं समझते, जिसके चलते इस ऐतिहासिक परंपरा का अस्तित्व ख़त्म होता जा रहा है. अगर समय रहते लोगों ने इस पर सोचना शुरू नहीं किया तो यह ऐतिहासिक परंपरा इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह जाएगी.

कई सदियों से ज्येष्ठ-आषाढ़ के महीने में यहां एक विशेष प्रकार के मेले का आयोजन किया जाता रहा है. इसे मेला नहीं, बल्कि सौराठ सभा या सभागाछी के नाम से जाना जाता है. सभा का आयोजन 22 बीघा ज़मीन पर खुले आसमान के नीचे होता है. यह ज़मीन दरभंगा महाराज ने दान में दी थी. लोग यहां विवाह योग्य लड़के-लड़कियों की तलाश में इकट्ठा होते हैं और यहीं से शादी तय होती है. वर अपने संबंधी या अभिभावक के साथ यहां आते हैं. वधू पक्ष के लोग उनसे पूछताछ करते हैं और उसके बाद शादी तय होती है. इस तरह के आयोजन का सबसे बड़ा फ़ायदा यह होता है कि कन्यागत (वधू पक्ष) को यहां-वहां भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती. उन्हें एक ही स्थान पर बहुत सारे लड़के मिल जाते हैं और वे किसी सुयोग्य वर से अपनी बेटी की शादी करा देते हैं.

सौराठ में शादियां कराने वाले पंजीकार विश्वमोहन चंद्र बताते हैं कि 700 साल पहले क़रीब 1310 ईस्वी में इस प्रथा की शुरुआत हुई थी. लिखित रूप में पंजी प्रथा की शुरुआत मिथिला नरेश हरिसिंह देव ने की थी. हालांकि इससे पूर्व उनके पूर्वज नान्यदेव इसकी नींव डाल चुके थे, मगर उस वक्त पंजी लिपिबद्ध नहीं होती थी. पंजी प्रथा का मुख्य उद्देश्य विवाह संबंध अच्छे कुल में होना है. इस प्रथा के अनुसार, कम से कम मातृकुल के पांच एवं पितृकुल के सात पुरखों के मध्य रक्त संबंध होने पर उस पीढ़ी के मध्य वैवाहिक संबंध वर्जित है. वैज्ञानिक कारण भी यही है, क्योंकि एक ही ब्लडग्रुप में शादी करने की सलाह डॉक्टर भी नहीं देते. शायद यही वजह है कि ब्राह्मण एक ही गोत्र एवं मूल में शादी नहीं करते. उनका मानना है कि अलग गोत्र में विवाह करने से संतान उत्तम होती है. शादी कराने में पंजीकारों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है.

पंजीकार ही शादियों की फिक्सिंग कराते हैं. मेले में सिद्धांत लिखवाने का भी काम होता है. मतलब यह कि वर और वधू पक्ष का वंशगत लेखाजोखा पंजीकार ही रखते हैं. यहीं से उन्हें उनके पुरखों की सारी जानकारी मिल जाती है. पुरखों का यह सिद्धांत क़ानूनी रूप से किसी भी शादी को स्वीकृति प्रदान करता है और अदालत में भी इसे मान्यता प्राप्त है.

क़रीब दो दशक पहले यहां शादी करने और कराने वालों की अच्छी-खासी भीड़ होती थी, लेकिन विडंबना यह है कि अब धीरे-धीरे यहां आने वाले लोगों की संख्या साल दर साल घटती जा रही है. सवाल यह उठता है कि इस स्थिति के लिए ज़िम्मेदार कौन है? हालांकि किसी एक को ज़िम्मेदार ठहराना सरासर ग़लत होगा. इसके लिए नेता, प्रशासन और वहां के लोग समान रूप से ज़िम्मेदार हैं. सभागाछी की इस स्थिति के लिए युवा पीढ़ी भी कम ज़िम्मेदार नहीं है, जो इस तरह के आयोजन में जाने से कतराती है. वह सोचती है कि वहां जाने से उसकी इज़्ज़त कम हो जाएगी. अब वहां जाना वे अपनी शान के ख़िलाफ़ समझते हैं.

विश्वमोहन चंद्र ने बताया कि 1971 में इस आयोजन में क़रीब डेढ़ लाख लोग आए थे, लेकिन धीरे-धीरे यहां आने वालों की संख्या कम होती गई. 1991 में लगभग पचास हज़ार लोग आए थे और इस वर्ष महज़ दस हज़ार लोग ही इस मौक़े पर पहुंचे. उक्त आंकड़े मेले की स्थिति बताने के लिए काफी हैं. मेला आयोजक चुनचुन मिश्र का कहना है कि इस स्थिति के लिए सरकार ज़िम्मेदार है, सभा को अब पहले जैसी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, जैसे यातायात, पानी और बिजली आदि की व्यवस्था नहीं की जाती. इसके अलावा भी कई कारण हैं, जिनसे सभागाछी का अस्तित्व ख़त्म होने की कगार पर हैं. इस इलाक़े में जितने भी सुखी संपन्न परिवार हैं, वे यहां नहीं आते. इसलिए एक हद तक यहां के लोग भी ज़िम्मेदार हैं. वे अपनी संस्कृति को नहीं बचाना चाहते. दहेज की समस्या ने भी इसे प्रभावित किया है. पहले यहां स्थिति यह थी कि कोई भी वर दहेज नहीं मांगता था, लेकिन अब यहां दहेज मुंह खोलकर मांगा जाता है. मेले में वर की तलाश में पहुंचे राम चौधरी ने कहा, मैं अपनी बेटी की शादी के लिए लड़का खोज रहा था, लेकिन सभी ने काफी अधिक दहेज मांगा. यहां यह सोचकर आया कि अच्छा लड़का मिल जाएगा, लेकिन एक भी ढंग का लड़का नहीं मिला. जो अच्छे लड़के आए थे, वे खुलकर दहेज मांग रहे थे. पहले सौराठ में विवाह होना सम्मान की बात मानी जाती थी, लेकिन अब यह कहा जाता है कि जिनका विवाह कहीं नहीं होता है, वही वर शादी करने के लिए यहां आते हैं.

bimlesh@chauthiduniya.com

भाग्यश्री का रेड अलर्ट

यह क़िस्मत की ही मार है कि मैंने प्यार किया जैसी सुपरहिट फिल्म की अभिनेत्री भाग्यश्री वह मुकाम हासिल नहीं कर पाईं, जो मुकाम को-स्टार सलमान खान को हासिल हुआ. राजश्री प्रोडक्शन की इस फिल्म के बाद भाग्यश्री इक्का-दुक्का फिल्मों में ही नज़र आईं. वह धीरे-धीरे सिलवर स्क्रीन से गायब सी हो गईं. मतलब यह कि उनका करियर ख़त्म होने की कगार पर पहुंच गया. इसी बीच उन्होंने शादी कर घर भी बसा लिया. अब पति के साथ मिलकर उन्होंने प्रोडक्शन हाउस शुरू किया है. इस प्रोडक्शन हाउस के तहत वह एक भोजपुरी फिल्म का निर्माण भी कर चुकी हैं. इस फिल्म का नाम एगो चुम्मा दे दे राजाजी है. हिंदी फिल्मों में काम करने वाली भाग्यश्री अचानक भोजपुरी फिल्मों का निर्माण कैसे करने लगीं? दरअसल, भाग्यश्री भोजपुरी फिल्मों में बतौर निर्माता जुड़ने से पहले कई फिल्मों में बतौर अभिनेत्री काम कर चुकी हैं. अगर उनकी कुछ सुपरहिट फिल्मों का नाम लिया जाए तो उठाइले घूंघटा चांद देखले, जनम जनम के साथ और देवा आदि प्रमुख हैं. इन फिल्मों की कामयाबी और मुनाफे को देखकर भाग्यश्री एवं उनके पति हिमालय दासानी के मन में फिल्म निर्माण का विचार आया. दोनों ने मिलकर सृष्टि इंटरटेनमेंट नामक कंपनी की स्थापना की. जब भाग्यश्री से पूछा गया कि क्या अब पूरी तरह से भोजपुरी फिल्मों में रमने का इरादा है तो उनका जवाब कुछ और था. उन्होंने कहा कि एक अभिनेत्री होने के नाते अगर उन्हें किसी भी भाषा की फिल्म मिलेगी तो वह इंकार नहीं करेंगी, बशर्ते किरदार में दम होना चाहिए. उन्होंने उदाहरण के तौर फिल्म रेड अलर्ट का जिक्र किया. ग़ौरतलब है नक्सली समस्या जुड़ी फिल्म रेड अलर्ट में भाग्यश्री ने मजबूरी में नक्सली बने युवक की पत्नी का नॉन ग्लैमरस किरदार निभाया था. इस किरदार के लिए समीक्षकों से उन्हें वाहवाही भी मिली थी. अब देखते हैं भाग्यश्री रेड अलर्ट की तरह भोजपुरी में भी कोई जानदार किरदार निभाती हैं या फिर नाच-गाने वाली विशुद्ध व्यवसायिक फिल्में ही करती रहेंगी.

हिंदी फिल्मों में काम करने वाली भाग्यश्री अचानक भोजपुरी फिल्मों का निर्माण कैसे करने लगीं? दरअसल, भाग्यश्री भोजपुरी फिल्मों में बतौर निर्माता जुड़ने से पहले कई फिल्मों में बतौर अभिनेत्री काम कर चुकी हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com